RNI NO. DELHI/2012/48369
वर्ष 8 अंक 193
नई दिल्ली, सोमवार, 18 मई, 2020
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

तेंदुलकर को चुनौती देकर बुरे फंसे युवराज
स्पोर्ट्स-10

www.dailypioneer.com

लॉकडाउन-4 में जिंदगी की डोज

- 31 मई तक बढ़ा लेकिन इस बार नए रंग रूप में होगा
- राज्यों को जोन तय करने समेत मिले कई अधिकार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

कोरोना वायरस के चलते जारी लॉकडाउन के बीच रविवार को प्रयागराज में जमीन पर रखे बैग के सहारे ही सो गयी बच्ची। गुजरात से आए उसके परिजन बस द्वारा घर जाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कराने में लगे हैं

कोरोना संकट के मद्देनजर सरकार ने रविवार को देशव्यापी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 'लॉकडाउन 4' के लिए जारी दिशा निर्देशों में थोड़ी ढील देते हुए राज्यों को बस और यात्री वाहनों के संचालन की अनुमति दे दी गई है, वहीं सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने जैसी पहले से लागू पाबंदियां जारी रहेंगी। कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव वाले इलाकों को कंटेनमेंट और बफर जोन में तब्दील करने का अधिकार अब राज्यों को दे दिया गया है। ये उस इलाके में संक्रमण के स्तर पर तय होंगे।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक इन क्षेत्रों में केवल जरूरी सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी जबकि बाकी क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के साथ सभी व्यवसायिक और आर्थिक गतिविधयां चालू रहेंगी। सात बजे शाम से सुबह सात बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। दिशा-निर्देश के अनुसार, घरेलू हवाई एम्बुलेंस के अलावा अन्य सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी। गृह मंत्रालय का कहना है कि 31 मई तक देश भर में मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल (तरण ताल), जिम आदि बंद रहेंगे।

इस अवधि में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी साथ ही सभी प्रार्थना और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है। सभी मालवाहक वाहनों और खाली मालवाहक वाहनों को एक से दूसरे राज्य में बगैर किसी बाधा के आवाजाही की अनुमति दी जाएगी। राज्य यात्री वाहन जिसमें टैक्सी, उबर, ओला जैसे कैब, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा की परिभाषा तय करने तथा बसों समेत इन सभी वाहनों में यात्रियों की संख्या निर्धारित करने का फैसला लेंगे। कुछ क्षेत्रों में आरोग्य सेतु ऐप को डॉउनलोड करने के पहले के नियमों में बदलाव करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि नियोक्ता कर्मचारियों के लिए बेहतर सेवा का इस्तेमाल करे तथा जिला प्रशासन लोगों को ऐप डॉउनलोड करने का सुझाव दे।

ऐप की आलोचना तथा एक वर्ग द्वारा निजता के नियमों का हवाला देते हुए ऐप को डाउनलोड करने के 'अवैध' आदेश के खिलाफ अदालत जाने की चेतावनी दिए जाने के मद्देनजर केंद्र ने इस संबंध में अपना रुख बदल (शेष पेज 9)

दिल्ली मेट्रो भी रहेगी बंद

नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने रविवार को कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाये जाने के मद्देनजर मेट्रो सेवाएं यात्रियों के लिए 31 मई तक बंद रहेंगी। डीएमआरसी ने एक ट्वीट में कहा, 'सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ाये के मद्देनजर, मेट्रो सेवाएं यात्रियों के लिए 31 मई तक बंद रहेंगी। हमारी हेल्पलाइन सेवा 155370 भी उपलब्ध नहीं होगी। आप हम तक **helpline@dmrc.org** पर पहुंच सकते हैं।'

गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश

- सभी दुकानें सुनिश्चत करें कि उनके ग्राहक एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें और एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा लोग ना हों।
- स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें।
- 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें।
- आवश्यक सेवाओं से इतर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।
- केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में 'निषिद्ध' और 'बफर' जोन चिह्नित करेगा।
- राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति।
- सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में बंद रहेंगे।
- होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, स्वीमिंग पूल, जिम 31 मई तक बंद रहेंगे।
- घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर रोक बरकरार रहेगी।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज

मनरेगा को मिलेगा 40 हजार करोड़ का अतिरिक्त फंड

- एक साल तक कंपनियों पर दिवालिया कार्रवाई नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं पर बढ़ाएंगे खर्च, सभी जिलों में बनेंगे कोविड-19 अस्पताल

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

नई दिल्ली में पत्रकारों से वार्ता करतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

सरकार ने कोविड-19 संकट के बीच उद्योग को राहत के लिए कर्ज चूक के नए मामलों में दिवाला कार्रवाई पर एक साल के लिए रोक लगा दी है। इसके अलावा अपने घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार के लिए मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

इसके साथ ही सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए नई नीति लाने की घोषणा की है। इसके तहत गैर-रणनीतिक क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जाएगा। वहीं चिह्नित रणनीतिक क्षेत्रों में चार से अधिक कंपनियों को परिचालन की अनुमति नहीं होगी। इस सीमा से अधिक कंपनियों होने पर उनका आपस में विलय किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आर्थिक पैकेज की पांचवीं किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वजह से अपने राज्यों को लौटे श्रमिकों को रोजगार के (शेष पेज 9)

नाटक कर रहे हैं राहुल गांधीः निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए रविवार को कहा कि उसके नेता राहुल गांधी 'नाटक' कर रहे हैं और राजनीतिक दलों को प्रवासी श्रमिकों की मुश्किलों का राजनीतिकरण करने से बचना तथा जिम्मेदारीपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा शनिवार को अपने गृह राज्य लौट रहे प्रवासी श्रमिकों के एक समूह (शेष पेज 9)

वित्त मंत्री से गंभीरता की उम्मीदः कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने रविवार को सरकार पर आर्थिक पैकेज के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र द्वारा घोषित उपाय भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 1.6 प्रतिशत हैं जो 3.22 लाख करोड़ रुपये है लेकिन प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपये का दावा किया था। पार्टी ने कांग्रेस पर हमले के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर (शेष पेज 9)

बाजार

सेंसेक्स	31,097	
निफ्टी	9,136	
सोना		/10g
चांदी		/kg

क्विक न्यूज

चक्रवात अम्फान से मुकाबले को ओडिशा, बंगाल तैयार

नई दिल्ली। चक्रवात अम्फान के आसन्न खतरे के मद्देनजर रविवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम तैनात कर दी गई। इस बीच, ओडिशा ने कहा कि वह इस चक्रवात से बुरी तरह से प्रभावित होने वाले 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। एनडीआरएफ के महानिदेशक एस एन प्रधान ने नई दिल्ली में कहा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रविवार सुबह की एक रिपोर्ट के अनुसार चक्रवात अम्फान बंगाल की खाड़ी में एक प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील हो रहा है और संभवतः अगले 24 घंटों में यह अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। उन्होंने कहा, इसका पथ मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, सागर द्वीप समूह और शायद बांग्लादेश की ओर है...लेकिन हमें इस पर करीबी नजर रखनी होगी। एनडीआरएफ ने समय रहते अपनी टीम तैनात कर दी है। (विस्तृत पेज 9)

नक्सलियों से मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी शहीद

गढ़चिरौली। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में रविवार सुबह नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में दो पुलिस कर्मी शहीद हो गए और तीन अन्य घायल हो गए। मुठभेड़ में चार से पांच नक्सली भी मारे गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि गोलीबारी सुबह 6 से 6.30 बजे के बीच पोयारकोटी-कोपार्शी वन क्षेत्र में हुआ, जब भामरागढ़ की एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम और गढ़चिरौली पुलिस के सी-60 के कमांडो एक संयुक्त नक्सल-विरोधी अभियान पर निकले थे। विज्ञप्ति में कहा गया कि उप-निरीक्षक धन्नाजी होनमाने और कांस्टेबल किशोर अतराम की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य कर्मी घायल हो गए। मुठभेड़ में संभवतः चार से पांच नक्सली भी मारे गए। घायल पुलिस कर्मियों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और शवों को हेलीकॉप्टर से गढ़चिरौली शहर लाया गया।

देश में एक दिन में सबसे ज्यादा पांच हजार मामले

- कुल संक्रमितों की संख्या 91 हजार पहुंची, एक दिन में 120 लोगों की मौत

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

देश में कोविड-19 का प्रसार अब तेजी से हो रहा है। रविवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 4,987 केस आए हैं। यह अब तक सबसे ज्यादा है। अब कुल मामलों की संख्या 90,927 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा 2,347 नए मामले आए और 63 मरीजों की मौत हुई। राज्य में अब तक 33,053 केस हो गए हैं। देश में बीते 24 घंटे में 120 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ये आंकड़े शनिवार सुबह आठ बजे तक के हैं। मंत्रालय का कहना है कि देश में लगभग 91,000 मरीजों में से 34,108 ठीक हो चुके हैं और 2,872 की मौत हो चुकी है। अब कुल 53,946 मरीजों का इलाज चल रहा है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब तक करीब 37.59 फीसद मरीज ठीक हो चुके हैं। तीन राज्यों में संक्रमण के 10,000 से अधिक मामले हैं जिनमें सर्वाधिक महाराष्ट्र में हैं। गुजरात में 10,988 और तमिलनाडु में 10,585 केस हैं। दिल्ली में कोरोना की वजह से अब तक 148 लोगों की मौत हुई है। यहां बीते 24 घंटे में 422 नए केस आने के साथ ही 9,755 मरीज हो गए हैं। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक देश में कुल 2,872 मरीजों की मौत हुई है जिनमें सर्वाधिक 1,135 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। गुजरात में 625, मध्य प्रदेश में 243, पश्चिम बंगाल में 232, दिल्ली में 148, राजस्थान में 126, उत्तर प्रदेश में 104, तमिलनाडु में 74 और आंध्र प्रदेश में 49, कर्नाटक में 36, तेलंगाना में 34, पंजाब में 32, हरियाणा में 13, जम्मू-कश्मीर में 12, बिहार में सात, केरल में चार, झारखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में तीन-तीन तथा असम में दो मरीजों की मौत हुई है।

इनके अलावा मेघालय, उत्तराखंड और पुडुचेरी में कोविड-19 के एक-एक मरीज की मौत हुई। संक्रमण से मौत के 70 फीसद से अधिक मामलों में मरीज अन्य गंभीर बीमारियों से भी ग्रस्त से थे। मुंबई में रविवार को कोरोना के 1571 केस आए और 38 लोगों की मौत हो गई। यहां कुल संख्या 19,967 हो गई है। अब तक (शेष पेज 9)

राष्ट्रपति भवन पहुंचा संक्रमण, एसीपी कोरोना पॉजिटिव

पायनियर समाचार सेवा। नयी दिल्ली

दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस के साथ संक्रमण राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है। यहां तैनात दिल्ली पुलिस के एक सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद पांच पुलिसकर्मियों को क्वॉरंटीन किया गया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि (शेष पेज 9)

यूपी की सभी जेलों में रैंडम सैंपलिंग शुरू

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश के आगरा केंद्रीय कारागार में कोविड-19 संक्रमित एक कैदी की मौत के बाद कारागार प्रशासन ने राज्य की सभी जेलों में रैंडम सैंपलिंग शुरू की है। कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के महानिदेशक आनंद कुमार ने रविवार को भाषा को बताया आगरा जेल में आठ मई को कोविड-19 संक्रमित एक कैदी की मौत हो गई। वह छह मई कोरोना संक्रमित पाया गया था। उसके संपर्क (शेष पेज 9)

हिंसा पर उतारू मजदूरों ने की तोड़फोड़

- घर भेजने की मांग को लेकर सहारनपुर में लगाया जाम, रीवा में पुलिस से झड़प- राजकोट में पथराव

पायनियर समाचार सेवा। सहारनपुर

सहारनपुर में बिहार जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग को लेकर करीब ढाई हजार प्रवासी मजदूर ने सहारनपुर-अंबाला हाईवे को जाम कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा वे उन्हें बिहार सीमा तक बसों से भेजेंगे, जहां से श्रमिक अपने गृह राज्य में जाएंगे।

लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी और दिक्कतो ं से परेशान बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों के पलायन का दौर जारी है। घर जा रहे बहुत से श्रमिक हादसों के शिकार भी हो चुके हैं, जिसे देखते हुए कई राज्य सरकारों ने बॉर्डर सील कर दिए हैं और मजदूरों के पैदल, साइकिल, बाइक या ट्रकों पर बैठकर जाने पर रोक लगा दी है।

इसके बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में मजदूरों ने रविवार को जमकर हंगामा काटा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रवासी मजदूरों ने खूब हंगामा किया और सहारनपुर-अंबाला हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस-प्रशासन के अधिकारी उन्हें समझाते रहे मगर प्रवासी मजदूर नहीं हटे। इसके बाद कमिश्नर, डीएम, एसएसपी मौके पर पहुंचे और उनकी मांगों को सुना। सभी अपने-अपने घर बिहार भेजे जाने की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। इसके बाद अधिकारियों ने रोडवेज की बसें मंगाकर इन्हें इनके-इनके घरों के लिए रवाना कर दिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के रीवा में भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित चकघाट इलाके में मजदूरों ने उपद्रव किया। यहां प्रवासी मजदूरों की पुलिसकर्मियों से झड़क हुई और मजदूरों ने पुलिस बैरिकेड उखाड़कर फेंक दिए। दोपहर में उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी प्रवासी मजदूर अपने-अपने घर (शेष पेज 9)

भारत की नभ सीमा में घुसे चीनी चॉपर

- पिछले महीने 11 और 20 अप्रैल को चीनी सैनिकों ने की थी हरकत

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ से बाज नहीं आ रहे हैं। चीन के हेलीकॉप्टरों ने हाल ही में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की थी। हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का यह मामला पिछले महीने सामने आया था। सिक्किम और लद्दाख में इसी महीने की शुरुआत में भारतीय और चीनी सैनिक आमने-सामने आ गए थे।

इस संघर्ष में दोनों पक्षों के सैनिकों में से कुछ को चोटें भी आई थीं। एक चीनी हेलीकॉप्टर ने 11 अप्रैल को लाहौल-स्पीति में भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया और उसके बाद 20 अप्रैल को भी चीनी हेलीकॉप्टर ने इसी तरह उड़ान भर कर भारतीय क्षेत्र में चक्कर लगाया। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि हेलीकॉप्टर हिमाचल के अंदर कम से कम आठ से दस किलोमीटर दूर आया और कुछ समय बाद वापस उड़ गया। हिमाचल प्रदेश में कुछ साल पहले भी इसी तरह चीनी हेलीकॉप्टरों ने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था।

भारत के आखिरी गांव, जहां यह हेलीकॉप्टर घुसपैठ की ताजा घटना हुई है, वर्ष 2017 में भी चीनी सेना की गतिविधियों में वृद्धि देखी गई थी। यह उस समय की बात है जब सिक्किम के डोकलाम में भारत और चीन के बीच 73 दिन तक गतिरोध चला था। रविवार को यहां सूत्रों ने कहा कि तब से चीन ने एलएसी के पार अपने (शेष पेज 9)

मुठभेड़ में हिज्बुल का शीर्ष आतंकी ढेर एक जवान शहीद

पायनियर समाचार सेवा। डोडा, जम्मू

जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में रविवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में हिज्बुल मुजाहिदीन का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। वह आरएसएस के एक पदाधिकारी और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) की हत्या के मामले में वांछित था। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद डोडा कस्बे से 26 किलोमीटर दूर गुंडाना इलाके के पोस्ता-पोत्रा गांव में एक संयुक्त तलाश अभियान चलाया। इस दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई, जो पांच घंटे तक चली। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ के दौरान जमींदोज हुए (शेष पेज 9)

चीन छोड़ यूपी आएगी जर्मन कंपनी

- अवसर में बदला कोरोना संकट, आगरा में करेगा करोड़ों का निवेश अंतरराष्ट्रीय फुटवियर ब्रांड, जल्द नोएडा में भी स्थापित होंगी अन्य कंपनियां, दस हजार नौकरियों के सृजन का वादा

रिंकू यादव। नोएडा

वुहान से निकले कोरोना वायरस महामारी के चलते बहुत सी विदेशी कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेटने की फिराक में हैं।

सस्ते मानवश्रम और सुविधाओं को देखते हुए वे अब अपना ठिकाना भारत में बनना चाहती है। कोरोना से जंग लड़ रहा भारत इस मौके को अवसर में तब्दील करना चाहता है। उत्तर प्रदेश सरकार वहां से निकलने वाली कंपनियों पर निगाह रखे हुए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति है कि वह चीन छोड़कर जाने की तैयारी कर रही कंपनियों को उत्तर प्रदेश लेकर आएंगे। इसके लिए उनके सिपहसालारों ने मल्टीनेशनल कंपनियों से बैठक भी की हैं। इस मुहिम का पहला परिणाम रविवार को सामने आया है, जब जर्मनी का अंतरराष्ट्रीय जूता ब्रांड उत्तर प्रदेश आ रहा है।

दुनिया के जाने माने हेल्थ फुटवियर ब्रांड वॉन वेलक्स के मालिक कासा एवरेज जीएमबीएच ने चीन से अपना पूरा उत्पादन भारत स्थानांतरित करने का फैसला किया है। उत्पादन अब इराट्रिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से उत्तर प्रदेश के आगरा में होगा। वॉन वेलक्स पैरों, (शेष पेज 9)

अमेरिकी कंपनियों को मनचाही छूट की पेशकश

उत्तर प्रदेश सरकार चीन में संचालित करीब 100 अमेरिकी कंपनियों के संपर्क में है। सरकार द्वारा उक्त सभी कंपनियों को मन चाही छूट देने का ऑफर भी दिया है। इस लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने उक्त कंपनियों के प्रबंधकों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बाात भी की है और उन्हे उत्तर प्रदेश में अपनी इकाई स्थापित करने के लिए मनचाही छूट देने की पेशकश भी की है। योगी सरकार ने (शेष पेज 9)

पायनियर
नई दिल्ली, सोमवार, 18 मई, 2020

रादौरी गांव में एक एकड़ में खड़े गेहूं के फाने जलकर राख

पायनियर समाचार सेवा। रादौर

रादौर के गांव रादौरी में आग बुझाने के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी।

रादौरी गांव में अज्ञात कारणों के चलते रविवार दोपहर अचानक आग लगने पर एक एकड़ में खड़े गेहूं के फाने जलकर राख हो गये। गांव के लोगों ने आग बुझाने की बहुत कौशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बाद में सूचना मिलने पर रादौर से फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और लगभग एक घंटे की मश्क्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार गांव रादौरी निवासी अमित कांबोज के एक एकड़ में खड़े गेहूं के फाने में अचानक आग लग गई। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से प्रभावित किसान को हजारों रुपये का नुकसान हुआ है।

'रै मास्टर, बालंका का काम नहीं भैजा तनै...'

रविवार छुट्टी का दिन होंने के बावजूद अभिभावक शिक्षकों को कर रहे फोन

रणबीर सिंह रोहिल्ला। सोनीपत

सरकारी स्कूल के अध्यापक नरेश कुमार आकाश।

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में लॉकडाउन के समय ऑनलाइन पढ़ाई के सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। रविवार छुट्टी का दिन होंने के बावजूद अभिभावक फोन करके कहते हैं (रै मास्टर, बालंका का काम नहीं भैजा तनै) के बात आज पढ़ना नहीं सै के।

राजकीय कन्या उच्च विद्यालय जाहरी के कला अध्यापक एवं कला विशेषज्ञ नरेश कुमार आकाश ने बताया पहले जो अभिभावक फोन करने पर अनुचित असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए कहते थे। रै मास्टर तनै भी नाका म दम कर राख्या सै। याडै पहल्या तै इस नासपीटी बीमारी कोरोणा नै दम काढ राख्या सै, अर दूसरा तनै भी रोज-रोज फोन करकै नै म्हारा जी काढण न हौरैया सै। नरेश आकाश ने बताया अब वही माता-पिता फोन करके बच्चों को कार्य कराने का आग्रह कर रहे हैं।

आरंभ में जब लॉकडाउन हुआ है तो सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को भी लग रहा था कि वे एक अजीब सी दौड़ का हिस्सा बन गए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए प्रतिदिन नित नए फरमान उनकी समझ में नहीं आ रहे थे। शिक्षा निदेशालय द्वारा मांगी गई सूचना प्राप्त करने के लिए जब वे बच्चों के घर फोन करके पूछते, आपके घर में कौन सा फोन है? कीपैड वाला या स्मार्ट फोन हैं? आपके घर टेलीविजन है? तो नित नए अनुभव सामने आते।

कुछ माता-पिता ने तो फोन ही नहीं उठाया, शायद सोच रहे होंगे कि मास्टर जी फिर पूछेंगे कि बच्चों ने जो होमवर्क दिया था किया या नहीं... या फिर बच्चों ने टीवी पर कार्यक्रम देखा था, या नहीं?... मैसेज जो भेजा था पढ़ा या नहीं? बहुत से अभिभावकों के जवाब तो इतनें मासूम और पीड़ा से लबरेज होते कि आंखें छलक जाती हैं।

इन प्रश्नों के उत्तर में कई अभिभावकों का जवाब होता, नमस्कार मास्टर जी.. ध्याड़ी पे हूं जी, हम त गरीब सै जी, म्हारै घर म कुछ भी ना सै, याडै तै रोटियां के भी लाले पड रै सै, अर तम नै रोज-रोज नई-नई बात आवै सै, लेकिन अब खुशी की बात है कि राजकीय कन्या उच्च विद्यालय जाहरी के अध्यापक सुरेश दहिया, अशोक, वेदपाल, ऋतु दांगी, राज कुमारी, बबिता, प्राध्यापिका तन्नू सैनी व नवीन के सामुहिक प्रयासों और मुख्याध्यापक मदन लाल गुप्ता के प्रोत्साहन व सार्थक प्रयोगों से विधार्थी ऑनलाइन शिक्षा प्राप्ति के लिए जागरूक व उत्साहित हैं।

हरियाणा से अब तक एक लाख 60 हजार प्रवासियों ने किया पलायन

केंद्र ने चलाई रेलगाड़ियां तो हरियाणा सरकार ने तीन हजार से अधिक बसें लगाई

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

हरियाणा में लॉकडाउन के चलते अब तक एक लाख 60 हजार 300 प्रवासी मजदूर अपने-अपने पैतृक राज्यों को जा चुके हैं। हरियाणा सरकार द्वारा इन श्रमिकों को भेजने के लिए प्रबंध किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यालय से रविवार को जारी जानकारी के अनुसार हरियाणा से तीन रेलगाड़ियां बिहार के लिए रवाना हुई। जिसमें दो ट्रेनें गुरुग्राम और एक ट्रेन पानीपत से चली। इसके साथ ही, 400 बसें उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों के लिए भी रवाना हुई। सीएमओ के प्रवक्ता ने बताया कि 16 मई को तीन ट्रेनों और 492 बसों के माध्यम से 22,672 प्रवासी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में पहुंचाने का कार्य किया गया। उन्होंने बताया कि आज तक 3100 से अधिक बसों के माध्यम से विभिन्न राज्यों में प्रवासी श्रमिकों को पहुंचाया है जिनमें 781 बसें गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश भेजी गई। इसी प्रकार रविवार तक कुल 40 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को बिहार व मध्य प्रदेश राज्यों में पहुंचाया गया हैं जिनमें 28 रेलगाड़ियां बिहार व 12 रेलगाड़ियां मध्य प्रदेश भेजी गई हैं।

अब तक हरियाणा से 75,600 प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश पहुंचाया है। इसी प्रकार, हरियाणा से 37,866 प्रवासी श्रमिकों को बिहार भेजा है। राज्य से उत्तराखण्ड के 14,940 प्रवासी मजदूरों को भेजा गया है, तो वहीं, 19,982 प्रवासी मजदूरों को मध्य प्रदेश भेजा गया है। इसके अलावा 1210 प्रवासी श्रमिकों को जम्मू व कश्मीर, 947 प्रवासी मजदूरों को राजस्थान, 336 प्रवासी मजदूरों को महाराष्ट्र, 223 प्रवासी मजदूरों को पंजाब, 79 प्रवासी मजदूरों को हिमाचल प्रदेश, 62 प्रवासी मजदूरों को असम, 27 प्रवासी मजदूरों को गुजरात, 169 प्रवासी श्रमिकों को दिल्ली, 40 प्रवासी मजदूरों को तमिलनाडू, 57 प्रवासी मजदूरों को पश्चिम बंगाल व 20 प्रवासी श्रमिकों को आंध्र प्रदेश पहुंचाया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि संबंधित जिला प्रशासन से पास लेकर विभिन्न राज्यों में जाने वाले लगभग 8500 प्रवासी श्रमिकों को भी उनके गृह राज्यों में पहुंचा चुके हैं। इसी तरह, लगभग 11 हजार हरियाणा के निवासियों को अन्य राज्यों से हरियाणा लाया गया है। यह प्रकिया जारी है।

प्रवासी मजदूरों पर लाठीचार्ज पर विपक्ष ने सरकार को घेरा

चंडीगढ़। पलायन कर रहे मजदूरों पर यमुनानगर में लाठीचार्ज करने का मुद्दा सियासी तौर पर गर्माने लगा है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यमुनानगर में प्रवासी मजदूरों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि हालात के मारे गरीब मजदूरों पर लाठी बरसाना अमानवीय है। सरकार को इस मुश्किल दौर में मजदूरों से संवेदना के साथ पेश आना चाहिए। सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि किसी मजदूर को यहां से पलायन न करना पड़े। उनके लिए रहने, खाने-पीने, तुरंत राहत राशि या रोजगार की व्यवस्था की जाए। अगर सरकार ऐसा करने में सक्षम नहीं है या गरीब मजदूर घर जाना चाहते है तो प्रवासियों के घर जाने का उचित बंदोबस्त किया जाना चाहिए लेकिन, सरकार ऐसा करने में भी सक्षम नजर नहीं आ रही है और मजदूरों को पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। इनके लिए बस या ट्रेन चलाने की बजाए सरकार इनपर लाठियां चला रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। महामारी की सबसे ज्यादा मार इन गरीब मजदूरों पर ही पड़ी है। इसलिए सरकार को इनके प्रति अपनी प्रशासनिक और मानवीय दोनों जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। हुड्डा ने एक और गंभीर मुद्दे की तरफ सरकार का ध्यान खींचते हुए आग्रह किया कि गुड़गांव और दूसरे कई जिलों से ज्यादातर कोरोना मरीजों को पीजीआई रोहतक रेफर किया जा रहा है। इससे पीजीआई पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी बीमारियों का इलाज सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। इसलिए सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरोना मरीजों को आसपास के ही अस्पतालों में इलाज मिले। इससे संक्रमण का खतरा भी कम होगा और मरीजों को परेशानी भी नहीं होगी।

यूपी ने हरियाणा से गए डेढ़ हजार प्रवासी मजदूर लौटाए

यमुनानगर, अंबाला समेत कई जिलों से गई थी बसें

चंडीगढ़। लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश प्रशासन का अमानवीय चेहरा सामने आया है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से 50 बसों में सवार होकर यूपी पहुंचे 1500 प्रवासी मजदूरों को लौटा दिया गया है। इन मजदूरों को सहारनपुर से कानून-व्यवस्था का हवाला देकर वापस भेजा गया है। हरियाणा सरकार ने रविवार को इन मजदूरों को दोबारा उन्हीं जिलों में भेज दिया है जहां से इन्हें बसों में भरकर यूपी भेजा गया था।

हरियाणा सरकार द्वारा पिछले कई दिनों से प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों में भेजा जा रहा है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार तथा हरियाणा सरकार के बीच शुरू से सहमति बनी हुई है। यूपी के कई जिले हरियाणा से सटे होने के कारण हरियाणा रोडवेज की बसों से प्रवासी मजदूरों को भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले करीब 1500 कामगारों को हरियाणा से भेजने की मंजूरी दी थी, मगर रविवार को इन मजदूरों के साथ काफी बुरा हश्र हुआ। इन मजदूरों को लेकर हरियाणा रोडवेज की 50 बसें जैसे ही सहारनपुर की सीमा में पहुंची तो उन्हें रोक दिया गया। गृह मंत्री अनिल विज के अनुसार वहां मजदूर पहले से आंदोलनरत थे। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने हमारे अफसरों से कहा कि इन मजदूरों को वापस लिया जाए, क्योंकि स्थिति कंट्रोल में नहीं है और उनके रुकने का कोई इंतजाम नहीं हो सकता। लिहाजा सभी मजदूरों व कामगारों को लेकर हरियाणा रोडवेज की बसें वापस आ गई। जिस जिले से जो बस आई थी, फिलहाल उसे वहीं पर भेज दिया गया है।

अपने ही लोगों को लेने को तैयार नहीं कई राज्य

हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने बताया कि सरकार इन कामगारों व प्रवासी मजदूरों को उनके मूल राज्यों में भेजना चाहती है और इसके लिए सरकार ने पुख्ता इंतजामों भी किए हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत विभिन्न राज्य सरकारें हरियाणा सरकार को इन प्रवासियों को भेजने के लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) नहीं दे रही हैं। बिना एनओसी के न तो रेलगाड़ी बुक की जा सकती है और न ही बसें भेजी जा सकती हैं। यदि राज्य सरकारें एनओसी दें तो सभी प्रवासियों को चार से पांच दिन के भीतर उनके मूल राज्यों में पहुंचाने का इंतजाम किया जा सकता है।

संक्षिप्त समाचार

मानव सेवा से हम कर सकते हैं सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन

कुरुक्षेत्र। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि सेवा ही सद्भावना और सच्ची मानवता है। कोरोना महामारी के कारण देश में आए संकट के समय हमें इससे प्रभावित सभी लोगों की आगे आकर सहायता करनी चाहिए और जरूरतमंदों की मदद भी करनी चाहिए। इस प्रकार मानवता की सेवा कर हम अपने सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन कर सकते है। इससे पहले गत दिवस श्रीकृष्ण कृपा सेवा समितियों ने स्वामी ज्ञानानंद महाराज का जन्म दिवस सद्भावना दिवस के रूप में लोगों की सेवा और जरूरतमंदों को राशन बांटकर मनाया। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज गीता ज्ञान संस्थान में बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण कृपा सेवा समितियों को निर्देश दिए हैं कि वह प्रतिदन कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों की सहायता करें। उन्होंने का कि लॉकडाउन के दौरान श्रीकृष्णा कृपा परिवार की तरफ से बस्तियों में जरूरतमंद व्यक्तियों व मजदूरों को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत अब तक 12 हजार किट्स वितरित की गई हैं। 2121 परिवारों को राशन सामग्री प्रदान की है। श्रीकृष्ण कृपा परिवार की तरफ से गऊशालाओं का भी संचालन किया जा रहा है, जिसमें गऊओं की सेवा की जा रही है। उन्होंने कहा कि 15 मई को थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन कर विभिन्न जिलों में 600 यूनिट रक्त एकत्रित किया है। उन्होंने कहा कि हजारों गीता परिवारों ने कोरोना महामारी के प्रकोप से शीघ्र राहत के लिए गीता पाठ व सेवा सद्भावना यज्ञ भी किया गया, ताकि मानवता को जल्द ही इस बिमारी से निजात मिल सके।

भाजपा सरकार ने पेश किया है एक और आर्थिक पैकेज का जुमला

कुरुक्षेत्र। प्रदेश कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष एडवोकेट मधुसूदन बवेजा ने कहा कि भाजपा ने एक बार फिर जुमला पैकेज देशवासियों के समक्ष पेश किया है। कहने को तो यह लॉकडाउन में लोगों को स्वरोजगार देने और उनका आर्थिक स्तर उठाने का अभियान है, लेकिन इसकी हकीकत जगजाहिर है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा किसानों, खेतिहर मजदूरों, मछुआरों आदि के लिए कथित आर्थिक पैकेज भी एक ऐसा जुमला है, जिसमें संकटग्रस्त किसान, मजदूरों, गरीबों, मछुआरों और आदिवासियों को संकट से निपटने में कोई आर्थिक सहायता देने बजाए उन्हें मुंगेरीलाल के सपने दिखाए गए है। सवाल तो यह उठता है कि भविष्य की योजनाओं से क्या इन तबकों का वर्तमान का आर्थिक संकट मिट जाएगा, क्या भविष्य की खुशहाली के सपनों से आज का आर्थिक संकट खत्म हो जाएगा। एडवोकेट बवेजा ने उदाहरण देते हुए कहा वर्ष 2014 में किसान को सपना दिखाया था कि 2017 तक उसकी आय दोगुनी कर दी जाएगी। फिर कहा गया 2019 तक आय दोगुनी होगी और 2019 में कहा गया वर्ष 2022 में आय दोगुनी होगी और अब 2020 में कहा जा रहा है वर्ष 2025 में आय दोगुनी होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में कह दिया जाएगा कि 2030 में आय दोगुनी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक पैकेज के नाम पर कर्ज लेने का हाका लगा रही है। सरकार कह रही है कि कर्ज ले लो, कर्ज ले लो, काम करो, कर्ज बढ़ाओ और मोदी के गुण गाओ।

प्रवासी मजदूरों का पैदल घर पंहुचने का संघर्ष जारी

रादौर। कोरोना महामारी के चलते प्रवासी मजदूरों का लगातार पैदल अपने घर पहुंचने के लिए संघर्ष जारी है। कई कई दिनों से भंयकर गर्मी में कई किलोमीटर से प्रवासी मजदूर अपने परिवारों के साथ रादौर क्षेत्र से गुजर रहे हैं, लेकिन शनिवार शाम को प्रशासन ने पुलिस की मदद से प्रवासी मजदूरों का उत्तर प्रदेश की ओर यमुनानदी के रास्ते जाने पर कठोरता से प्रतिबंध लगा दिया। जिसके बाद शनिवार देर शाम 21 प्रवासी मजदूरों को शहर के निरंकारी भवन में ठहराया। रविवार को पुलिस ने यमुनानदी के अलग-अलग घाटों की ओर जा रहे मजदूरों को यमुनापार जाने से रोक दिया। जिसके बाद लगभग 78 प्रवासी मजदूरों को शहर की शहीद उधमसिंह धर्मशाला में ठहराया। जहां उनके रहने व खाने की व्यवस्था की गई। इसके बावजूद रविवार शाम को भी प्रवासी मजदूरों का काफी संख्या में पैदल रादौर क्षेत्र में पहुंचना जारी था। रादौर के लोग सड़कों से गुजर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए खाने-पीने की व्यवस्था करते नजर आये। प्रवासी मजदूर रामलखन, मोहन, नरेंद्र, उमेश आदि ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कारखाने बंद होने से देश के करोड़ों मजदूर बेरोजगार हो गये है। जिनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। इसलिए मजबूरी में मजदूर पैदल ही घर जा रहे है। लेकिन रास्ते में पुलिस उन्हे परेशान कर रही है। जबकि वह शांतिपूर्वक घर जा रहे है।

वाल्मीकि समाज सहित 36 अन्य जातियों को मिलेगा लाभ

सोनीपत। अनुसूचित जाति आरक्षण में सरकार द्वारा शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने से अनुसूचित जाति समाज के लोगों में खुशी का माहौल है। हरियाणा वाल्मीकि महापंचायत सोनीपत चेयरमैन राजीव पिहवाल एवं इंजीनियर रणवीर सिंह ने सरकार का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि इस फैसले से वाल्मीकि जाति के साथ बाजीगर धानक, खटीक, डेहा, बंजारा और नट, वादी, मजहबी, सपेरा, सिकलीगर व पासी सहित 36 जातियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस घोषणा से सभी जातियों के युवाओं को भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने 16 जून 2019 को जींद में कबीर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में वादा किया था कि यदि प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनती है तो शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति के आरक्षण में आरक्षण का प्रावधान लागू करेंगे। इस मौके पर एचवीएम वाइस चेयरमैन रवि कुमार टांक, जिला ग्रामीण चेयरमैन विजय पिहवाल, कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार, जिला अध्यक्ष संदीप सारसर, सचिव सतवीर सिंह, शाहिल राणा, मास्टर नरेंद्र सारसर, संदीप बागड़ी, राकेश सरपंच, जयकिशन, मनजीत पिहवाल, सुरज एवं इन्द्रजीत राणा आदि ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद किया।

इंद्री के गांव चौंगावा में एक पॉजिटिव केस मिला

इंद्री। गांव चौंगावा में कोरोना वायरस पॉजिटिव एक केस मिलने से पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति व उसके परिवार के सभी सदस्यों को करनाल कल्पना चावला मेडिकल हस्पताल में भेज दिया है। इंद्री के एसडीएम सुमित सिहाग ने बताया कि गांव चौंगावा में एक कोरोना पॉजिटिव केस मिलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही वे मेडिकल टीम के साथ गांव पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि ईश्वर सिंह नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नि व दो बच्चों के साथ दो दिन पहले ही गुरुग्राम से अपने गांव में आया था। मुलाना मेडिकल कॉलेज में उसे कोई सर्जरी करानी थी। वहां उसकी कोरोना जांच की गई तो पॉजिटिव निकला। सिहाग ने बताया कि उसके परिवार के कुल दस लोग हैं जिन्हें कल्पना चावला मेडिकल हस्पताल करनाल में दाखिल करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिस गली में ईश्वर सिंह रहता था उस गली को कन्टेमैंट जोन घोषित कर दिया है। सिहाग ने बताया कि बाकि गांव को बफर जोन घोषित किया गया है।

मीडिया सेंटर का इंटरनेट दो माह से खराब

कैथल। पिछले करीब दो महीने से मीडिया सेंटर में इंटरनेट सेवा खराब होने के कारण विभिन्न समाचार पत्रों और टीवी चैनल के पत्रकारों को भारी दिक्कतों का समाना करना पड़ रहा है। इस बारे में कई बार जिला लोक संपर्क अधिकारी और बीएसएनएल के एसडीओ को कहा गया है लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। इंटरनेट सेवा लचर होने के कारण पत्रकारों को अपने फोन से नेट सेवा कनेक्ट करके समाचार संप्रेषण का काम करना पड़ रहा है। मीडियाकर्मियों की मांग है कि इंटरनेट सेवा तुरंत बहाल की जाए ताकि उनके काम में बाधा ना आए।

पुलिस कर्मियों को मास्क व सैनेटाइजर बांटे

पुलिसकर्मियों को मास्क व सैनेटाइजर वितरित करते समाजसेवी राजन कुकरेजा।

असंध। लॉकडाउन में नगर के जींद चौक पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को समाजसेवी राजन कुकरेजा ने मास्क व सैनेटाइजर वितरित किए। कोरोना योद्धा पुलिसकर्मी, सफाईकर्मी व चिकित्सक अपनी व अपने परिवार की जान की परवाह किए बिना जी-जान से लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की जंग में एसडीएम अनुराग ढालिया, तहसीलदार नवजीत कौर बराड, डीएसपी दलबीर सिंह व नगरपालिका सचिव राजेश शर्मा दिन-रात मेहनत कर रहे हैं।

समाजसेवी राजन कुकरेजा ने कहा कि असंध प्रशासन की गाइडलाइन से ही असंध क्षेत्र सुरक्षित है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सरकार व प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। आपको यहां बता कि लॉकडाउन के नियमों के पालन की सराहना करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों मे एसडीएम अनुराग ढालिया और उनकी टीम पर सरपंचों, किसानों, नम्बरदारों और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोगों ने पुष्प वर्षा की थी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमण से बचाव के लिए सरकार व प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं।

स्कूल स्टाफ को नहीं दे पा रहे दो माह का वेतन

लॉकडाउन : प्राइवेट स्कूल संचालक रो रहे अपना दुखड़ा

मोहित गुलाटी। कैथल

प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा अपने स्टाफ का वेतन न दिए जाने से स्कूल के अध्यापकों और अन्य स्टाफ सदस्यों को घर का खर्च चलाने में कठिनाई हो रही है। पिछले दो महीने से प्राइवेट स्कूल संचालक अपने स्टाफ को वेतन नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन अध्यापक, अध्यापिकाओं व अन्य गैर शिक्षक स्टाफ को दिक्कत आ रही है जिनका घर स्कूल की सेलरी से चलता है।

स्कूल संचालकों और सरकारी नियमों का पालन करते हुए ये स्कूल अध्यापक घर से ऑनलाइन कक्षाएं ले कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। ये अध्यापक, अध्यापिकाएं लॉकडाउन के कारण अपने घरों से ही ऑन लाइन कक्षाएं लेकर अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल अध्यापकों का कहना है कि यदि लॉकडाउन लंबे समय तक चलता है और स्कूल नहीं खुलते हैं तो उनके घर का खर्च कैसे चलेगा।

वे कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते जिससे उन्हें कुछ आमदनी हो जाए। प्राइवेट स्कूल संचालकों का वेतन न देने के पीछे यह तर्क है कि सरकार की हिदायतों के अनुसार वे पूरी फीस नहीं ले सकते तो वेतन कहां से देंगे।

अभिभावक सहयोग नहीं कर रहे : वरुण जैन

इस बारे में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के राज्य सचिव वरुण जैन का तर्क था कि बच्चों के अभिभावक सहयोग नहीं कर रहे इसलिए उन्हें स्टाफ का वेतन देने में कठिनाई हो रही है। लॉकडाउन के आरंभ में सरकार ने फीस लेने से मना कर दिया था लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व सरकार की गाइड लाइन आई है कि प्राइवेट स्कूल केवल मासिक ट्यूशन फीस ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकतर पेरेन्ट्स मासिक फीस भी नहीं दे रहे, केवल पांच प्रतिशत अभिभावकों ने मासिक फीस दी है। इसके बावजूद वे अपने स्टाफ को वेतन देने का प्रयास कर रहे हैं। जैन ने बताया कि ज्यादातर स्कूलों ने अप्रैल महीने की सेलरी दे दी है।

स्टाफ की सेलरी दें प्राइवेट स्कूल : डीईओ

इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी बीएस नारवाल का कहना था कि सरकार ने प्राइवेट स्कूल संचालकों को मासिक फीस लेने के लिए कह दिया है। स्कूल संचालकों को चाहिए कि स्टाफ का वेतन दें ताकि उनके घर का खर्च चलता रहे। वैसे भी यह स्कूल संचालकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने स्टाफ का वेतन दें।

उल्देपुर की 60 वर्षीय महिला में हुई कोरोना की पुष्टि

सोनीपत। उपायुक्त डॉ. अंशज सिंह ने कहा कि रविवार को उल्देपुर गांव की एक 60 वर्षीय महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस एक नये केस के साथ सोनीपत जिला में कोविड-19 कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 135 पर पहुंच गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उपायुक्त डॉ. सिंह ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि सोनीपत में कोरोना वायरस का एक और पॉजिटिव केस मिला है। उन्होंने कहा कि सोनीपत दो दिन पूर्व कोरोना वायरस से पहली मृत्यु हुई थी, जिसका संबंध ठरू गांव से था। उन्होंने कहा कि नये केस में संक्रमित पाई गई वृद्ध महिला उस मृतक महिला की बहन है।

इस दौरान उपायुक्त डा. सिंह ने लोगों का आह्वान किया कि वे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए हर संभव उपाय अपनायें। जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण पालन करें।

नंगे पैर पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों दी चप्पल

गोविंद रसोई ने दी जरूरतमंदों को बांटे भोजन के पैकेट

पायनियर समाचार सेवा। सोनीपत

जरूरतमंदों के लिए भोजन के पैकेट तैयार करते लोग।

सेफ इंडिया फाउंडेशन ने रविवार को रोड पर पैदल चलने वाले प्रवासी मजदूरों को चप्पल वितरण अभियान चलाया। जिसमें करीब 30 मजदूरों व उनके बच्चों को चप्पल वितरित की गई, जो नंगे पैर ही पलायन कर रहे थे।

गोविन्द रसोई द्वारालॉक डाउन के दौरान जरूरतमंद, गरीब व पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को भोजन वितरित करने का कार्य लगातार जारी है। रविवार को गोविन्द रसोई द्वारा मुरथल तथा सैल्टर सेंटर राई में मजदूरों को भोजन खिलाया गया व रास्ते के लिए भोजन के पैकेट वितरित किये गए। गोविंद रसोई द्वारा पलायन कर रहे करीब 30 मजदूरों व उनके बच्चों को चप्पल भी वितरित की गई, जोकि नंगे पैर ही पलायन कर रहे थे। खाना वितरित करने का कार्य जिला प्रशासन की देखरेख में किया गया। इसके अलावा सेफ इंडिया फाउंडेशन व रोटरी क्लब आफ सोनीपत एक्सीलेंस व महाराजा अग्रसेन समाज कल्याण समिति सोनीपत द्वारा संचालित गोविंद रसोई द्वारा लॉकडाउन के दौरान 2079 लोगों को खाना वितरित किया। चेयरमैन वाईके त्यागी व प्रधान संजय सिगंला ने बताया कि श्री श्याम एकता परिवार मंडल ने 11 हजार रुपये का आर्थिक योगदान दिया। जिसमें प्रमोद गोयल, संजय सिगंला, अंकुर सिंगला व पुनीत कुमार का योगदान रहा। डॉक्टर अनिता सिंह ने भी गोविंद रसोई में सहयोग दिया व सेवा कार्य किया।

इस कार्य में प्रवीण वर्मा, दिनेश कुच्छल, महेंद्र अरोरा, अरविंद मित्तल, मनीष बंसल, अशोक गुप्ता, शालू त्यागी, राम कुमार जिंदल, टिका राम मित्तल, पवन अग्रवाल, सचिन गर्ग, सतपाल गुप्ता, राजेश गर्ग, प्रदीप खन्ना, विजय कुमार, मनोज जैन, मनीष कुच्छल, चन्द्र भान, अनिपाल, राधा स्वामी सत्संग मंडल की सेवक मंडली तथा निरंकारी सेवा मंडल व श्रीराम शरणम आश्रम आदि ने सहयोग दिया।

पहले की तरह जारी रहेगा ओड-ईवन नम्बर

करनाल। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि लॉकडाउन 4 की घोषणा के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस रविवार देर रात तक आने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि जैसे पहले लॉकडाउन 3 की स्थिति में कार्य चल रहे हैं अभी उसी प्रकार से कार्य चलेंगे, लेकिन दुकानों के समय में बदलाव किया है, पहले दुकानें प्रात: 8 से दोपहर दो बजे तक खुलती थी अब दुकानें प्रात: 9 से सायं पांच बजे तक खुलेंगी।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा ढाबे और रेस्टोरेंट पहले की तरह सिर्फ होम डिलीवरी ही कर सकते हैं। जिस भी क्षेत्र में ओड-ईवन के हिसाब से दुकानें खुल रही हैं, वह दुकानें अब भी ओड-ईवन के हिसाब से ही खुलेंगी। उन्होंने बताया कि दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होता और मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य है, इसे जरूर लगाएं।

उन्होंने बताया कि करनाल वासियों ने जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक भरपूर सहयोग दिया है और आगे भी भरपूर सहयोग जिला प्रशासन को मिलता रहेगा ऐसी उन्हें पूरी उम्मीद है। उन्होंने बताया कि दुकानें ठीक शाम 5 बजे बंद हो जानी चाहिएं, जो भी दुकानदार इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ नियमानुसार प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

सड़क-रेलवे ट्रैक पर दिखें मजदूर तो भेजें शेल्टर होम

मजदूरों की देखभाल हमारी जिम्मेदारी, उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे : केजरीवाल

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

केजरीवाल सरकार ने अधकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी प्रवासी मजदूर सड़क या रेलवे ट्रैक पर चलता हुआ दिखाई नहीं दे। अगर कोई मिले तो उसे समझाया जाए ओर उसको पास के शेल्टर होम में ले जाकर उसके खाने-पानी और रहने की समुचित व्यवस्था करें। ऐसा तब तक किया जाए जब तक कि उनको उनके राज्य में बस या श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए पहुंचाने की व्यवस्था नहीं हो जाती। रेलवे के साथ बेहतर समन्वय सहयोग स्थापित करें ताकि जल्द मजदूरों को विशेष ट्रेन के जरिए उनके राज्यों में भेजा जा सके।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के मद्देनजर आने वाले संकट के दौरान प्रवासी श्रमिकों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ेगी। दिल्ली में रहने वाले हर प्रवासी मजदूरों की जिम्मेदारी उनकी है। अगर वे यहां रहना चाहते हैं, तो सरकार उनका पूरा ध्यान रखेंगी। यदि वे अपने घर वापस जाना चाहते हैं तो वह उनके लिए ट्रेनों की व्यवस्था करेंगे। जो भी मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें *https://epass-jantasamvad-org/train/passenger/* पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि सभी अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि किसी प्रवासी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनके लिए जितनी जरूरत होगी, उतनी ट्रेन का इंतजाम किया जाएगा।

आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 22 के जारी दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रवासी श्रमिक सड़क और रेलवे पटरियों पर चलने का सहारा न लें। यदि वे ऐसी स्थिति में पाए जाते हैं, तो उन्हें समझा कर पास के शेल्टरों में ले जाया जाए और भोजन, पानी आदि मुहैया कराया जाए। यह सुविधा तब तक दी जाए, जब तक उनके लिए अपने मूल स्थानों तक जाने के लिए श्रमिक ट्रेनों या बसों की सुविधा न कर दी जाए।

दिल्ली के शेल्टर होम में प्रवासी मजदूरों से बात करते उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया।

इस बीच उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 25 से अधिक ट्रेनों और बड़ी संख्या में बसों के जरिए 35,000 प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों में पहुंचा दिया है और आज 8 श्रमिक विशेष ट्रेनें लगभग 12,000 प्रवासी मजदूरों को उनके घरों में ले जाएंगी। पहले से ही 25 से अधिक ट्रेनों और बड़ी संख्या में बसों के जरिए 35,000 से अधिक लोगों को उनके गंतव्य राज्यों में पहुंचाया गया है। प्रवासी मजदूर जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें https://epass-jantasamvad-org/train/passenger/ पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।

पंजीकरण होने के बाद उनसे संबंधित ट्रेनों व बसों के प्रस्थान और समय के बारे में उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। बिना पंजीकरण के किसी भी यात्री को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिसोदिया ने रविवार को कुछ ऐसे शेल्टर केंद्रों का दौरा किया, जहां दिल्ली सरकार ने प्रवासी मजदूरों के ठहरने, भोजन और चिकित्सा जांच की व्यवस्था की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इनमें से अधिकांश मजदूर 2-6 महीने पहले नौकरी के लिए दिल्ली आए थे।

विचाराधीन कैदी को मिली सशर्त जमानत

नई दिल्ली। हत्या के मामले में गिरफ्तार विचाराधीन कैदी को दिल्ली की एक अदालत ने अंतरिम जमानत दी है। साथ ही उसे निर्देश दिया कि वह अपने फोन में 'आरोग्य सेतु' ऐप डाउनलोड करे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवीन कुमार कश्यप ने शनिवार को आरोपी रवि धीका को जमानत दे दी। उसने याचिका में अनुरोध किया था कि उसे अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करनी है, जिसका इलाज चल रहा है और उसकी देखभाल वाला कोई नहीं है।

जांच अधिकारी ने पुष्टि की कि पत्नी के इलाज के बारे में आरोपी के तर्क सत्य हैं जिसके बाद अदालत ने यह आदेश जारी किया। अदालत ने उसे अपने मोबाइल फोन पर 'आरोग्य सेतु' ऐप डाउनलोड करने का निर्देश देने के साथ ही कहा कि रिहाई के दौरान वह अपने मोबाइल फोन का जीपीएस लोकेशन और ब्लूटूथ भी खुला रखे। न्यायालय ने धीका को निर्देश दिया कि साक्ष्यों, गवाहों को प्रभावित नहीं करे और न्याय से नहीं भागे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाया हिरासत में लेने का आरोप

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी को दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर ही हिरासत में ले लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार से प्रवासी मजदूरों को दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर पहुंचाया और वहां भीड़ जुटा दी। चौधरी का कहना है कि प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। हालांकि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस आरोप को खारिज कर दिया।

अनिल चौधरी के अनुसार रविवार सुबह तकरीबन 10 दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने उनके दल्लूपुरा घर पर बिना किसी लिखित आदेश के हाउस अरेस्ट कर लिया और घर से बाहर नहीं जाने नहीं दिया। जो सरासर उनके मानव अधिकारों का हनन है। उनका आरोप है कि यह कार्रवाई भाजपा और आम आदमी पार्टी कि बोखलाहट का नतीजा है क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान

पुलिस का इनकार

आओ हाथ बढ़ाएं कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस की रसोई चलाई जहां पर रोजाना लगभग 50 हजार प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों को ताजा पका हुआ पौष्टिक खाना खिलाते है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुमार से केवल पूछताछ की गई और घर में रहने के लिए कहा गया। वह इलाके में गश्त कर रहे थे जब उन्हें कुछ प्रवासी श्रमिकों से पता चला कि अनिल ने उन्हें उनके गृह राज्य भेजने में मदद करने का आश्वासन दिया था। इसलिए उन्होंने उनसे घर में रहने और बाहर न निकलने का अनुरोध किया।

दिल्ली में फंसी पूर्वोत्तर की बच्चियों को है घर वापस जाने का इंतजार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

आठ साल की नन्हीं सी नंदिनी छुट्टियों में अपनी मां के पास नगालैंड जाने को लेकर बेहद उत्साहित थी लेकिन लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में ही फंस गई और अब विशेष ट्रेन में टिकट उपलब्ध नहीं होने से घर जाने का लंबा इंतजार उसे मायूस कर देता है।

वह हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले के दैहण में 'भारतीय जनसेवा संस्थान' के 'मातृछाया' छात्रावास में रहकर पढ़ रहीं पूर्वोत्तर की उन 26 लड़कियों में से है जिन्हें 22 मार्च को दिल्ली से गुवाहाटी और फिर अपने अपने घर जाना था । जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन के कारण वे जा ही नहीं सकीं ।

इनमें असम की चार, मेघालय की छह और नगालैंड की 16 गरीब परिवारों की लड़कियां हैं जिनकी उम्र आठ से 15 वर्ष है । नगालैंड के दीमापुर में रहने वाली नंदिनी की मां खेती करती है और पिता अब नहीं रहे । उसने बताया कि उसकी मां उनका इंतजार कर रही है। दिन भर तो समय कट जाता है लेकिन रात को मां की याद आती है। बहुत दिन हो गए मां से मिले। फोन पर बात होती है लेकिन बहुत थोड़ी देर।

चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मियों ने किया प्रदर्शन

नोएडा। सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल के पृथक-वास में काम करने वाली चतुर्थ श्रेणी महिलाओं ने सैलरी को लेकर रविवार को 18वीं मंजिल पर चढ़कर प्रदर्शन किया। इस मामले की जांच मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह तथा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अमित विक्रम सिंह को सौंपी गई है।

जिला सूचना अधिकारी बताया कि जिला अस्पताल के पृथक-वास में काम करने वाली महिलाओं ने रविवार को अपनी सैलरी को लेकर प्रदर्शन किया। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तत्काल मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इसकी जांच का निर्देश दिया।

हिंदू राव अस्पताल के 6 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

हिंदू राव अस्पताल के छह स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ये सभी एक कोविड-19 मरीज के संपर्क में आए थे। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि इन कर्मचारियों को 63 अन्य लोगों के साथ क्वॉरंटीन में रखा गया था क्योंकि वे उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित इस अस्पताल में डायलसिस कराने आए कोविड-19 मरीज के संपर्क में आए थे।

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में कोरोना का डबलिंग रेट अभी 11 दिन के

मृतकों की संख्या 148, 9,755 मरीज संक्रमित

आसपास है और कल का ग्रोथ रेट 4-4.5 प्रतिशत है। लेकिन ग्रोथ दर 4.5 प्रतिशत के हिसाब से तो केस के दोगुना होने की दर 18 दिन बन जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जीतने भी केस आज हैं, इससे आधे कितने दिन पहले थे। फिलहाल दिल्ली में केस दोगुना होने की दर करीब 11 दिन है।

रविवार को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राजधानी में 276 मरीज ठीक हुए हैं।

डीयू के प्रोफेसरों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र

ओपन-बुक परीक्षा कराने के फैसले के खिलाफ हैं शिक्षक

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय के चार प्रोफेसरों ने कोविड-19 के कारण पैदा हुए हालात सामान्य नहीं होने की स्थिति में ओपन-बुक के जरिए ऑनलाइन परीक्षाएं कराने के विश्वविद्यालय के मनमाने फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिखा है।

ओपन-बुक परीक्षा में परीक्षार्थियों को सवालों के जवाब देते समय अपने नोट्स, पाठ्य पुस्तकों और अन्य स्वीकृत सामग्री की मदद लेने की अनुमति होती है। छात्र अपने घरों में बैठकर वेब पोर्टल से अपने-अपने पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र डाउनलोड करेंगे और दो घंटे के भीतर उत्तर-पुस्तिका जमा करेंगे।

पत्र लिखने वाले चार प्रोफेसर कौशल पंवार, प्रेमचंद, डॉ. डी आर अनिल कुमार और दीपांकर हैं। पत्र में कहा गया है, वह आपसे इस बात पर तुरंत ध्यान देने की अपील करते हैं कि विवि प्रशासन ने मनमाने तरीके से फैसला किया और 13 मई 2020 को सभी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखकर प्रश्न पत्र के तीन सेट्स ओपन-बुक परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए कहा।

प्रोफेसरों ने कहा, ओपन-बुक से परीक्षा कराने का यह कदम उच्च शिक्षा को निजीकरण की ओर लेकर जाएगा। उन्होंने कहा कि ओपन-बुक और क्लोज-बुक व्यवस्थाएं बिल्कुल अलग-अलग हैं। दोनों व्यवस्थाओं में प्रश्न पत्र की आवश्यकताएं भी अलग होती हैं। प्रोफेसरों ने दावा किया कि ओपन-बुक परीक्षा विभिन्न स्तरों पर छात्रों के बीच एक तरह से भेद-भाव को भी बढ़ावा देगी। जिन छात्रों के पास संसाधन हैं, केवल उन्हें ही इसका फायदा मिल सकता है।

इस बीच एबीवीपी के नेतृत्व में डीयू छात्र संघ ने छात्र प्रतिनिधियों, डूसू के 8 कार्यकारी परिषद सदस्यों व 41 निर्वाचित कॉलेज संघ प्रतिनिधियों की एक आम सभा बुलाई।

कंपनी के दो सुरक्षाकर्मी मिले कोरोना संक्रमित

नोएडा। शनिवार देर शाम चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो के दो सिक्योरिटी गार्डों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। इसके बाद मोबाइल कंपनी और दनकौर कोतवाली क्षेत्र के नवादा गांव में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना संक्रमित नवादा गांव के व्यक्ति के परिजनों को क्वॉरेंटाइन सेंटर भेजा है। वहीं, वीवो कंपनी के भी 283 कर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें कोरोना से बचाव के निर्देश जारी किए गए हैं।

नवादा गांव निवासी एक युवक क्षेत्र में स्थित एक चाइनीज कंपनी में सुरक्षा गार्ड है। जिसकी मेडिकल रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई है।

साठ फीसद से अधिक यौनकर्मी गृह राज्यों को लौटीं

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

लॉकडाउन के कारण आजीविका के साधन खत्म होने के कारण भुखमरी की कगार पर आई यौनकर्मी अपने गृह राज्यों को लौट गईं। संक्रमण के डर से ग्राहक नहीं मिल रहे जिसका असर शहर की यौनकर्मियों पर पड़ रहा है।

देशभर के यौन कर्मियों के लिए कानूनी अधिकार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर काम करने वाले समूह ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स (एआईएनएसब्लयू) की अध्यक्ष कुसुम ने कहा कि दिल्ली की 60 फीसदी यौनकर्मी अपने गृह राज्यों के

लॉकडाउन के कारण भुखमरी के कगार पर

लिए निकल चुकी हैं। उन्होंने बताया सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पंजीकृत यौनकर्मियों की संख्या कुल पांच हजार है और गृह राज्यों को लौटने वाली यौनकर्मियों की संख्या तीन हजार है। भोजन और दवाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कई हफ्तों के संघर्ष के बाद उन्हें शहर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।

एक यौनकर्मी ने बताया कि आठ साल यहां रहने के बाद आखिरकार उसे उत्तर प्रदेश में अपने गांव को जाना पड़ा। एक अन्य युवती ने कहा वह उप्र के अपने घर से 18 साल की उम्र में भाग गई थी। वह अभिनेत्री बनना चाहती थी लेकिन आजीविका के लिए इस धंधे में आ गई। जब से लॉकडाउन लगा है, कोई ग्राहक नहीं है और सारी जमापूंजी खत्म होती जा रही है।

एक अन्य ने बताया कि उसने और उसके चार साल के बेटे ने दो महीने से ठीक से खाना नहीं खाया। कमजोरी के कारण जब बेटा बेहोश हो गया तो उसने घर लौटने का फैसला किया। अन्य कई यौनकर्मी भी ऐसी ही बेबसी की शिकार हैं। ये सभी यौनकर्मी जीबी रोड पर रहती हैं जहां करीब 100 वेश्यालय हैं, इनमें करीब 1500 यौनकर्मी रहती हैं।

नाले में मिला नवजात शिशु का शव, मां की तलाश में पुलिस

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

थाना सेक्टर 49 क्षेत्र की पुलिस को बरौला गांव के पास बह रहे बड़े नाले में रविवार सुबह नवजात शिशु का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस को शक है कि बच्चे की मां ने लोक लज्जा के कारण से उसे पैदा होते ही नाले में बहा दिया।

सहायक पुलिस आयुक्त विमल कुमार सिंह ने बताया कि रविवार सुबह थाना सेक्टर 49 पुलिस को सूचना मिली कि बरौला गांव के पास से बह रहे बड़े नाले में एक नवजात शिशु का शव दिखा है। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सिंह ने बताया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जन्म लेते ही बच्चे की मां ने उसे नाले में फेंक दिया है।

एसीपी ने बताया कि पुलिस को शक है कि बच्चे की मां कुंवारी है तथा उसने लोक लज्जा के कारण जन्म देते ही अपने बेटे को नाले में फेंका दिया। पुलिस बच्चे की मां का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

संक्षिप्त समाचार

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कतार में खड़े प्रवासी मजदूर। फोटो : रंजन डिमरी

बिहार छोड़ने के नाम पर मजदूरों से ठगी

गाजियाबाद। बिहार ले जाने के नाम पर 40 मजदूरों के साथ ठगी का मामला सामने आया है। दिल्ली यूपी की सीमा पर कुछ मजदूरों का आरोप है कि दिल्ली में ट्रक ड्राइवर ने 83 हज़ार रुपये लेकर बिहार छोड़ने का वादा किया था लेकिन ट्रक जैसे ही यूपी की सीमा में दाखिल हुआ, वैसे ही पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। ट्रक ड्राइवर ने पूरे पैसे भी वापस नहीं किए। आरोप है कि 83,000 रुपये में से 15000 रुपये ट्रक ड्राइवर ने वापस नहीं लौटाए। इतना ही नहीं इन मजदूरों को वापस दिल्ली भी नहीं जाने दिया गया। ऐसे में ये मजदूर घण्टों दिल्ली-गाजियाबाद की सीमा यूपी गेट पर धूप में बैठे रहे। इनका कहना है कि इनके 15 हजार रुपये वापस दिलवाए जाएं, और इन्हें वापस जाने दिया जाए।

फीस के लिए स्कूल बना रहे दबाव

गाजियाबाद। अभिभावकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक से फिर शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि कई स्कूल संचालक फीस अदा न कराने वाले अभिभावकों पर दबाव बनाने के लिए लॉकडाउन में जिन अभिभावकों ने फीस जमा कर दी है उनकी भुगतान रसीदों की फोटो वरुचुअल क्लास ग्रुप पर डाल रहे हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक रविदत्त शर्मा ने चेतावनी दी है कि कोई भी विद्यालय इस तरह की हरकत नहीं करेगा। इस तरह से दबाव डालने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी। अभिभावकों का कहना है कि विद्यालयों की इस हरकत से उनके बच्चों में हीन भावना आ रही है। उन्हें लग रहा है कि दूसरे बच्चों के माता-पिता ने फीस जमा कर दी, लेकिन उनके अभिभावक अभी फीस जमा नहीं कर पाए। इससे बच्चों की मानसिक स्थिति पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। फीस जमा न कर पाने वाले अभिभावकों का कहना है कि कुछ अभिभावक तो खुद भी फीस जमा करके रसीदें ग्रुप पर डाल रहे हैं, जोकि गलत है।

झंडेवालान मंदिर सोसाइटी ने बांटे भोजन के पैकेट

नई दिल्ली। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की घोषणा होते ही राजधानी में फंसे हजारों लोगों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में अपने सामाजिक एवं राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति तत्पर झंडेवाला देवी

मंदिर ने अपने सहयोगियों और सेवादारों के साथ मिलकर 25 मार्च से 10 हजार भोजन के पैकेट तैयार कर आरएसएस के अनुशांगिक संगठन सेवा भारती के माध्यम से वितरण प्रारंभ किया जो बाद में बढ़कर 40 हजार पैकेट प्रतिदिन हो गया। औसतन 35 हजार पैकेट प्रतिदिन के हिसाब से अब तक 17 लाख 25 हजार भोजन पैकेट का वितरण किया जा चुका है। भोजन वितरण के इस कार्य में दिल्ली पुलिस का भी सक्रिय सहयोग रहा है। इतने विशाल कार्य के लिए मंदिर के लगभग 250 सेवादार और कर्मचारी दिन-रात अथक परिश्रम कर जरूरतमंद लोगों को समय पर भोजन पहुंचाने का कार्य निरंतर कर रहे हैं।

गाजियाबाद के एंजेल मॉल में रुके प्रवासी श्रमिक।

प्रवासी मजदूरों से भरे बैंक्वेट हॉल और मॉल

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों का गाजियाबाद आना रुक नहीं रहा है। लगातार दूसरे राज्यों से मजदूर यहां पहुंच रहे हैं। रविवार को बड़ी संख्या में मजदूर टीएचए के विभिन्न इलाकों में पहुंचे। पुलिस ने इस सभी मजदूरों को इलाके के बैंक्वेट हॉल और मॉल में रुकवाया। इन मजदूरों को यहां से बसों के जरिए गाजियाबाद के रामलीला ग्राउंड पहुंचाया जा रहा है। जहां से ट्रेन और बसों के जरिए उनके घर तक पहुंचाया जाएगा।

लॉकडाउन के बाद से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आदि आसपास के राज्यों से प्रवासी मजदूर यूपी में अपने घर आ रहे हैं। इनका आना लगातार जारी है।

गाजियाबाद से बस और ट्रेन संचालन की जानकारी मिलने पर शनिवार रात से इनकी संख्या बढ़ गई है। यहां लोग पैदल ही दिल्ली से गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। शनिवार रात को यूपी गेट पर काफी संख्या में मजदूर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया। कुछ मजदूर अंदरूनी रास्तों के जरिए गाजियाबाद में प्रवेश कर गए और पैदल ही अपने घर जाने लगे। पुलिस ने जगह-जगह इन मजदूरों को रोका और आसपास बने बैंक्वेट हॉल और मॉल को खुलवाकर उनके रूकने की व्यवस्था की। टीएचए में कौशांबी के ऐंजल मॉल, लिंक रोड स्थित वंदना बैंक्वेट हॉल, जीटी रोड स्थित कृष्णा बैंक्वेट हॉल, रेलवे रोड स्थित सरकारी स्कूल आदि जगहों पर रोका गया।

पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से इन लोगों के लिए खाने और पानी की व्यवस्था की गई। अधिकारियों की माने तो ऐंजल मॉल में 650 से अधिक, वंदना फार्म हाउस में 300 से अधिक मजदूरों को रोका गया है।

महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी

नोएडा। सेक्टर 49 थानाक्षेत्र के सेक्टर 48 में रहने वाली एक 65 वर्षीय महिला ने रविवार दोपहर को कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

एसीपी विमल कुमार सिंह ने बताया कि सुखी ने रविवार दोपहर को अपने घर पर पंखे से कथित रूप से फांसी लगा ली। उसके पति का नाम राम अवतार है और वह नोएडा के सेक्टर 48 में रहती थी। वह पेट की बीमारी से परेशान थी तथा मूल रूप से जनपद बांदा की रहने वाली थी। एसीपी ने बताया कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

महिला की सरेआम हत्या करने वाला नंदोई साथी समेत गिफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

पैसे के लेनदेन व अवैध सबंधों के चलते एक महिला की मॉर्निंग वॉक पर जाते समय गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने महिला के नन्दोई व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। इसमें से एक आरोपी की गिरफ्तारी पर एसएसपी ने नकद ईनाम भी घोषित कर रखा था।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में गोविंदपुरम कैलाश पुरम निवासी विनोद उर्फ पव्वा व बेहटा हाजीपुर निवासी सूरज कुमार है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया है। इस मामले में वारदात के दिन ही एक आरोपी को रईसपुर गांव के

गिरफ्तार आरोपी

जंगल से लोगों की मदद से पुलिस ने दबोच लिया था जबकि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले दो अन्य आरोपी फरार चल रहे थे। कविनगर थाना प्रभारी मोहम्मद असलम ने बताया कि मामले में रिपोर्ट मृतका के पुत्र ने दर्ज कराया था। मुख्य आरोपी शैलेश को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था तथा उसके पास से तमंचा भी बरामद किया था।

कोरोना वॉरियर : सेहत पर भारी मानव सेवा का जुनून

रोजाना ले रहे केवल दो घंटे की नींद, छह किलो घटा वजन-पत्नि, बच्चों से रहते हैं दूर

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

विश्वस्तरीय महामारी कोविड-19 से

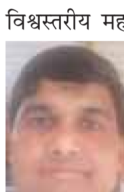
संजय यादव

निपटने के लिए यूं तो देश में बहुत से लोग अपनी ड्यूटी का फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद में एम्बुलेंस प्रभारी संजय यादव भी ऐसे कोरोना वॉरियर हैं जो अपने फर्ज व मानव सेवा के जूनून के आगे अपने आराम व चेन की नींद को भी भूल गए हैं।

संजय पिछले 56 दिनों से रोजाना दो से तीन घंटे की ही नींद पा रहे हैं जिसके चलते उनका वजन भी छह किलो कम हो गया है, लेकिन इसकी प्रवाह किए बिना वे अपने ड्यूटी को लगातार अंजाम दे रहे हैं। संजय यादव जिला छह रोग अस्पताल में सीनियर लैब सुपरवाइजर हैं, लेकिन कोरोना के चलते उनकी ड्यूटी पिछले 23 मार्च को इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (आईडीएसपी) में एम्बुलेंस प्रभारी के रूप में लगाई गई थी जो अभी भी अनवरत जारी है ।

संजय का कार्य पॉजिटिव केस आने पर संबंधित व्यक्ति को कोविड अस्पताल में पहुंचाना और उसके संपर्क में आने वाले परिजनों व अन्य लोगों को एकांतवास (कोरोंटाइन) सेंटर में पहुंचाने की जिम्मेदारी है। यदि कोई सूचना आती है तो संजय ही एम्बुलेंस व स्टॉफ को मौके पर भेजते हैं और कई बार विरोध या विवाद भी हो जाता है तो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर सामंजस्य बैठते हैं।

संजय ने बताया कि उन्हें केवल रात में दो से तीन घंटे ही सोने का समय मिल पाता है उसमें भी कई बार बड़े अधिकारियों का फोन आ जाता है तो उस ड्यूटी को अंजाम देना पड़ता है।

कम हुआ छह किलो वजन

संजय पिछले 56 दिनों से केवल दो से तीन घंटे की नींद ले पा रहे हैं, जिसके चलते उनके शरीर पर विपरीत प्रभाव असर पड़ना स्वाभाविक है। यहीं कारण है कि उनका वजन 72 किलो से घटकर 66 किलो रह गया है लेकिन मानव सेवा के प्रति उनका जूनून कम नहीं हुआ है । उनका कहना है कि उनके पिताजी कहते हैं कि जिस किसी शख्स को जीवन में मानव सेवा का मौका मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है । पिता जी की यहीं बात उनके जज्बे व होंसले को बढ़ाये हुए है।

संजय के पत्नी के अलावा एक बेटी व एक बेटा हैं, लेकिन वे पिछले 56दिनों से केवल बच्चों के कमरे में नहीं जाते हैं और पत्नी व बच्चों से दूर से ही हाल चल लेते हैं । घर कब आना है और कब जाना है इसकी तो उन्हें भी जानकारी नहीं रहती। अपनी सेहत का ख्याल संजय भले ही ना रख पाते हो, लेकिन अपने सहयोगी एम्बुलेंस चालकों का ख्याल करना वह नहीं भूलते।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक चन्दन मित्रा द्वारा नं. 6, गुलाब भवन के पीछे, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक: चन्दन मित्रा, स्थानीय सम्पादक: उषा श्रीवास्तव। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तो और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879800-4879900।

नूंह पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग में एक बदमाश घायल

एक देशी कट्टा व एक कारतूस बरामद, दो बदमाश दबोचे

पायनियर समाचार सेवा। सोहना

नूंह के गांव घासेड़ा बाइक सवार दो बदमाशों ने पुलिस पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए एक बदमाश के पैर में गोली मारते हुए काबू किया और दूसरे को भागते समय दबोच लिया।

सीआईए 2 नूंह पुलिस ने शनिवार रात गांव घासेड़ा के पास बाइक सवार इनामी दो बदमाशों को घेर लिया। बाइक पर पीछे बैठा बदमाश ने पुलिस के चंगुल से भागने की नीयत से फायरिंग कर दी। गोली सरकारी गाड़ी में कंडेक्टर साइड खिड़की पर जाकर लगी। बदमाशों द्वारा की गई गोलीबारी का जवाब भी पुलिस ने उन्हीं की भाषा में दिया। पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में शौकत नामक बदमाश के पैर पर लगी। जिससे वह जख्मी हो गया और जमीन पर गिर गया। दूसरे बदमाश ने बाइक से भागने का प्रयास किया तो उसे काबू कर लिया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान शौकत व राहुल निवासी शिकारपुर के रूप में हुई है।

पुलिस द्वारा पकड़ा गया इनामी बदमाश।

नूंह सीआईए 2 विपिन कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने गुप्तचर की सूचना के आधार पर इनामी बदमाश शौकत शिकारपुर व उसका साथी बदमाश राहुल निवासी शिकारपुर थाना तावडू जिला नूंह, मोटरसाइकिल मार्का हीरो स्पलेंडर प्लस बिना नम्बरी पर सवार होकर गांव घासेडा की कच्ची नहर पटडी से होते हुये नूंह पलवल रोड पर जाने की सूचना दी। बदमाश शौकत पर हरियाणा पुलिस द्वारा इनाम घोषित है व बदमाश शौकत के कब्जा से एक देशी कट्टा बरामद किया और मौके से कारतूस के दो खोल बरामद किये व दूसरे बदमाश को काबू करने पर बदमाश का नाम राहुल निवासी शिकारपुर थाना सदर तावडू मालूम हुआ। जिसके कब्जे से एक देशी कट्टा व एक कारतूस बरामद हुआ। बदमाश शौकत को पैर में लगी गोली से घायल होने पर इलाज के लिए मांडीखेड़ा अस्पताल में दाखिल कराया गया। इनामी बदमाश शौकत को इलाज उपरांत शामिल तफ्तीश कर गहनता से पूछताछ की जाएगी व बदमाश राहुल को मुकदमा में नियमानुसार गिरफ्तार करके गहनता से पूछताछ की जा रही है। दोनों बदमाश जिला नूंह के अन्य मुकदमों में भी वांछित हैं और बदमाश शौकत पर जिला नूंह के मुकदमों के अतिरिक्त दिल्ली, फरीदाबाद, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड व अन्य राज्यों में भी मुकदमे दर्ज है।

घायल बदमाश को अस्पताल में दाखिल

निरीक्षक विपिन कुमार प्रभारी सीआईए : 2 नूंह द्वारा इनामी बदमाश शौकत को अवैध हथियार सहित काबू कर अन्य साथी बदमाश राहुल को अवैध हथियार के साथ किया गिरफ्तार करने का दावा किया है। विपिन कुमार ने बताया कि घायल शौकत को नूंह के मांडीखेड़ा के अस्पताल में दाखिल कराया गया है।

एयरपोर्ट कर्मचारी को ससुरालियों ने खिलाया जहर, मौत

गुरुग्राम। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात कर्मचारी को ससुरालियों द्वारा देकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसके साथ पहले भी मारपीट कि गई थी। परिजनों की ओर से पुलिस को उपलब्ध करवाए गए ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस ने तीन सालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया।

मृतक के चाचा खजान सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि झज्जर के लोवा कलां गांव निवासी सोमबीर (42) दिल्ली एयरपोर्ट में नौकरी करता था। 16 वर्ष पूर्व झाड़सा निवासी मीना से इनकी शादी हुई थी। इनके 14 वर्ष व 8 वर्ष के दो बच्चे हैं। करीब दो माह पूर्व पति-पत्नी में झगड़े के बीच वह अपनी पत्नी को ससुराल छोड़ आया था। 17 अप्रैल को उसे पत्नी को लेने बुलाया तो उसके सालों समेत अन्य लोगों ने बुरी तरह मारपीट की जिसमे वह जख्मी हो गया। इसके बाद अस्पताल में उसका उपचार चला। आरोप है कि 15 मई को उसके सालों ने दोबारा उसे बुलाया तो वह चला गया। ससुराल आकर उसने अपनी भांजी मंजू को फोन कर कहा कि ये लोग मुझे जहर देकर मारना चाहते हैं।

केएमपी पर जा रहे प्रवासियों को खिलाया खाना, पहनाई चप्पलें

गुरुग्राम के खंड फर्रुखनगर के पास केएमपी पर प्रवासियों को खाना खिलाते व चप्पलें पहनाते समाजसेवी।

नवकल्प फाउंडेशन की ओर से उपलब्ध कराई गई चप्पलें

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

लॉकडाउन में रोजगार बंद होने के साथ-साथ खाने-पीने के साधन बंद होने के बाद परेशान होकर अपने प्रदेशों को पलायन कर रहे लोगों को समाजसेवियों द्वारा भोजन आदि देने की सेवा की जा रही है। इसी कड़ी में रविवार को कुछ समाजसेवियों ने एकत्रित होकर केएमपी एक्सप्रेस-वे पर फर्रुखनगर से लेकर पचगांव तक, जयपुर हाइवे पर पचगांव से लेकर राजीव चौक तक प्रवासी राहगीरों को भोजन कराया।

राजेंद्र पार्क से समाजसेवी विजय कुमार करनाणी, मनोज कुमार सोनी, सुभाष शर्मा, हरिओम, संजय कुमार, सुरेंद्र सिंह फलसवाल ने एकत्रित होकर फर्रुखनगर से केएमपी पर पैदल जा रहे प्रवासियों को भोजन कराने की शुरुआत की। इस दौरान जिन प्रवासियों की चप्पलें टूटी हुई थी, उन्हें सम्मान के साथ चप्पलें भी पहनाई गई। इस मौके पर फर्रुखनगर पुलिस थाना से पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। वे प्रवासियों को आगे जाने से रोक रहे थे।

एक युवक की दयनीय स्थिति ने किया भावुक

प्रवासियों के झुंड से आगे चलकर देखा तो एक युवक जा रहा था। वह बुरी तरह से हांफ रहा था। उसके होश फाख्ता थे। उसे देखकर सभी भावुक भी हो गए। समाजसेवियों की टीम उसके पास जाकर ठहरी तो वह डर भी गया। उसे रोककर पहले पानी पिलाया और फिर खाना परोसा। जिस तरह से उस युवक ने खाना खाया, उससे पता लगा रहा था कि वह काफी समय से भूखा है। वह किसी की सुन नहीं रहा था, बल्कि उसका पूरा ध्यान खाने में थे। और खाना लेने की वह न तो ना कर रहा था और न ही हां। मतलब उसे दोबारा दिया तो उसने खा लिया। ऐसे प्रवासियों को देखकर लगा कि इन लोगों ने नारकीय जीवन देख लिया है। जिनके खून-पसीने से शहर में जमीन से लेकर गगन तक इमारतें खड़ी हैं, आज वे भूखे-प्यासे अपनों से मिलने के लिए चले जा रहे हैं। उसकी चप्पलें भी घिसी हुई थी, जिससे एक जोड़ी चप्पलें भी पहनाई, ताकि वह आराम से अपना रास्ता तय कर सके। टीम ने इसके बाद पचगांव केएमपी से उतरकर मानेसर का रुख किया।

शिशु के नामकरण पर ली स्वदेशी अपनाओ की शपथ

गुरुग्राम में हवन करवाकर स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाते पंडित अमरचंद भारद्वाज।

गुरुग्राम। श्रीमाता शीतला देवी श्राइन बोर्ड के पूर्व सदस्य एवं स्वदेशी जागरण मंच के गुरुग्राम महानगर मीडिया प्रभारी पंडित अमरचंद भारद्वाज ने देश हित में अनोखी पहल करते हुए शिशु के नामकरण के अवसर पर स्वदेशी अपनाओ अभियान की शपथ दिलाई।

शिशु के माता-पिता, परिजनों व शुभचिंतकों ने भी इस धारणा को अपनाने की शपथ ली। कोरोना से देश को उबारने के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की गई। कोरोना की रोकथाम के लिए देशभर में किए गए लॉक डाउन को लेकर नामकरण समारोह में मित्रों व रिश्तेदारों को आमंत्रित नहीं किया जा सका था। परिवार के नागरिक भी मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। पंडित अमरचंद ने भी मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर आदि का प्रयोग कर सेक्टर-9 निवासी दिनेश सैनी व साक्षी सैनी के नवजात पुत्र का नामकरण तनिश के रूप में करते हुए, शिशु के दीर्घायु एवं गृह शुद्धिकरण के लिए पूजन व हवन किया। तनीश के परिजन जयभगवान सैनी, लीलू सैनी, दीपक सैनी, मोनू सैनी, दक्ष सैनी और माता सावित्री देवी आदि ने आशीर्वाद प्रदान कर स्वदेशी अपनाने की शपथ ली।

डीएलएफ में 54 यूनिट रक्त एकत्रित

नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त अमरदीप जैन व पार्षद आरएस राठी ने किया शुभारंभ

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में थैलीसीमिया के मरीजों के रविवार को नवकल्प फाउंडेशन की ओर से 8 दिन के भीतर दूसरा रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें लायंस ब्लड बैंक व गुड़गांव सिटीजन काउंसिल का भी सहयोग रहा। शिविर का शुभारंभ नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त अमरदीप जैन, पार्षद आरएस राठी ने किया। इस शिविर में 54 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया।

शिविर के शुभारंभ पर अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त अमरदीप जैन ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं। वह भी उस समय में जब दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैली हो। सभी को ऐसे समाजसेवा के कार्यों में आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजसेवा का कोई रूप नहीं होता। वह तन से भी होती है, मन से भी होती है और धन से भी होती है। जिस व्यक्ति में इन तीनों में से जो सामर्थ है, वह उससे कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि यह दौर एक नए जीवन की शुरुआत करने का है। हमें कोरोना काल से निकलने के बाद नहीं, बल्कि अभी से अपने जीवन में बहुत से बदलाव लाने होंगे। घर-परिवार से लेकर प्रोफेशनल लाइफ बहुत प्रभावित हुई है। फिर भी लॉकडाउन में जनता ने पूर्ण सहयोग दिया है। पार्षद आरएस राठी ने कहा कि कोरोना बीमारी के समय खून की बहुत कमी हो चुकी है। इस कमी को पूरा किसी अन्य से नहीं, बल्कि व्यक्तियों के खून से ही पूरा किया जा सकता है। नवकल्प फाउंडेशन के सचिव डा. सुनील आर्य ने बताया कि आज संस्था का 8 दिन के भीतर दूसरा यह शिविर था। इसमें 50 यूनिट रक्त का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पार कर दिया गया।

डीएलएफ फेज-1 में आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान करते रक्तदानी।

लॉकडाउन में फूलों से किसानों को लाखों का घाटा

गुरुग्राम के खंड फर्रुखनगर में फूलों की खेती के बीच खड़े किसान।

फर्रुखनगर। जहां एक ओर सरकार परम्परागत खेती को छोड़ बागवानी और फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को प्रेरित कर रही है, वहीं लॉक डाउन के चलते फूलों की खेती करने वाले किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं।

रविवार को क्षेत्र के दर्जनों किसानों ने छत्तर की ढ़ाणी में बैठक करके सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सोमवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपेंगे। किसान नेता राव मानसिंह, रामबीर यादव, मास्टर जेपी यादव, मुकेश सैनी, रोशन लाल, शिवचरण सिमार, दीपक यादव, रामपत सैनी, मूला सैनी, श्याम सैनी, जगदीश आदि ने बताया कि सरकार की योजनाओं से प्रेरित होकर क्षेत्र के किसानों ने करीब 200 एकड़ भूमि पर मोतिया, चमेली, चम्पा, गुलदावरी, गुलाब, गेंदा आदि के फूलों की खेती की तरफ रुख किया।

सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन

गुरुग्राम में कोरोना का दोहरा शतक, रविवार को आए 11 केस

गुरुग्राम। कोरोना के पॉजिटिव मामलों में गुरुग्राम में दोहरा शतक बन गया है। रविवार को आए 11 केसों के साथ अब यहां कुल पॉजिटिव केसों की संख्या 204 हो गई है।

रविवार को आए 11 केसों में एक केस शक्ति पार्क से, एक केस खांडसा रोड से, 1 केस सरहोल से, 1 केस सेक्टर-9ए से, 2 केस रवि नगर से, 1 केस सेक्टर-10ए से, 1 केस सुशांत लोक फेस-1 से, 1 केस सेक्टर-55 से, 1 केस सेक्टर-48 से और 1 केस मुल्लाहेड़ा से आया है। इस तरह से पहले के 193 मिलाकर यहां पर पॉजिटिव केसों की संख्या 204 हो गई है। इनमें से 104 लोगों को पॉजिटिव से नेगेटिव यानी ठीक होने पर डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। अब कुल पॉजिटिव यहां पर 100 रह गए हैं। जो कि उपचाराधीन हैं। रविवार को 170 लोगों के सेंपल भी लिए गए। जिनमें 153 सरकारी लैब से और 17 प्राइवेट लैब से लिए गए हैं।

नियमानुसार सरसों की पूरी खरीद न होने से किसान दुखी

बीस दिनों से खरीद की बाट जोह रहे अन्नदाता, मंडी अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप

पायनियर समाचार सेवा। नूंह

प्रदेश के पिछड़े जिलों में सुमार नूंह जिले में सरसों की खरीद न होने से किसान परेशान हैं। किसानों की मानें तो सरकार के नियमानुसार पहली खरीद में प्रत्येक किसान से 40 क्विंटल सरसों की खरीद होनी थी। लेकिन कुछ किसानों की सरसों में नमी के कारण पहली खरीद में उनकी 40 क्विंटल सरसों नहीं खरीदी गई। आरोप है कि नमी वाली सरसों को किसानों को सुखाने के लिए वापस घर भेज दिया गया। जिसे बीस दिन बाद भी नहीं खरीदा जा रहा है, जिसके कारण इस समस्या से जिलेभर में अधिकतर किसान परेशान हैं।

सरसों को दिखाते किसान।

पाठखोरी गांव के सहाबुद्दीन, सरफुद्दीन, लियाकत, आस मोहम्मद, शमसुद्दीन, इस्सर, उमर व समाजसेवी साजिद हुसैन ने बताया कि उनके गांव से जब किसान सरसों को बेचने के लिए मंडी लेकर गए तो सूखी सरसों को तो खरीद लिया गया और नमी वाली सरसों को मंडी के अधिकारियों ने घर पर सुखाकर लाने की बात कहकर लौटा दिया। किसानों का कहना है कि उस समय तो उनसे नमी वाली सरसों को सुखाकर लाने के लिए कहा गया था, लेकिन अब सुखाने के बाद उनसे सरसों को खरीदा ही नहीं जा रहा है। किसानों की मानें तो आज नहीं कल खरीदी जाएगी, उन्हें इसी इंतजार में 20 दिन से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उनकी सरसों नहीं खरीदी जा रही है।

हरीश बेकरी के खिलाफ लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन पर केस

गुरुग्राम। लॉकडाउन में तय नियमों का उल्लंघन करने पर शहर के नामचीन रेस्तरां हरीश बेकरी के मालिक देवेंद्र नुहानी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। न्यू कॉलोनी थाना प्रभारी निरीक्षक वेदपाल ने बताया कि मामले की जांच कि जा रही है। इस संबंध में बेकरी प्रबंधक से जवाब तलब किया जाएगा। लॉकडाउन ड्यूटी के दौरान शनिवार शाम को न्यू कॉलोनी थाना पुलिस कि पीसीआर गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान सिपाही विक्रम को शाम पांच बजे बाद सेक्टर-4/7 चौक स्थित रेस्तरां हरीश बेकरी खुला मिला। पुलिस टीम ने रेस्तरां में जाकर कर्मचारियों को रेस्तरां बंद करने की चेतावनी दी, लेकिन मालिक देवेंद्र नुहानी ने नहीं मानी।

ट्रेन से बिहार और बसों से बुलंदशहर भेजे श्रमिक

गुरुग्राम से रवाना की गई बसें व ट्रेन

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

प्रवासी श्रमिकों को अपने गृह राज्य भेजे जाने का काम रविवार को भी जारी रहा। यहां ट्रेन व बसों से श्रमिकों को बिहार, यूपी के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। साथ ही उनसे उम्मीद जताई गई कि लॉकडाउन के बाद भारत निर्माण को वे फिर से यहां पर आकर विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से रविवार को मधुबनी (बिहार) के लिये श्रमिक स्पेशल ट्रेन शाम चार बजे रवाना हुई। इसमें 1600 प्रवासी नागरिक हरियाणा सरकार की तरफ से मुफ्त टिकट, भोजन, पानी आदि लेकर सकुशल अपने घरों को गए हैं। सभी ने तालियां बजाकर तथा हाथ हिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं 900 प्रवासी नागरिक हरियाणा राज्य परिवहन की 30 बसों में बुलंदशहर के लिए रवाना किया गया। ये बसें सेक्टर 21 स्थित कम्युनिटी सेंटर से रवाना हुई। हरियाणा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रवासी नागरिकों को अपनी राज्य परिवहन की बसों में निशुल्क बुलंदशहर भेजा जा रहा है, जहां से इन प्रवासी नागरिकों को इनके घरों तक वहां की प्रदेश सरकार द्वारा भेजा जा रहा है। सोहना की एसडीएम एवं नोडल अधिकारी डॉ. चिनार चहल ने सभी प्रवासी नागरिकों के सकुशल घर पहुंचने की कामना की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण से आज कोरोना के तहत चल रहे लॉकडाउन में प्रवासी नागरिकों को उनके गृह जिलों में परिजनों के पास भेजने की व्यवस्था नि:शुल्क की गई है। एसडीएम चिनार चहल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवासी नागरिकों की रवानगी से पूर्व उनके स्वास्थ्य की जांच की गई और उनकी थर्मल स्कैनिंग की गई। जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं थे, उन्हें ही इन बसों में भेजा गया।

गुरुग्राम से बिहार व यूपी के लिए ट्रेन, बस में रवाना होते श्रमिक।

इसके अलावा इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बसों में मास्क पहनाकर, पानी की बोतलें, फूड पैकेट व बिस्कुट पैकेट आदि देकर रवाना किया गया है। इसके साथ ही, प्रवासी नागरिकों को कोविड-19 संक्रमण संबंधी बचाव उपायों के बारे में भी जागरूक किया गया। प्रवासी नागरिकों का कहना था गुरुग्राम जिला ने उन्हें बहुत काम व सम्मान दिया। हालात सुधरने का इंतजार करेंगे और यहां लौट कर जरूर आएंगे। उन्होंने यात्रा से पूर्व मौके पर उपस्थित जिला प्रशासन के अधिकारियों का भी आभार व्यक्त किया।

सोहना आढ़तियों को नहीं मिल रहें हैं सब्जियों के सही दाम

प्रवासियों के पलायन करने मंडी में मजदूरी की कमी

नरेश कुमार। सोहना

कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों का अपने पैतृक गांव लौट जाने से सब्जी मंडी में बैठे आढ़तियों को जोर का झटका धीरे से लग रहा है। पिछले एक सप्ताह में सब्जियों के दाम गिरते जा रहे हैं। जिससे आढ़तियों को सब्जी बेचने में घाटा हो रहा है।

जैसे ही लॉकडाउन दो समाप्ती के बाद 3 शुरू हुआ था। वैसे ही क्षेत्र में रहने वाले बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान आदि राज्यों के प्रवासी मजदूरों ने अपने पैतृक गांव को पलायन शुरू कर दिया था। जो आज तक भी प्रवासी मजदूर अपने गांव सरकार द्वारा जारी की गई बस रेल की सुविधाओं के अलावा पैदल और साइकिलों पर सवार होकर लौट रहे है। प्रवासी मजदूरों के लौट जाने का असर स्थानीय सब्जी मंडी में साफ नजर आ रहा है। मंडी में सब्जी बिक्री कम हो गई है। सब्जी की बिक्री कम होने साथ उनके दाम भी गिर रहे हैं। सब्जियों के दाम कम होने से आढ़तियों को घाटा हो रहा है।

सोहना के देवीलाल खेल स्टेडियम में अस्थाई रूप से लग रही सब्जी मंडी।

40 से 45 फीसदी बिक्री

सब्जी एसोसिएशन के प्रधान उमेश कुमार ने बताया कि मंडी में सब्जी की बिक्री एक दम से नीचे आ गई है। एक सप्ताह पहले एक आढ़ति यदि एक सौ किलो सब्जी एक दिन में बेचता था। आज वह 40 से 45 किलो ही सब्जी बेच रहा है। जिसका कारण प्रवासी मजदूर का पलायन होना। क्योकि प्रवासी मजदूर जो बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का स्थानीय मंडी में पल्लेदारी कर रहा था। वह तीन दिन के अंदर अपने घर चला गया। किसान स्वयं ही सब्जियों को उठा-उठाकर आढ़त पर रख रहा है और ग्राहक को खड़े होकर बेच रहा है। उन्होंने बताया कि आढ़तियों को मंडी से स्टेडियम में सब्जियों को बिक्री के लिए लेकर जाना और वापस लाने पर 500 रुपये का अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी को अपने स्थान पर ही लगाया जाए।

सब्जियों की कीमतों में गिरावट

आढ़ती सत्ते सैनी ने बताया कि गुरुग्राम, बादशाहपुर, पलवल, नूंह, तावडू की सब्जी मंडियों में काम शुरू होने से यहा पर खपत कम हो गई है। जिसके कारण प्याज से लेकर खीरा, घीया, पालक, तोरई, करेला, खरबूजा, टमाटर, सीताफल आदि के दाम 50 फीसदी कम हो गए है। मार्केट कमेटी के सैल इंस्पेक्टर ओमबीर सिंह ने बताया कि पिछले एक सप्ताह में बिक्री कम हुई है। जो अब 45 से 50 फीसदी रह गई है।

कौन सी सब्जी क्या है दाम

सब्जी का नाम	एक सप्ताह पहले	वर्तमान समय में
करेला	25	12
खीरा	12	05
तोरई	18	05
प्याज	14	10
टमाटर	15	04
सीताफल	12	05
पालक	10	08
शिमला मिर्च	25	12
ककड़ी	12	04

(यह कीमत प्रति किलोग्राम की दर से है।)

स्पिनी ने तैयार किया कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी सिस्टम

ग्राहकों को मिलेगा पुरानी कार खरीदने का सुकूनभरा अनुभव

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

कोरोना महामारी के कारण देश में लगभग सभी सार्वजनिक परिवहन बंद हैं। ऐसे में अपनी कार ही कहीं आने-जाने का सबसे सुरक्षित माध्यम है।

हालांकि अर्थव्यवस्था जिस तरह ठहरी हुई है और लोगों के पास जिस तरह नकदी की किल्लत है, उससे नई कारों के बजाय लोगों का रुख पुरानी कारों की ओर कर दिया है। इन हालात को देखते हुए पुरानी कारें खरीदने के रिटेल प्लेटफॉर्म स्पिनी ने वक्त से आगे की सोच दिखाते हुए ग्राहकों को कार खरीदने का एक कॉन्टेक्टलेस अनुभव देने की रास्ता अपनाया है। स्पिनी ने कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी सिस्टम तैयार किया है और यही वजह है कि लॉकडाउन के दौरान भी दो शहरों में छह दिन में स्पिनी को 50 से ज्यादा कारों के ऑर्डर मिले हैं।

स्पिनी ने कार बेचने की पूरी प्रक्रिया के दौरान सभी टच प्वॉइंट पर ग्राहकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा है। साथ ही डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के अनुरूप ग्राहकों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए होम टेस्ट ड्राइव की शुरुआत की है। ग्राहक स्पिनी की वेबसाइट या एप के जरिये 3 आसान स्टेप की मदद से अपनी पसंद की कार अपने घर ला सकते हैं। पहले स्टेप के तहत ग्राहकों को पूरी तरह जांची-परखी पुरानी कारों (2012 या उसके बाद के मॉडल) में से अपनी पसंद की कार चुननी होती है। ग्राहक इस संबंध में कोई फैसला लेने से पहले वर्चुअल टूर भी कर सकते हैं। इसके बाद ग्राहक आसानी से पूरी तरह से सैनिटाइज की हुई कार को होम टेस्ट ड्राइव के लिए घर मंगा सकते हैं। इसमें ग्राहकों के लिए एक सेफ्टी किट भी रहती है। आखिरी स्टेप के तौर पर ग्राहकों को जरूरी दस्तावेज और भुगतान से जुड़ी जानकारियां देनी होती हैं। एक बार भुगतान होते ही कार आपके दरवाजे पर पहुंच जाती है।

स्पिनी के सह संस्थापक और सीईओ नीरज सिंह ने कहा कि अब सब कोरोना वायरस के साथ संतुलन बनाकर जीने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सबकी प्राथमिकता है। इस नई दुनिया में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जीवन का सामान्य हिस्सा हो गए हैं। ऐसे में हमारी पहल सुरक्षित और कॉन्टेक्टलेस लेनदेन के नए मानक स्थापित कर रहे हैं। यही कारण है कि इस समय होम टेस्ट ड्राइव के बारे में ज्यादा लोग जानकारी ले रहे हैं।

फटाफट खबरें

ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन

फरीदाबाद। गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म महाविद्यालय के रसायन विभाग द्वारा ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ जी.के.सपरा ने की। कार्यक्रम की प्रभारी डॉ अंजु ने बताया कि आज की कोविड–19 की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य नई तकनीक द्वारा आने वाले समय में छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करना तथा यह भी ज्ञान प्राप्त कराना कि रसायन शास्त्र कोविड–19 से लड़ने के लिए कैसे सहायक सिद्ध हो सकता है। इस प्रतियोगिता में देश विदेश से कुल 600 प्रतिभागियों ने अपनी भागीदारी दिखाई जिसमें भारत से हरियाणा, राजस्थान,मध्य प्रदेश,उत्तर प्रदेश,महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू–कश्मीर ,उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली एवं तमिलनाडु आदि कई राज्यों तथा भारत के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, कीनिया,संयुक्त राष्ट्र, सिंगापुर, ब्रिटिश कोलंबिया,कनाडा और यूनाइटेड किंगडम आदि राष्ट्रों के छात्र छात्राएं शामिल थे। यह उत्साह देखते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य ने आगे भी ऐसी प्रतियोगिता करवाने के लिए रसायन विभाग को प्रेरित किया।डॉ अंजु ने बताया कि जो विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए उनको जल्दी ही मौका मिलेगा क्योंकि तकनीकी कारणवश एक साथ केवल 500 विद्यार्थियों को ही मौका दिया जा सकता था। इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन में रसायन विभाग के प्राध्यापक डॉ रुचि शर्मा, डॉ रमन सैनी , डॉक्टर साबिर हुसैन एवं डॉ वनिता सपरा ने मुख्य भूमिका निभाई। प्रतियोगिता में 50 प्रतिशत बच्चों ने 80 प्रतिशत से ऊपर अंक प्राप्त किए ,10 प्रतिशत बच्चों ने 100 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। सभी विद्यार्थियों को रसायन विभाग की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा । अंत में

मजदूरों की बदहाली के खिलाफ प्रदर्शन

फरीदाबाद। इंकलाबी मजदूर केन्द्र व परिवर्तनकारी छात्र संगठन ने केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए लम्बे लॉकडाउन के कारण फैली अव्यवस्था, भूख और सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मजदूरों की मौतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोरोना महामारी के कारण बिना विचार तुगलकी फरमान के द्वारा अचानक लॉकडाउन कर दिया गया। 22 मार्च से चल रहे लॉकडाउन का 57वां दिन है, लोग खासकर प्रवासी मजदूरों के घरों में खाने को अन्न नहीं है। मकान मालिक जबरन किराया ले रहे हैं। रेल व बस बंद होने के कारण प्रवासी मजदूर अपने परिवार के साथ पैदल, साईकिल, ठेला वगैरह से तथा बहुत से मजदूर ट्रकों से मजबूरन महंगा किराया देकर अपने गांवों की ओर जा रहे हैं। इस भागदौड़ में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में बहुत से लोगों की जान चली गई है। सरकार का पक्षपात दिखता है कि विदेशों में फंसे अमीरों को हवाई जहाजों से ला रही है। वहीं देश के अंदर रेल बस नहीं चलने से लोग बेमौत मरने को विवश है। इंकलाबी मजदूर केन्द्र व परिवर्तनकारी छात्र संगठन के प्रतिनिधियों ने मांग की है कि सरकार को साधनहीन सभी मजदूरों व गरीबों को राशन, रूम किराया तथा दूसरे जरूरी सामान उपलब्ध कराएं।

मंच ने अभिभावकों से की ऑनलाइन बातचीत

फरीदाबाद। हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने जागो अभिभावक जागो अभियान के तहत प्राइवेट स्कूलों के अभिभावकों से वीडियो कांफ्रेंस के द्वारा स्कूलों की मनमानी के बारे में जानने का सिलसिला शुरू किया है। इसी के तहत रविवार को ग्रैंड कोलंबस व मॉडर्न डीपीएस के अभिभावकों से बातचीत की गई। अभिभावक जितिन मंगला व राजेश अग्रवाल ने बताया कि शिक्षा विभाग हरियाणा के बिना बढ़ाई गई ट्यूशन फीस लेने के आदेश के विपरीत स्कूल प्रबंधक बढ़ाई गई ट्यूशन फीस व अन्य फंडों में फीस मांग रहे हैं। विरोध करने पर बच्चों को परेशान करने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन दोनों स्कूल के अभिभावकों की ओर से अप्रैल महीने में ही चेयरमैन एफएफआरसी व जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद को लिखित शिकायत दर्ज करा दी गई थी लेकिन शिकायत किए हुए 1 महीना होने को आया है इन अधिकारियों ने दोषी स्कूल के खिलाफ कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की है। मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा, प्रदेश संरक्षक सुभाष लांबा, जिला अध्यक्ष एडवोकेट शिव कुमार जोशी, जिला सचिव डॉ. मनोज शर्मा ने वीडियो कांफ्रेंस में भाग लेते हुए अभिभावकों को आश्वस्त किया कि वे जागरूक व एकजुट होकर स्कूलों की मनमानी का विरोध जारी रखें। मंच प्रशासनिक व लीगल स्तर पर दोषी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। मंच ने अधिकारियों के नकारात्मक रवैए और स्कूलों की मनमानी की शिकायत सबूत के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के पास रजिस्टर्ड कराई है। मंच जागो अभिभावक जागो अभियान जारी रखते हुए आगे डीपीएस 19 व 81, मानव रचना, सेंट एंथोनी, जीवा, डीएवी 14 व 49, आदि स्कूलों के अभिभावकों से संपर्क करके इन स्कूलों की मनमानी की जानकारी प्राप्त करेगा।

कोरोना का कहर : छठी मौत, तीन पॉजिटिव के साथ संख्या 147

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

जिले में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव 45 वर्षीय जिस व्यक्ति की मौत रविवार को हुई है, वह मधुमेह रोगी बताया गया है। डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. रामभगत ने बताया कि मृतक की मौत मधुमेह की वजह से हालत खराब होने से हुई है। जिले में मृतकों की संख्या का आंकड़ा आधा दर्जन पर पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ तीन लोग पॉजिटिव पाये गए। जिले में अब तक कुल 147 पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं रविवार को दो लोग डिस्चार्ज हुए है। इसमें खेड़ीकलां स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम और ग्रीनफील्ड में होम आइसोलेट 14 वर्षीय बच्चे ने कोरोना को मात दी है।

मधुमेह से मौत का दावा

नहरपार इलाके के खेड़ी रोड़ स्थित कर्नल विहार के रहने वाले जिस 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। वह बुखार व शुगर की समस्या को लेकर 12 मई को एक निजी अस्पताल में भर्ती हुआ था। डॉक्टरों ने उनका कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिसके बाद 13 मई को मरीज को ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। व्यक्ति शुगर से ही वेंटिलेटर पर था। वहां पर इलाज के दौरान शनिवार रात को व्यक्ति की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार कराया है।

ऐसे हुए पॉजिटिव

भारत कॉलोनी निवासी एक 36 वर्षीय व्यक्ति डेयरी में मृतक के साथ काम करता था। वह उसके सम्पर्क में आने से पॉजिटिव हुआ। सेक्टर 14 में रहने वाला एक 32 वर्षीय व्यक्ति

तीन पॉजिटिव

रविवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा तीन लोगों को पॉजिटिव घोषित किया गया है। जिसमें मृतक के संपर्क में आने से एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि की है। वहीं एक बैंक कर्मी व निजी अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी को भी पॉजिटिव घोषित किया गया है।

से गुरुग्राम में रहने वाला मित्र फरीदाबाद आया था। उसके पॉजिटिव आने पर उसका सैम्पल लिया था। रविवार को उसे कोरोना पॉजिटिव घोषित किया गया। इन दोनों को ईएसआइसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं सेक्टर–16 स्थित एक निजी अस्पताल में काम करने वाला स्वास्थ्य कर्मी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर उसे निजी अस्पताल के ही आईसोलेशन में दाखिल किया गया है।

यह है आंकड़ा

डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. रामभगत ने बताया कि जिले में अब तक 7578 यात्रियों को सर्विलांस पर लिया जा चुका है। जिनमें से 1728 लोगों का निगरानी में रखने का 28 दिन का पीरियड पूरा हो चुका है। शेष 5845 लोग अंडर सर्विलांस हैं। कुल सर्विलांस में रखे गए लोगों में से 7431 होम आइसोलेशन पर हैं। अब तक 6974 लोगों के सैंपल लैब में भेजे गए थे। जिनमें से 6205 की नेगेटिव रिपोर्ट मिली है तथा 622 की रिपोर्ट आनी शेष है। अब तक 147 लोगों के सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। जिनमें से 60 लोगों को अस्पताल में दाखिल किया गया है तथा चार पॉजिटिव मरीजों को घर पर आइसोलेट किया गया है। इसी प्रकार ठीक होने के बाद 77 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक छह मरीजों की मौत हो चुकी है।

डबुआ के बाद अब बल्लभगढ़ मंडी से बढ़ा संक्रमण का खतरा

बल्लभगढ़ एम्स का क्लर्क पाया गया पॉजिटिव, भेजा दिल्ली

कविता। फरीदाबाद

डबुआ और सेक्टर–16 की सब्जी मंडी बंद होने से बल्लभगढ़ मंडी में भी बढ़ गई है। जिसे देखते हुए बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉ. मान सिंह ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए, जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग को सूचना ठोस कदम उठाने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ बल्लभगढ़ एम्स अस्पताल का क्लर्क भी पॉजिटिव पाया गया है। लेकिन उसे जिले के पॉजिटिव मरीजों में शामिल नहीं किया गया है। उसे झज्जर एम्स में दाखिल कराया गया है। उसके सम्पर्क में आने वाले सभी लोगों के सैम्पल सोमवार की सुबह एकत्रित किए जाएंगे।

फैल सकता है कोरोना

एसएमओ डॉ. मान सिंह ने बताया कि मंडी में भीड़ बढ़ने से कोरोना फैल सकता है। क्योंकि डबुआ मंडी के ज्यादातर सब्जी विक्रेताओं की भीड़ यहां लग रही है। रात्रि में मंडी

में भीड़ बढ़ने से यहां भी कोरोना के मरीजों की संख्या डबुआ की तरह बढ़ सकती है। इस खतरे का अंदेशा होते देखकर उन्होंने रविवार को जिला उपायुक्त और जिला सिविल सर्जन को इसकी सूचना दी। जिस पर दोनों अधिकारियों ने उन्हें इससे निपटने के लिए विशेष प्रबंध करने का आश्वासन दिया है।

क्लर्क भी पॉजिटिव, 27 क्वारंटाइन

डॉ. मान सिंह ने बताया कि बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल में एम्स की शाखा भी है। यहां तैनात कुम्हारबाड़ा निवासी क्लर्क के पॉजिटिव होने की सूचना उन्हें देर शाम मिली है। जिस पर उसके प्राइमरी कॉटेक्ट के सभी साथियों के सैम्पल लिये जाएंगे। उसके सम्पर्क में आए 27 लोग के सोमवार को सैम्पल लेंगे। क्लर्क थाईराइड की बीमारी से पीड़ित है और उसकी उम्र करीब 40 साल है। उसका कोई ऑपरेशन होना था। जिस पर उसने दिल्ली एम्स से जांच कराई। जहां कोविड–19 का टेस्ट उसे बताया गया, दो बार रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन जब ऑपरेशन का समय आया, तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। ऐसे में उसे दिल्ली एम्स से सीधे झज्जर भेज दिया गया। इसलिए उसकी रिपोर्ट को फरीदाबाद में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन उसका परिवार यहां होने के कारण उनके सैम्पल अब बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल से लिये जाएंगे। वहीं अस्पताल को सेनिटाइज किया गया है। उसके परिवार और सम्पर्क में आए सभी को क्वारंटाइन कर दिया गया है।

प्राइमरी कांटेक्ट के सैम्पल

डॉ. मान सिंह ने बताया कि सिविल अस्पताल में सभी पॉजिटिवों के सम्पर्क में आने वालों को सैम्पल लिये जा रहे है। जिसके तहत रविवार को 56 लोगों के सैम्पल लिये गए। जिसमें सीही गांव के पॉजिटिवों के अलावा बल्लभगढ़ बस अड्डा चौकी के कुछ पुलिस कर्मियों ने भी जांच कराई है।

कोरोना से निपटने को प्रशासन ने बनाई नई रणनीति

विदेशों से यहां आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग की जानी सुनिश्चित की जाए

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

जिलाधीश यशपाल ने कहा कि कोरोना के फैलाव व संक्रमण को रोकने के लिए, सरल व ई–दिशा पोर्टल के माध्यम से मूवमेंट पास प्राप्त करने व विदेशों से यहां आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग व टेस्टिंग की जानी सुनिश्चित की जाए। इसकी सूचना डीएसईओ अमिताभ द्वारा उप सिविल सर्जन डा. रामभगत को उपलब्ध करवाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि 16 मई से 19 मई तक डबुआ सब्जी मंडी व सेक्टर–16 स्थित सब्जी मंडी पूर्ण रूप से बंद की गई हैं, इस दौरान नगर निगम की ओर से इन मंडियों की अच्छी प्रकार से सेनेटाइज करवाया जाए। जिलाधीश ने यह आदेश जिला संकट समन्वय समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पारित किए।

उन्होंने बताया कि कोरोना के अधिकतर मामले शहरी क्षेत्र में सामने आने के कारण जरूरी है कि जिस प्रकार पहले घर–घर जाकर आईएलआई के पैशेंट की पहचान की गई थी, उसी प्रकार एक बार फिर आईएलआई के पैशेंट की पहचान के लिए घर–घर सर्वे किए जाएं ताकि पता लगाया जाए कि एक घर में 60 वर्ष से अधिक आयु के कितने व्यक्ति रह रहे हैं तथा रोग के लक्षणों वाले लोगों की संख्या कितनी है। जिला नगर योजनाकार रेणुका सिंह उप सिविल सर्जन डा. गीता पालिया व सहायक प्रोफेसर ईएसआई डा. पूजा के सहयोग से कंटेनमेंट जोन की नई सूची प्राप्त कर इनमें सर्वे का कार्य करवाएंगी तथा किस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में शामिल किया जाए या बाहर किया जाए, पर विचार–विमर्श करेंगी।

एचएसईबी वर्कर्स ने की टैरिफ पॉलिसी की निंदा

फरीदाबाद । एचएसईबी वर्कर्स यूनियन के प्रदेश महासचिव सुनील खटाना ने देश की वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण की बिजली के टैरिफ पोलिसी घोषणा की कड़े शब्दों में निन्दा की। सुनील खटाना ने कहा कि आज जब पूरा विश्व इस कोरोना जैसी महामारी के आपातकाल से जूझ रहा है और देश का बहादुर बिजली कर्मचारी कोरोना वारियर्स के रूप में 24 घन्टे दिनरात देश को निर्बाध सेवाएं दे रहा है। अभी तक पूरे देश में एक भी ऐसा मामला सामने नही आया जहां देखा गया हो बिजली की आपूर्ति में बाधा से किसी कोरोना पीड़ित की जान गई हो। ऐसे समय मे देश की वित्तमन्त्री का क्वालिटी बिजली के नाम पर निजीकरण करने वाले बयान का हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन पुरजोर विरोध करती है। संकट के इस समय में वित्तमन्त्री का यह बयान देश के लाखों बिजलीकर्मी कोरोना वारियर्स का अपमान है। सही मायने में तो सरकार इस संकट की घड़ी में आम जनमानस, कर्मचारी, किसान और छोटे उद्यमियों की कोई चिन्ता नही है। बल्कि निजीकरण व एफडीआई की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74 फीसदी कर देश के बड़े पूंजीपतियों को इसका सीधा लाभ पहुंचाया है। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़कर टैरिफ पोलिसी के नाम पर जो बिजली का निजीकरण करने जा रही है।

जेसी बोस ने जारी किया संशोधित अकादमिक कैलेंडर

फरीदाबाद। जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद ने मौजूदा शैक्षणिक सत्र के लिए संशोधित अकादमिक कैलेंडर जारी किया है तथा सभी पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षा और शैक्षणिक सत्र 2020–21 शुरू करने के लिए तारीखों की घोषणा की है। इसके साथ–साथ विश्वविद्यालय ने 18 मई से 25 जून, 2020 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा भी की है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी संशोधित अकादमिक कैलेंडर के अनुसार, सभी पाठ्यक्रमों की अंतिम सेमेस्टर परीक्षाएं 1 से 10 जुलाई, 2020 तक आयोजित की जायेंगी। हालांकि, अन्य सेमेस्टर की परीक्षाएं 11 जुलाई, 2020 से आयोजित की जायेंगी। यूजीसी के दिशानिर्देशों की अनुपालन करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में शैक्षणिक कैलेंडर तथा परीक्षा प्रक्रिया में आवश्यक बदलावों को लेकर निर्णय लेने के लिए एक 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था।

कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

बल्लभगढ़ शहर के एसएचओ राजीव कुंडू, चौकी इंचार्ज विनोद गौतम व लगभग 140 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आरएसएस व हरिदेव सेवा ट्रस्ट द्वारा सम्मानित किया, जो दुनिया में फैली कोरोना महामारी से निपटने के लिए, अपनी जान की परवाह किये बगैर अपने कर्तव्य का निष्ठा पूर्वक पालन कर रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वमसेवक के हरियाणा प्रान्त के अधिकारी गंगा शंकर मिश्र ने सम्बोधित करते हुए

कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है।

श्रीहरिदेव सेवा ट्रस्ट के संस्थापक डॉ. अशवनी गौड़ ने सभी योद्धाओं का आभार व्यक्त किया व जाने माने समाज सेवी जो इस कोरोना महामारी में एक महान योद्धा का कार्य कर रहे केके गोयल जो लगभग 25 मार्च से पूरे फरीदाबाद में निराश्रितों को आरएसएस व श्री हरिदेव सेवा ट्रस्ट के सहयोग से भोजन की व्यवस्था व हल्दीराम के उत्पादन निशुल्क वितरित कर रहे हैं।

युवा नेता ने दी होम्योपैथिक दवाइयां

फरीदाबाद। युवा भाजपा नेता अमन गोयल ने पुलिस के जवानों को रोग प्रतिरोधक क्षमता में मदद करने वाली होम्योपैथिक दवाई भेंट की। गोयल ने बताया कि पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल के आह्वान पर पूरे फरीदाबाद में होम्योपैथिक दवाई बांटी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड कोरोना वायरस जैसी महामारी में शारीरिक क्षमता को बढ़ाने में मदद की जा सके। उन्होंने बताया कि हमारे पुलिस के जवान इस महामारी में 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं जोकि सराहनीय कदम है। इसके साथ ही फरीदाबाद की जनता से अपील की है कि जब तक जरूरी काम न हो तब तक घर से बाहर न निकले ओर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का हर संभव सहयोग करें। इस महामारी में हम सब मिलकर एक दूसरे के सहयोग करें। गोयल ने कहा कि पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने जरूरतमंद लोगों के घर तक खाना पहुंचाना या फिर लोगों को सूखा राशन बांटने वाले फरीदाबाद के सभी समाजसेवी और सामाजिक संस्थाओं की इस नेक कार्य के लिए सराहना की और साथ में अपील भी की है कि हर सक्षम व्यक्ति जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आए। अमन गोयल ने बताया कि महामारी के दौरान भी कठिनाई के समय मे जो लोग अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं ये समाज मे अतुलनीय योगदान दे रहे हैं।

रक्तदान शिविर का किया आयोजन

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

मारवाड़ी युवा मंच फरीदाबाद, सेव लाइफ ट्रस्ट, गीतांजलि पब्लिक स्कूल, जिला रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से थैलासीमिया के बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक दीपक मंगला, रेडक्रॉस से डीटीओ ईशाक कौशिक, महेश मलिक, पार्षद प्रदीप छाबड़ी, यशपाल मवई, राजेंद्र हवलदार ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

विधायक दीपक मंगला ने सबसे पहले तो सभी रक्त दाताओं को दिल से साधुवाद कहा कि इस संकट की घड़ी में अपने घरों से निकलकर जो आपने साहस दिखाया है, लोगों की जीवन बचाने का जो कार्य आप कर रहे हैं आप कोरोना योद्धा के रूप में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं, आप सभी ने विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है, डीटीओ ईशाक कौशिक ने सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों को बहुत–बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं और आप यह बहुत नेक कार्य कर रहे हैं, मारवाड़ी युवा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री खंडेलवाल ने बताया कि रक्त देने से शरीर में नया खून बहुत जल्द बन जाता है, इससे किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होती, एक प्रति यूनिट से हम तीन लोगों का जीवन बचाते हैं, अमित अत्री ने कहा कि युवा में रक्तदान शिविर में आकर रक्त देने के लिए उत्साह बहुत प्रशंसनीय के काबिल है, राजेश बैंसला ने सभी को अवगत कराया कि समाज की अन्य संस्थाओं को भी इस नेक कार्य में आगे आकर अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, गीतांजलि पब्लिक स्कूल के प्रबंधक राजेश भारद्वाज जी ने बताया कि अगली बार तकरीबन 200 यूनिट का कैंप थैलेसीमिया के बच्चों के लिए बहुत जल्द लगाया जाएगा।

सड़क दुर्घटना में दो मासूम बच्चों की मौत, देवर–भाभी गंभीर

जांच के बाद डाक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

राष्ट्रीय राजमार्ग पर जेसीबी चौक के पास तेज रफ्तार से दौड़ रही एक बुलेट मोटर साइकिल संतुलन बिगड़ने की वजह से सड़क के बीच बने डिवाइडर से जा टकराई। इस दुर्घटना में बाइक पर सवार युवक, उसकी भाभी, भतीजा और भतीजी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों को तुरंत बीके अस्पताल ले जाया गया है। जहां जांच के बाद डाक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। जबकि अन्य दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें दिल्ली के

सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। समाचार लिखे जाने तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

पुलिस प्रवक्ता सुबेसिंह के मुताबिक राजकुमार नामक व्यक्ति दिल्ली के किराड़ी इलाके में अपने परिवार के साथ रहता है। राजकुमार के परिवार में उसकी पत्नी रेनू के अलावा सात साल का बेटा हर्ष और पांच साल की बेटी परी शामिल है। रेनू होली से पहले अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर आगरा से करीब 100 किलोमीटर आगे अपने मायके गई थी। बाद में लॉकडाउन होने पर तीनों वहीं पर फंसे रह गए थे।

पिछले दिनों लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलने पर राजकुमार ने अपने छोटे भाई विष्णु को पिछले दिनों पत्नी व बच्चों को लेने के लिए अपनी ससुराल में भेजा था। विष्णु बीती रात अपनी भाभी रेनू और बच्चों के साथ अपनी बुलेट मोटर साइकिल पर सवार होकर आगरा से दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। रविवार सुबह वह राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेक्टर 58 के नजदीक से गुजर रहा था।

तभी अचानक उसकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया। जिससे बाइक सड़क के बीच बने डिवाइडर से जा टकराई। इस दुर्घटना में चारों बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। जबकि विष्णु और रेनू की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया है। सूचना मिलने पर मृतक बच्चों का पिता राजकुमार अपने भाई विरेंद्र के साथ यहां पहुंच गया। बच्चों की मौत से लगे सदमें की वजह से राजकुमार कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। पुलिस राजकुमार के भाई विरेंद्र के बयान पर आगे की कार्यवाही कर रही है। दोनों बच्चों के शव पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं।

यमराज को अर्थी लेकर सड़क पर उतरा देख लोग हुए हैरान

यमराज ने बिना हैलमेट और बिना सोशल डिस्टेंस के कार वालों को रोका

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

मास्क लगाओं नहीं तो चलों यमलोक, यमराज के मुंह से जब यह बाते सुनी, तो फैशनेबल युवती ने मास्क लगाना बेहतर समझा। लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए सामाजिक संस्था मिशन जागृति द्वारा बीके चौक पर इस तरह का एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। उनके साथ उस समय ट्रेफिक ताऊ भी मौजूद रहे।

जानकारी के मुताबिक मिशन जागृति के द्वारा जरूरतमंदों की मदद को जारी रखते हुए अब एक नई मुहिम छेड़ी है, जिस का नारा है

जागते रहो–जगाते रहो। संस्था के जिला उपाध्यक्ष राजेश भूटिया ने बताया कि जागते रहो– जगाते रहो की कड़ी में रविवार को जिले के विभिन्न स्थानों पर लोगों को जागरूक किया। संस्था द्वारा लोगों को इस महामारी की विकरालता के बारे में समझाने के लिए जगह जगह नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए। नाटक में यमराज का किरदार अर्थी दिखाकर बीमारी की विकरालता के बारे जागरूक करने का प्रयास कर रहा था। ट्रैफिक ताऊ ने लोगों को कसम दिलाई वे हर हाल में प्रशासन द्वारा बताए गए नियमों का पालन करेंगे।

संस्था के महासचिव प्रवेश मलिक ने बताया कि संस्था के जिला उपाध्यक्ष द्वारा खुद यमराज का किरदार निभाते हुए बताया कि मास्क अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमें हर हाल में कोरोना के साथ जीना होगा, लगातार हाथ धोते रहना होगा और सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी। इस अवसर पर उपस्थित वीरेंद्र बल्हारा ट्रैफिक ताऊ ने कहा की प्रशासन के दिशा निर्देशों को प्रत्येक नागरिक को पालन करते हुए कोरोना योद्धाओं का सम्मान करना चाहिए। इस अवसर पर गुरनाम सिंह, विपिन शर्मा, अशोक भटेजा, राजेंद्र नागर, दिनेश सिंह, दिनेश कुमार, कल्पना राजपूत, मोहिनी, विकास कुमार, मुकेश, विकास कश्यप, दिनेश, अभिषेक आदी मौजूद रहे।

कोरोना महामारी में रक्तदान करना एक महान कार्य : सिंगला

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

जिला रेडक्रास सोसायटी एवं महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल ट्रस्ट द्वारा नहरपार के सेक्टर–87 स्थित श्रद्धा मंदिर पब्लिक स्कूल में अर्श हॉस्पिटल के सहयोग से एक रक्तदान शिविर एवं फ्री ओपीडी क्लीनिक का आयोजन किया गया। इस शिविर में जहां आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने अपने स्वास्थ्य की निशुल्क जांच करवाई वहीं रक्तदाताओं ने कोरोना महामारी के इस दौर में बढ़चढ़कर रक्तदान किया। शिविर में मुख्यातिथि के रूप में फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेसी प्रत्याशी लखन कुमार सिंगला ने शिविर का उद्घाटन किया वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाजसेवी शालिनी मेहता भी उपस्थित रही।

रक्तदाओं की हौंसला अफजाई करते हुए, लखन कुमार सिंगला ने कहा कि संसार में रक्तदान सबसे बड़ा दान है क्योंकि किसी मनुष्य द्वारा दान किया गया रक्त आपातकाल के समय दूसरे मनुष्य की जिंदगी बचा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान देशभर में रक्त की कमी होने लगी है, ऐसे में प्रत्येक नागरिक को इस संकट के दौरा न रक्तदान करके समाज व देश के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए।

प्रवासी श्रमिकों की पीड़ा

नकदी की ज्यादा जरूरत

हमें एक कटु सत्य नहीं भूलना चाहिए। सरकार ने चाहे जो आश्वासन दिए हों, तथ्य यह है कि गांवों की ओर पलायन भारी संख्या में जारी है। हालांकि, अब कोविड-19 लाकडाउन के कारण शहरों में बेरोजगार व पैसे के अभाव का सामान करने वाले कामगारों के लिए बसों और टेऊनों की व्यवस्था की गई है, पर हजारों अब भी सड़कों पर लंबी यात्रा कर रहे हैं। विभिन्न खबरों से संकेत मिलता है कि वे जल्दी वापस नहीं लौटेंगे क्योंकि सरकार ने उनकी चिन्ता नहीं की है तथा लाकडाउन की घोषणा करते समय उनको कारगर विकल्प नहीं दिए गए थे। अनेक श्रमिकों ने कहा कि वे शहर में लौटने के बजाय मामूली खेती से थोड़ा-बहुत कमा लेंगे क्योंकि शहरों ने उनको बीमारी दी है, रोगवाहक बता कर उनकी छवि खराब की है, उनका रोजगार छीना है तथा मकान मालिकों ने बिना कोई रियायत दिए उनको बेघर किया है। उनकी गुस्सा, आहत भावना और कठोरता के कारण देश भर में श्रमिकों की कमी अनुभव की जा रही है तथा कोविड-पश्चात आर्थिक गतिविधियां बहाल होने के बावजूद श्रमिक जल्दी से वापसी को तैयार नहीं हैं। दिहाड़ी श्रमिकों व सड़क पर सामान बेचने वालों के लिए वित्तीय पैकेज में भी नीतिगत हस्तक्षेप शामिल हैं जिनका क्रियान्वयन लाभार्थी तक पहुंचना सरल नहीं है। खैरात की प्रतीक्षा या उसके लिए लाइनों में लगने के बावजूद श्रमिकों को तुरन्त नकदी की जरूरत है। अब तक की गई राहत घोषणायें लागू होने में कुछ समय लेंगी। किसानों व खेतिहर मजदूरों की यूनियनों ने लगातार 7,500 रुपये प्रति माह आय सहायता की मांग की है, पर सरकार ने अभी नकदी सहायता पर विचार नहीं किया है। उन्होंने बटाईदारों समेत सभी किसानों के लिए पीएम-किसान योजना में 18,000 रुपये प्रति वर्ष मांगे थे। लेकिन थोड़े लोगों को केवल 2,000 रुपये की किश्तें दी गईं। उनको बिना ब्याज का कर्ज भी नहीं मिला। एक संयुक्त बयान में किसानों ने कहा है कि पीएम-किसान से 14.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलना चाहिए था, पर केवल तीन करोड़ को कृषि कर्ज मिला है। इसके अलावा ज्यादातर कर्ज कृषि बिजनेसों व बड़े किसानों के हिस्से में आया है क्योंकि बैंक छोटे किसानों को कर्ज नहीं देना चाहते हैं। सप्लाई श्रृंखला में बाधा तथा खराब होने के कारण उनको कृषि उत्पाद के लिए उचित मूल्य या मुआवजा भी नहीं मिलता है। इसी प्रकार रेहड़ी-खोमचे वालों के लिए घोषित कर्ज मिलने में प्रक्रियाओं के कारण लंबा समय लगेगा। ऐसे 50 लाख लोगों को 5,000 करोड़ रुपये जल्दी नहीं मिलेंगे। 10,000 रुपये की पूंजी के लिए वे लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो वादे किए गए हैं, पर उनके पूरे होने का रास्ता स्पष्ट नहीं है।

सरकार ने अगले दो महीने तक उन लोगों को भी राशन देने की घोषणा की है जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं हैं। उसने 'एक भारत राशन कार्ड' की घोषणा भी की है जो एक साल में पूरी होगी और इसमें आठ करोड़ प्रवासी श्रमिक शामिल हो सकेंगे। उस समय तक केवल उनके घरों पर राशन कार्ड होंगे और शायद यह भी पलायन का एक अहम कारण है। सवाल यह है कि क्या अल्पकालीन रूप से सामुदायिक भोजनालयों या फूड टोकेनों की सुनियोजित व्यवस्था नहीं हो सकती थी। अपनी आय बहाल होने से पहले श्रमिकों को नकदी सहायता से लाभ मिल सकता था। कुछ समय पहले मनरेगा के अंतर्गत लौटने वाले प्रवासियों को समाहित करने पर बहुत कुछ कहा गया था। शुरुआत में इसमें पंजीकरण कराने वालों की संख्या बढ़ी, पर अब ठहर गई है। इसका कारण यह है कि योजना का समुचित विस्तार नहीं हुआ है तथा सोशल डिस्टेंसिंग व नए मानकों के कारण थोड़े काम ही संभव हैं। सस्ते मकानों की सब्सिडी योजना का विस्तार एक साल के लिए किया गया है, लेकिन बिना आमदनी या रोजगार के कोई आवास योजनाओं के बारे में सोच भी नहीं सकता है। सरकार को न्यूनतम मजदूरी तथा श्रमिक अधिकारों के मामले में संतुलन बनाना भी जरूरी है क्योंकि राज्यों में भाजपा सरकारें भारी निवेश आकर्षित करने के लिए जटिल श्रम कानून समाप्त कर रही हैं। लेकिन क्या समान सामाजिक सुरक्षा के अभाव में 12 घंटे की पाली अंततः हानिकारक नहीं सिद्ध होगी?

बढ़-चढ़कर मांग न करें राज्य सरकारें

राज्य सरकारों को अप्रैल-जून के लिए आवश्यक राशि का आकलन करना चाहिए, केंद्र द्वारा जो दिया गया है उसका ध्यान रखना चाहिए और यदि फिर भी आवश्यकता हो तो केवल वृद्धिकारी धन की मांग करनी चाहिए।

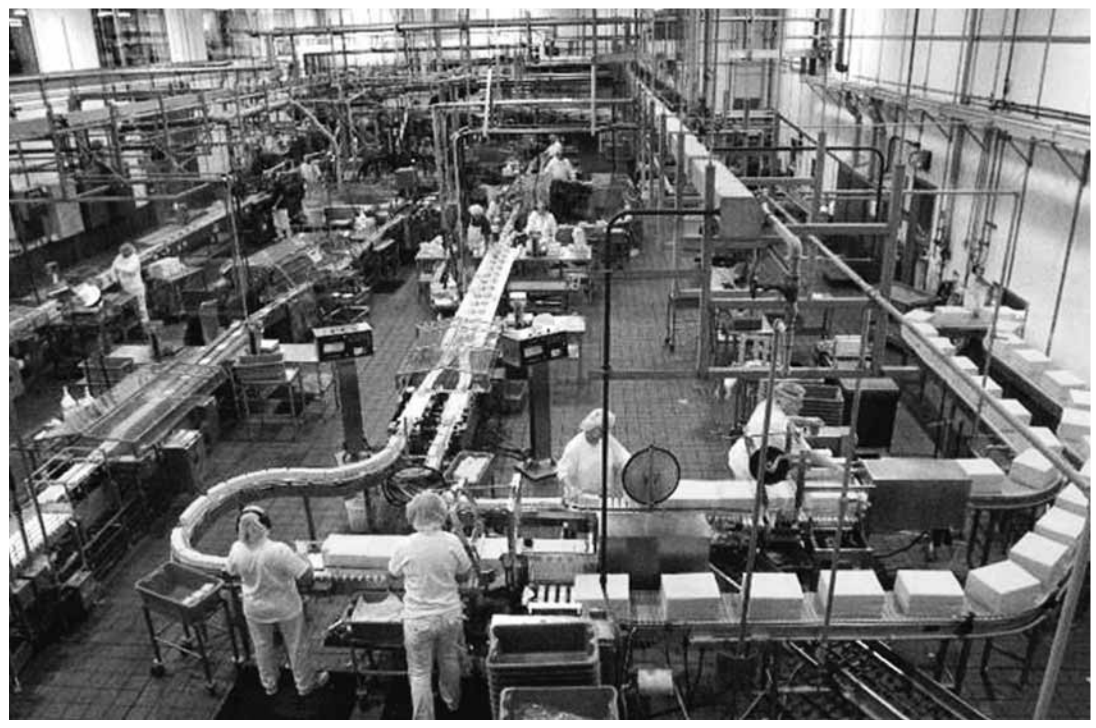

उत्तम गुप्ता
लेखक नीति विश्लेषक हैं

जबकि महामारी से प्रभावित कारपोरेट, एमएसएमई, अनौपचारिक क्षेत्र कामगार एवं अन्य केंद्र से राहत पैकेज की मांग कर रहे थे और उचित समय पर सरकार ने भारी-भरकम पैकेज का एलान कर दिया। इस पैकेज का उद्देश्य कोविड-19 के प्रभाव के चलते सुस्ती का शिकार हो चुकी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना है। राज्य सरकारों ने भी सरकार के समक्ष मांग सूची पेश की है तथा पांच राज्यों ने सामूहिक रूप से कुल मिलाकर 2,25,000 करोड़ रुपए की मांग की है। जबकि महाराष्ट्र ने 50,000 करोड़ रुपए की मांग की है, छत्तीसगढ़ को 30,000 करोड़ चाहिए, केरल को 80,000 करोड़, राजस्थान को 40,000 करोड़ चाहिए तथा पश्चिम बंगाल ने देशव्यापी लाकडाउन के कारण हुए राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु 25,000 करोड़ की मांग रखी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय कोविड-19 प्रबंधन निधि गठित करने का सुझाव दिया है जिससे राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर धन दिया जा सके। ममता ने इसका समर्थन किया है, जो चाहती हैं कि असंगठित क्षेत्र, चाय बागानों, एमएसएमई क्षेत्र के प्रत्येक कामगार व एवं किसानों को 10,000 रुपए दिए जाएं।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अगले तीन महीनों तक स्थानीय दशाओं के अनुरूप खर्च करने हेतु लचीलेपन के साथ राजस्व अनुदान दिए जाने की बात कही है जिसमें गेहूं की खरीद के लिए किसानों को बोनस, दिहाड़ी पर काम करने वाले औद्योगिक एवं कृषि मजदूरों को प्रत्यक्ष नगद सहायता देना भी शामिल है।

इसके साथ-साथ अन्य लंबित मांगें भी हैं, यथा, दिसंबर 2019 से जनवरी 2020 की अवधि के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति तत्काल जारी किया जाना, उधार लेने की सीमा को राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन कानून- एफआरबीएम के तहत राज्य जीडीपी के 3 प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत किया जाना, तीन महीने के लिए सभी राज्य विकास ऋण के पुनर्भुगतान स्थगित किया जाना, कोविड-19 प्रबंधन के लिए फ्लेक्सी फंडों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत लाना एवं उनके तरीकों व साधनों के एडवांसेज की सीमा में और बढ़ोतरी किया जाना, और एमएसएमई के लिए जीएसटी एडवांस कर तथा आयकर का भुगतान छह महीने तक टाला जाना आदि शामिल हैं। संकट की दशा में, जब तबाही चारों आोर फैली है तथा माहौल गरम है, कोई भी मांग, भले ही अतर्कसंगत हो, मगर उसका व्यापक प्रभाव होता है। जैसे कि महाराष्ट्र ने एक लाख करोड़ की मदद मांगी थी। लेकिन इसस बड़ा सवाल उठता है, वह यथार्थपरक राशि क्या होगी जो राज्यों को मांगनी चाहिए? यह काफी हद तक केंद्र द्वारा हाल ही में अपने पैकेज के अंतर्गत घोषित की गई सहायता पर निर्भर करता है। अतः, केंद्र क्या दे रहा है?

केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार चालू वित्त वर्ष के पहले दस महीनों के दौरान जनवरी 2021 तक, केंद्रीय करों का 70 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को जारी करने का वादा किया है जो लगभग 5,55,000 करोड़ की राशि होगी। यह बजट अनुमानों के अनुसार राज्यों को 8 लाख करोड़ कुल हस्तांतरण होगा। इस प्रकार, यदि कर संग्रहण में गिरावट आती है, जो कि महामारी के चलते अवश्यंभावी है, राज्यों को उपलब्ध धन में कोई कटौती नहीं होगी। सेस संग्रहण में गिरावट के बावजूद केंद्र ने लंबित जीएसटी मुआवजे का एक हिस्सा जारी कर दिया है। इस उद्देश्य के लिए, उसने न केवल पिछले वर्ष की 30,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि का इस्तेमाल किया है बल्कि उसका इरादा यह सुनिश्चित करने के लिए उधार लेने का हे कि सभी देयताएं पूर्ण हो जाएं। सरकार ने राज्यों को केंद्र पोषित योजनाओं के लिए धन की पहली किस्त जारी करके मदद मुहैया कराई है।

साथ ही साथ, भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च के स्तर एवं उसके ऊपर राज्यों की साधन एवं तरीके एडवांसेज सीमा में 60 प्रतिशत की वृद्धि के लिए अनुमति दी है (ये उधार इसलिए लिए गए हैं जिससे उन्हें अपनी प्राप्तियों एवं व्यय के नगदी प्रवाह में अस्थायी तालमेल के अभाव से निबटने के लिए लिए गए हैं, हालांकि, यह धन तीन महीने के भीतर लौटाना होगा)। एफआरबीएम अधिनियम- 2003 के पुनरीक्षण पर एनके सिंह समिति की सिफारिशों को लागू करते हुए, जिसमें अपवादपूर्ण स्थितियों में 0.5 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य का उल्लंघन करने की अनुमति है, केंद्र ने राज्यों को 0.5 प्रतिशत तक राज्य जीडीपी के तीन प्रतिशत का उल्लंघन करने की अनुमति दे दी है।

उपरोक्त चार तरीकों से उपलब्ध धन राज्यों के समक्ष संसाधनों के अभाव की समस्या को संबोधित करने में मददगार होना चाहिए। डब्लूएमए सीमा में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी से उनके पास 50,000 करोड़ उपलब्ध होंगे। इसी तरह, एफआरबीएम सीमा में राहत उन्हें अतिरिक्त अवसर देती है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र को 15,000 करोड़ अतिरिक्त उधार लेने में सक्षम होगा (30,00,000 करोड़ का लगभग 0.5 प्रतिशत राज्य जीडीपी है)। केंद्र की झोली से राज्यों को मिलने वाला टैक्सों का हिस्सा भी काफी मददगार होगा। जहां तक जीएसटी क्षतिपूर्ति का सवाल है, केंद्र लंबित देयताएं चुकाने के हरसंभव प्रयास कर रहा है।

इसके साथ-साथ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमकेजीएस) के अंतर्गत, केंद्र 1,70,000 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों को दे रहा है। इसमें शामिल है लगभग 80 करोड़ लोगों को तीन महीने के लिए प्रति माह 5 किलो चावल अथवा गेहूं मुफ्त दिया जाना, महिला जनधन खाताधारकों को 500 रुपए प्रति माह देना, पीएम-किसान के अंतर्गत लगभग 9 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए दिया जाना, तीन करोड़ विधवाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को 1,000 रुपए का अनुग्रह भुगतान, 8.3 करोड़ महिला उज्जवला योजना लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलिंडर देना एवं मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी।

राज्य सरकारें निर्माण श्रमिकों की मदद करने हेतु लगभग 31,000 करोड़ की कल्याणकारी निधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, परीक्षण गतिविधियों, चिकित्सा स्क्रीनिंग एवं महामसरी से लड़ने के लिए स्वास्थ्यरक्षा मुहैया कराने हेतु जिला खनिज निधि के अधीन निधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। केंद्र सरकार नियोक्ता एवं कर्मचारी को ईपीएफ योगदान अथवा तीन महीनों के लिए 24 प्रतिशत का भुगतान कर रही है। उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत लाभों के लिए अपार धन खर्च होगा और उसकी आवश्यकता पड़ने पर राज्यों को विचार करने की आवश्यकता होगी।

इसी तरह, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र की राज्यों में स्थित इकाइयों में दबाव ग्रसित संसाधनों के लिए मानक सरल बनाने एवं क्रेडिट की लागत घटाने एवं और अधिक क्रेडिट दिए जाने के लिए आरबीआई द्वारा उपायय किए गए हैं। मात्र 4.4 प्रतिशत पर लगभग पांच लाख करोड़ रुपयों की तरलता समाहित करने से मिलने वाले बल का भी गणनाओं में उचित ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। राज्यों को केवल वृद्धिकारी धन की मांग करनी चाहिए।

मगर ऐसा नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए, जब महाराष्ट्र एक लाख करोड़ की मदद मांगता है, तो तर्क दिया जाता है कि इसकी आवश्यकता लाकडाउन के कारण हुए राजस्व के नुकसान की भरपाई करने के लिए है। क्या केंद्र यह मान ले कि महाराष्ट्र ने 40 दिनों में इतना राजस्व गंवा दिया होगा? यह विचित्र बात है। यदि यह संपूर्ण वर्ष के लिए अनुमानित नुकसान है, तो भी इसे तत्काल जारी करने की मांग पूरी नहीं की जा सकती।

लाकडाउन समाप्त होने के पश्चात स्थिति क्या होगी, कोई नहीं कह सकता। सुधार का स्वयूप वी- आकार का हो सकता है। उस स्थिति में, महामारी के कारण राजस्व का नुकसान काफी कम होगा। यदि अर्थव्यवस्था में सिकुड़ने की स्थिति है और नुकसान बहुत ज्यादा है, तो भी राज्य बाद में मदद मिलने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। राज्यों को एक वस्तुपरक एवं तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों को अप्रैल-जून के लिए आवश्यक राशि का आंकलन करना चाहिए, केंद्र तथा आरबीआई द्वारा जो पहले से ही दिया जा रहा है उसका ध्यान रखना चाहिए। यदि फिर भी आवश्यकता हो तो केवल वृद्धिकारी धन की मांग करनी चाहिए। राज्यों को समझना चाहिए कि केंद्र में पास धन असीमित नहीं है और इसके अनुरूप अपनी मांगों को समायोजित करना चाहिए।

दंत चिकित्सकों पर कोविड-19 की मार

"कोविड-19 ने दंत चिकित्सकों को स्वास्थ्यकर्मियों के संकटग्रस्त समूह में शामिल कर दिया है क्योंकि लार ग्रंथियां कोरोनावायरस का संभावित भंडार स्थल होती हैं।"

ज्योति कपूर
(लेखिका एक दंत चिकित्सक हैं)

इस वर्ष भारत में दंत चिकित्सा के 100 साल पूरे हो रहे हैं। देश में पहला डेंटल कालेज कोलकाता में 1920 में खोला गया था और वहां दंत चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराई गई थी। इससे समुदाय को सस्ते दामों में दंत चिकित्सा उपलब्ध हुई। आज भारतीय डेंटल कौंसिल-डीसीआई में 2.7 लाख दंत चिकित्सक पंजीकृत हैं जिनमें से केवल 7,239 ही सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं। बहुसंख्यक दंत चिकित्सक या तो निजी अस्पतालों व क्लीनिकों में हैं या निजी प्रैक्टिस करते हैं। लगभग तीन चौथाई डेंटिस्ट शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं और वे अपने सहायकों तथा निजी बायोमेडिकल कचरा संग्रह कंपनियों के माध्यम से देश में रोजगार सृजन भी कर रहे हैं।

डेंटिस्ट अनेक गंभीर बीमारियों के निदान में अग्रणी पंक्ति में शामिल हैं जिनमें मुंह का कैंसर, कैंसर-पूर्व धब्बे, ल्यूकेमिया, मधुमेह, अग्नाशय कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग, अस्थियों का क्षरण आदि हैं। किसी व्यक्ति के मुख का स्वास्थ्य उसकी समग्र फिटनेस का संकेत देता है क्योंकि मुंह की समस्या पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है। 90 प्रतिशत से अधिक बीमारियों के लक्षण मुंह में दिखाई देते हैं जिनमें मसूढ़ों की सूजन, मुंह के अल्सर, मुंह सूखना, मसूढ़ों की गंभीर समस्यायें, आदि शामिल हैं। इस प्रकार सतर्क डेंटिस्ट अस्पतालों में रोज अनेक जीवन बचाने का काम करते हैं। लेकिन कोविड-19 ने डेंटिस्टों को स्वास्थ्यकर्मियों के संकटग्रस्त समूह में शामिल कर दिया है क्योंकि लार ग्रंथियां कोरानावायरस का संभावित भंडार स्थल होती हैं।

अप्रैल में जर्नल आफ डेंटल रिसर्च में प्रकाशित लेख 'सैलाइवरी ग्लैंड्स: पोटेंशियल रिज़रवायर्स फार कोविड-19' में बताया गया है कि 'कोविड-19 रोगियों की लार में वायरस की उपस्थिति 91.7 प्रतिशत तक हो सकती है तथा लार के नमूनों में जीवित वायरस पनप सकते हैं। इससे संकेत मिलता है कि कोविड-19 का एसिम्प्टोमैटिक संक्रमण लार ग्रंथियों से संभव है। ऐसे में हमें केवल लार की संक्रामक क्षमता पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए।'

डेंटिस्ट व उनके सहायक रोगियों के बहुत निकट होकर काम करते हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग लगभग असंभव है। एक आम डेंटल क्लीनिक एक बंद कमरा होता है जिसमें हवा बहुत कम आती है तथा सूर्य का प्रकाश भी कम होता है। अनेक डेंटल क्लीनिकें बेसमेंट में होती हैं। डेंटिस्ट्री में रोटरी, डेंटल व सर्जिकल उपकरणों का प्रयोग होता है। इनमें अल्ट्रासोनिक स्केलर्स व एयर-वाटर सिरिंजें शामिल हैं। इन उपकरणों से एक फुहार पैदा होती है जिसमें पानी, लार, रक्त, माइक्रोआर्गेनिज्म व अन्य चीजें हो सकती हैं। यह फुहार थोड़ी देर में फर्श तथा नजदीक की अन्य सतहों पर बैठ जाती है। इनमें डेंटिस्ट, उनका सहायक व स्वयं रोगी भी शामिल है।

कोरोनावायरस की संक्रामक प्रकृति को देखते हुए कोई संयोग नहीं है कि चीन में जनवरी में तीन महीने के लिए दांतों की देखभाल रोक दी गई थी। बाद में यह कठोर व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों के साथ फिर शुरू की गई। आस्ट्रेलिया की स्वास्थ्य संरक्षण समिति ने भी सभी आवश्यक एवं सामान्य दंत देखभाल चेकअप स्थगित करने की सलाह दी थी जिसमें टूटे दांतों, सूजे या खून निकलने वाले मसूढ़ों, सांस में बदबू, कमजोर दांत, नकली दांत लगाना, क्राउन व ब्रिज, स्केलिंग व पालिशिंग, फिलिंग, आदि प्रक्रियायें शामिल हैं।

डेंटिस्टों ने रोगियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। लेकिन कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए डेंटल क्लीनिकों में और परिवर्तनों की आवश्यकता है। डीसीआई ने क्लीनिक में प्रवेश करने वाले सभी रोगियों का तापमान देखने जैसे कुछ सुझाव दिए हैं। क्लीनिकों में भीड़ से बचने, पीपीई किट पहनने, इंट्रा-ओरल एक्सरे से बचने, एयरोसाल कम से कम करने तथा हाई-वोल्यूम सक्शन प्रयोग करने तथा थ्री-इन-वन सिरिंज का प्रयोग न्यूनतम करने की सलाहें इनमें शामिल हैं। इन मानकों से अनेक समस्यायें पैदा होती हैं। इसके साथ ही रोगियों के इलाज का खर्च बढ़ता है। क्या इससे दंत चिकित्सा पर खर्च लोगों की क्षमता से बाहर हो जाएगा? क्या भविष्य में छोटे डेंटल क्लीनिक चलाना संभव नहीं होगा और हमें वैश्विक महामारी के साथ जीना सीखना होगा?

वर्तमान समय में डेंटिस्टों को सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। सरकार टेस्टिंग किट, पीपीई व अन्य संक्रमण नियंत्रण सामग्री व उपकरण दे कर डेंटिस्टों की सहायता कर सकती है। सरकार डेंटिस्टों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों व इंप्लांट पर टैक्स में रियायत दे सकती है। दुनिया भर के डेंटिस्ट आज दुविधा में हैं। क्लीनिक बंद करने पर उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, जबकि ऐसा न करने पर वे स्वयं तथा अपने सहायकों को संक्रमण के खतरे में डालेंगे। दुनिया भर में डेंटिस्टों ने अपने काम का समय घटाया है या क्लीनिकें पूरी तरह बंद कर दी हैं। भविष्य अनिश्चित है, ऐसे में सबको साथ आ कर समस्या का समाधान निकालना चाहिए।

आप की बात

मजबूर है मजदूर

गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा तथा बिहार के चम्पारण पहुंचने की यात्रा, दोनों में एक सौ से कुछ अधिक वर्ष हो चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय नागरिकों को एग्रीमेंट पर मजदूरी करने को विवश किया गया जिसको देखते हुए यात्रा दादा अब्दुल्ला के आमंत्रण पर गांधी जी ने मजदूरों के पैरवीकार के रूप में की तथा पण्डित राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर बापू बिहार के चम्पारण 17 अप्रैल 1917 को अंग्रेजी शासन की अन्यायपूर्ण शोषण के चलते किसानों से तीनकठिया प्रथा के अंतर्गत जोर जबरदस्ती से नील की खेती न कराए जाने तथा किसानों पर लगाए गए करों को वापस करने के पक्ष में की गईं। दोनों यात्राएं मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाने की ओर आकर्षित करती जा रही थीं। ध्यान से सोचने की जरूरत है कि क्या पिछले एक सौ वर्षों से कुछ अधिक के वर्षों में दक्षिण अफ्रीका के तत्कालिक मजदूर शब्द व संस्कृति तथा अब स्वतंत्र भारत में मजदूर शब्द व संस्कृति में क्या कोई मौलिक अन्तर आया है? क्या मजदूर मजबूत है या मजबूर? इनका उत्तर नहीं में है क्योंकि गांधी जी की दोनों यात्राएं मजदूर एवं किसानों के लिए की जाती हैं इसका सीधा आशय यही है कि किसी भी देश का बुनियादी ढांचा इन्हीं दो वर्गों पर टिका हुआ है।

– **अभिनंदन भाई पटेल**, लखनऊ

ब्राजील की बड़ी गलती

कोरोना वायरस को जिस भी देश ने हल्के में लिया वह अब पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा है। गनीमत यही है कि भारत ने इस वायरस के खतरे को पहले ही जान लिया था और सही समय पर सटीक कदम भी उठा लिए गये और इसी लिए आज अन्य देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर कही जा सकती है । मगर जिनकी अर्थव्यस्था बहुत बेहतर है वह इस वायरस के खतरे को जानकर भी अंजान बनते रहे और इस संक्रमण से सतर्क होने के बजाय अर्थव्यस्था पर ध्यान दिया जिसके चलते आज हजारों बेकसूर जिन्दगियां दुनिया दामन छोड़ चुकी हैं और यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के प्रति लापरवाही करने में एक नया देश शामिल हो चुका है जिसका नाम है ब्राजील। कोरोना एक छुआछूत की बीमारी है जिसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। इस बात की जानकारी लगभग सभी देशों को हो गई थी मगर ब्राज़ील सरकार इस जानलेवा वायरस को मात्र एक साधारण बीमारी मान कर कोई भी सख्त कदम नहीं उठाए गये जिसका नतीजा यह है कि ब्राज़ील एक नया कोरोना हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। अब तक ब्राज़ील में 2 लाख से ऊपर कोरोना पीड़ितों के मामले आ चुके हैं।

– **यशस्वी सिंह**, प्रयागराज

विजय माल्या की वापसी

विजय माल्या वो शख्स जिसने भाजपा की सत्ता में वापसी होते ही, भगोड़ा शब्द को प्रचलन में ला दिया। सरकार की कार्रवाई के चलते माल्या के बाद कई और लोन डिफाल्टर देश से भागने का रास्ता अपनाने लगे कुछ सफल हुए तो कुछ असफल। लगभग दस हजार करोड़ रुपए के बैंक ऋण के घोटाले में भारत से लन्दन भाग गए माल्या की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। जब से पता चला है कि माल्या लन्दन में छिपा है तभी से जांच एजेंसियां उसे कानूनी तौर पर भारत लाने के लिए प्रयास कर रही थी। माल्या भी बचने के लिए लन्दन के लोअर कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक का सहारा ले रहा था किन्तु अब वहां की हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि माल्या को भारत भेजा जा सकता है साथ ही हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है। अब माल्या के पास सिर्फ यूरोपीय यूनियन की कोर्ट जाने का रास्ता बचा है। अगर वहां पर भारतीय जांच एजेंसियों की विजय होती है तो जल्द माल्या भारत की गिरफ्त में होगा। माल्या के भारत आते ही कई अनसुलझे सवालों के जवाब भी मिल जायेंगे।

– **अभिनव दीक्षित**, बांगरमऊ

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते है।

फरमाया

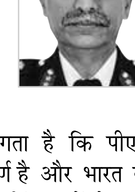

यह मानने का कारण है कि नेपाल ने किसी अन्य के कहने पर यह मुद्दा उठाया होगा। इसकी प्रबल संभावना है।

– **एमएम नरवने**
सेना प्रमुख

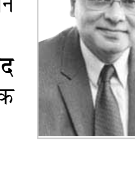

मुझे लगता है कि पीएम का आत्मनिर्भर मिशन महत्वपूर्ण है और भारत कोविड-19 पश्चात जीवन तथा आजीविका में भेद नहीं कर रहा है।

– **जुनैद अहमद**
विश्व बैंक के भारत निदेशक

कांग्रेस को प्रवासी मजदूरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उसे लोगों को लाने व भेजने की जिम्मेदारी निभाने के लिए अपनी राज्य सरकारों को निर्देशित करना चाहिए।

– **धर्मेंद्र प्रधान**
केंद्रीय मंत्री

आत्मनिर्भर बनने में मददगार होगा राहत पैकेज: योगी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

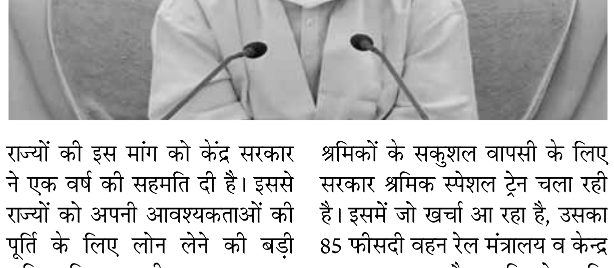

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश को स्वावलंबन और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार के पैकेज की सराहना करते हुये कहा कि आर्थिक पैकेज से देश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी। जिससे न केवल देश का हर नागरिक खुशहाल होगा, बल्कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जीतने में हम सफल होंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री राहत पैकेज के माध्यम से वित्तमंत्री ने चार दिनों में जो अलग-अलग पैकेज की घोषित किये है उससे देश आत्मनिर्भर बन सकेगा। उन्होंने कहा पैकेज में प्रत्येक नागरिक तक शासन की सुविधाओं को पहुंचाने और उनके स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा कि सभी राज्य एफआरबीएम की सीमा को 3 फीसदी से बढ़ाकर 5 फीसदी करने की मांग कर रहे थे। राज्यों की इस मांग को केंद्र सरकार ने एक वर्ष की सहमति दी है। इससे राज्यों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोन लेने की बड़ी सुविधा मिल जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रोजगार, शिक्षा, इंडस्ट्री और गरीब कल्याण को लेकर जो घोषणा की है उसका लाभ देश के हर एक नागरिक को मिलेगा। एमएसएमई लोकल को ग्लोबल बनाने की प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, उसका ये आधार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के सकुशल वापसी के लिए सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रही है। इसमें जो खर्चा आ रहा है, उसका 85 फीसदी वहन रेल मंत्रालय व केन्द्र सरकार कर रहा है, जबकि शेष राशि का वहन संबंधित राज्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 475 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन आई है। इसमें 6 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपद के क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाने का काम किया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रवासी श्रमिकों के बारे जो व्यापक कार्ययोजना घोषित की गई है, इसमें देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 18 करोड़ लोगों को तीन बार मुफ्त में राशन उपलब्ध करवाया जा चुका है। इसके अलावा प्रदेश में रोजगार सृजन के कार्य शुरू हुए हैं। एमएसएमई सेक्टर की इंडस्ट्री चालू हुई हैं, इसमें रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मनरेगा में प्रतिदिन 30 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इसमें 300 करोड़ रोजगार सृजित करने लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 40 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मानसून के दौरान भी सभी लोगों को कार्य मिले सके, इसका भी प्रावधान किया गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है।

सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य सेक्टर में प्रदेश पिछले तीन साल में बेहद मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट जब शुरू हुआ तो हमारे पास पर्याप्त सामान नहीं थे, लेकिन मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में 26 लैब हैं। पर्याप्त मात्रा में केंद्र सरकार हमें किट मुहैया करवा रही है। प्रतिदिन 6000 टेस्ट हो रहे हैं। अगले दो तीन दिन में इसे बढ़ाकर 10 हजार किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1.75 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से इसकी क्षमता में विस्तार किया जा रहा है।

योगी ने कहा कि पीपीई किट उत्पादन की 26 यूनिट अकेले उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई है। उत्तर प्रदेश से 28 राज्यों में सेनीटाइजर भेजा जा रही है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेक्टर में बड़ा काम हुआ है। प्रदेश में तीन साल के अंदर में 29 नए मेडिकल कालेज बनने प्रारंभ हुए है। इसमें पिछले साल 7 मेडिकल कालेज में प्रवेश भी शुरू हुआ। दो नए एम्स प्रारंभ हुए हैं। गोरखपुर और रायबरेली में ओपीडी के साथ-साथ पाठ्यक्रम भी प्रारंभ हुआ। शेष में कार्य तेजी के साथ चल रहा है।

यूपी में नहीं, महाराष्ट्र और पंजाब में बसें भेजें प्रियंका :सिद्धार्थ नाथ सिंह

● यूपी सरकार ने 400 से अधिक ट्रेनों की बुकिंग की है इसके अलावा 11000 बसें दूसरे राज्यों से प्रवासियों को उत्तर प्रदेश लाने में लगी हुई

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि एक हजार बसें यूपी भेजने के प्रियंका गांधी के सुझाव का कोई मतलब नहीं है। उन्हें समझना चाहिए कि प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं न कि यूपी से बाहर जा रहे हैं। इसलिए प्रियंका गांधी को इन बसों को कांग्रेस शासित राज्य महाराष्ट्र और पंजाब भेजना चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा द्वारा उप्र की सीमाओं पर बसें भेजने से पता चलता है कि उन्हें लॉजिस्टिक्स की समझ नहीं है और वे इस मुद्दे पर विशुद्ध रूप से राजनीति कर रही हैं।

प्रियंका वाड्रा को समझना चाहिए कि प्रवासी उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान आदि राज्यों से आ रहे हैं। इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी या उनके गठबंधन की सरकारें है। अगर प्रियंका वाड्रा लॉजिस्टिक्स के नियम को समझती तो बसों को उन्हीं राज्यों में रखा जाना चाहिए ताकि प्रवासी अपने गंतव्य अर्थात उत्तर प्रदेश पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से प्रियंका कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात ना करके उत्तर प्रदेश सरकार पर उंगली उठा रही है। इससे उनकी विषयों पर खराब समझ और पकड़ का पता चलता है। उन्होंन कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार ने 400 से अधिक ट्रेनों की बुकिंग की है। इसके अलावा 11000 बसें दूसरे राज्यों से प्रवासियों को उत्तर प्रदेश लाने में लगी हुई हैं। सरकार द्वारा सभी प्रवासियों के स्वास्थ्य का उचित प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद प्रत्येक प्रवासी को 15 दिन का राशन और 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके अलावा गांव पहुंचने पर प्रवासियों को प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है।

हर समस्या का किया जाएगा निदान: केशव प्रसाद मौर्य

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

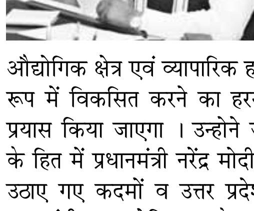

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को कौशांबी जनपद के विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता करते हुए उनकी समस्याएं सुनी तथा कोविड.19 के दृष्टिगत विभिन्न लोगों के सुझाव भी सुने तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह सुझावो पर विचार करते हुए निर्धारित मानकों व गाइड लाइन के अनुरूप कार्रवाई करें। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी कोविड.19 के चलते उनकी समस्याओं को साझा किया तथा उनके सुझाव सुनें और उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दिया । उन्होंने कहा कि प्रयागराज को औद्योगिक क्षेत्र एवं व्यापारिक हब के रूप में विकसित करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा । उन्होने जनता के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड.19 के दृष्टिगत की गई व्यवस्थाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दी तथा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी और कहा कि हम सब लोग मिलकर कोरोना की जंग में विजई होंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या दूर करने के लिए त्रिस्तरीय कंट्रोल रूम बनाएं

● पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को दिए निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

गर्मी के मौसम में ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या को देखते हुए पंचायती राज विभाग ने सभी जिले के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर पेयजल की समस्या दूर करने को कहा है। प्रमुख सचिव पंचायती राज जिलों के डीएम को जारी आदेश में जिलों में पेयजल की समस्या के निस्तारण को लेकर नोडल अधिकारी की नियुक्ति के साथ ही त्रिस्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना करते हुए प्रशासनिक मशीनरी को अलर्ट पर रखने को कहा गया है।

प्रमुख सचिव पंचायती राज अनुराग श्रीवास्तव के स्तर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना महामारी के चलते इस साल सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी नियमों के पालन करने जरूरी हैं। अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि इसके लिए ब्लाक व जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए। इस व्यवस्था से तहसीलों विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों को भी जोड़ा जाए। जिससे इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। अपने आदेश में प्रमुख सचिव ने यह सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है कि सभी खराब हैंडपंप तत्काल ठीक करा दिए जाएं। उन्होंने कहा है कि लोगों के घरों के नजदीक तक पानी उपलब्ध कराना संभव ना हो पा रहा हो तो पूर्व वर्षों की भांति वांछित टैंकरों की सूची तैयार की जाए।

लाचार श्रमिक और उनकी भूख साथ चलने को मजबूर: अखिलेश

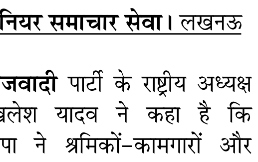

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने श्रमिकों-कामगारों और गरीबों को जितना अपमानित किया, वह दुखभरी अनन्त दास्तान है। इस पीड़ा और कष्ट को श्रमिक कभी भूल नहीं पायेगा। यह कैसी विडम्बना है आजाद भारत में लाचार श्रमिक और उनकी भूख साथ चलने को मजबूर है। यह स्थिति राष्ट्रीय त्रासदी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि बेसहारों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। यह घोर अमानवीय कृत्य है। इस संकट का जिम्मेदार कौन है, आखिर 54 दिन से केन्द्र और राज्य की सरकारें क्या करती रहीं यह लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार का आदेश है कि प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश की सीमा में न घुसने देंगे, न रेल ट्रैक पर चलने देंगे, न ट्रक-दुपहिया से जाने देंगे। भाजपा की गरीब विरोधी नीतियां ही लोगों को ये सब काम करने को मजबूर कर रही हैं। अच्छा हो, सरकार गरीब की जिंदगी पर ही रासुका लगा दे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार का गरीब मजदूरों के प्रति ऐसा ही दुर्भावनापूर्ण और उपेक्षापूर्ण व्यवहार बना रहा तो भला किस पर विश्वास कर ये प्रवासी मजदूर काम पर वापस लौटेंगे, अमीरों की इस सरकार ने अब तो श्रमकानूनों का रक्षा कवच भी छीन लिया है।

ट्रेनों से अब तक 6 लाख 65 हजार लोगों की हुई वापसी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि देश में सबसे अधिक प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश में आये हैं। प्रदेश में अब तक 522 ट्रेन के माध्यम से लगभग 665369 प्रवासी कामगार एवं श्रमिक आये हैं। प्रदेश में आज अन्य प्रदेशों से कामगारों, श्रमिकों को लेकर 87 ट्रेन और आ रही हैं। लगभग 250 और ट्रेन की सहमति दे दी गई है। अब तक प्रदेश में 16.50 लाख से अधिक कामगार, श्रमिक प्रदेश में आये हैं। गोरखपुर में अब तक 79 ट्रेन से 92298 कामगार एवं श्रमिक आए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा और राजस्थान से प्रतिदिन 150 से 200 बसें चलाई जा रही हैं। लखनऊ में 45 ट्रेन के माध्यम से 55 हजार लोग आए हैं। वाराणसी में 27 ट्रेन आ चुकी हैं। रेलवे विभाग को 6 करोड़ रूपए का भुगतान कर दिया गया है तथा 20 करोड़ रूपए और भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली से 11 ट्रेन प्रतिदिन प्रदेश के विभिन्न भागों में आयेगी। यूपीएसआरटीसी की 10 हजार बसों के माध्यम से प्रवासी कामगारों, श्रमिकों को उनके गृह जनपद में भेजने की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य से पहली ट्रेन प्रदेश में आई है। पूर्वोत्तर राज्यों एवं उड़ीसा से शीघ्र ही ट्रेन चलाये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

1 लाख 50 हजार से अधिक लोगों ने अपने निजी वाहनों से वापसी की है। कुल मिलाकर अब तक 16 लाख 50 हजार लोगों ने यूपी का रूख किया है। वहीं प्रदेश में मेमू ट्रेन चलाने की बात रेलवे मंत्रालय से की जा रही है। जल्द ही इसके लिए भी सहमति बन जाएगी। जिससे लाखों लोगों को राहत मिलेगी।

आशा वर्कर को भी दी गई जिम्मेदारी

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में बीते सोमवार से ही प्रदेश में एक्टिव केस कम है और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक होने का क्रम जारी है। प्रदेश में काफी संख्या में प्रवासी कामगार व श्रमिकों की वापसी हुई है। होम क्वारंटीन में रहने वालों की जांच गांव निगरानी व मोहल्ला निगरानी समिति द्वारा की जा रही है। अब इसी कड़ी को और मजबूत करते हुए आशा वर्करों को भी होम कवारंटीन में रहने वाले लोगों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि आशा वर्करों द्वारा अबतक 3 लाख 72 हजार लोगों की जांच की गई है। जांच के दौरान 414 लोगों के अंदर सर्दी, जुखाम, बुखार आदि का लक्षण पाया गया। ऐसे लोगों की रिपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई कर रहा है।

बुधवार तक रेहड़ी पटरी वालों को भी राहत पैकेज दिया जाएगा: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी प्रवासी कामगारों व श्रमिकों का डाटा तैयार किया जाए। सभी की स्किलिंग क्षमता का पूरा ब्यौरा एकत्र किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए राहत पैकेज का उपयोग इसी डाटा के आधार पर करने का निर्देश सीएम योगी ने दिया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री के ऐलान के अगले दिन ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई सैक्टर को दो हजार करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि आवंटित कर दी। अब रहेड़ी पटरी वालों को भी राहत पैकेज के अनुसार आने वाले बुधवार तक धनराशि आवंटित कर दी जाएगी।

मायावती ने कांग्रेस पर साधा निशाना

● कांग्रेस अपनी बसें यूपी भेजने के बजाय पंजाब व चंडीगढ़ भेजे

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

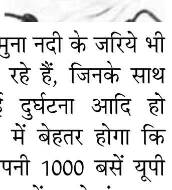

प्रवासी मजदूरों की लगातार हो रही घोर उपेक्षा वह आए दिन दुर्घटना से संबंधित घटनाओं को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में भी काफी दर्दनाक मौतें हो चुकी हैं जो अति दुखद है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि कांग्रेस को अपनी बसें यूपी भेजने के बजाय चंडीगढ़ व पंजाब भेजना चाहिए जिससे यमुना नदी के जरिए घर वापसी कर रहे लोग सुरक्षित घर पहुंच सके।

रविवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट और ट्वीट करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि कांग्रेसी नेताओं को भी सबक सीखना चाहिये क्योंकि पंजाब व चण्डीगढ़ से काफी प्रवासी यूपी के मजदूर लोग, सरकार की अनदेखी व उपेक्षा होने की वजह से, यमुना नदी के जरिये भी घर वापसी कर रहे हैं, जिनके साथ कभी भी कोई दुर्घटना आदि हो सकती है। ऐसे में बेहतर होगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी 1000 बसें यूपी भेजने के बजाए, उन्हें पहले पंजाब व चण्डीगढ़ ही भेज दें, ताकि वे पीड़ित श्रमिकगण यमुना नदी में अपनी जान जोखिम में डालने के बजाए सड़क के जरिये सुरक्षित यूपी पहुँच सकें। इसी प्रकार कांग्रेसी नेता लोग दिल्ली में मजदूरों से मिलने के दौरान यदि प्रवासी मजदूरों की कुछ आर्थिक मदद व खाने आदि की व्यवस्था भी कर देते तो उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिल जाती अर्थात कांग्रेस को उनके दु:ख दर्द को बांटने के साथ.साथ बीएसपी की तरह उनकी कुछ मदद भी जरूर करनी चाहिये।

सड़क हादसे में मृत मजदूरों के परिजनों को 10 लाख मुआवजा दे सरकार: प्रसपा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने औरैया दुर्घटना में हताहत मजदूरों के परिजनों को शीघ्रातिशीघ्र दस लाख रुपये मुआवजा देने की पुरजोर मांग की है । प्रसपा प्रवक्ता व बौद्धिक सभा के अध्यक्ष दीपक मिश्र ने राज्य सरकार पर मजदूरों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार रोज नई घोषणा बिना किसी तैयारी के कर देती है जिससे मजदूरों में भ्रम का फैलना लाज़मी है । बिना किसी देरी के मजदूरों के घर वापसी का समुचित प्रबंध हो ताकि औरैया जैसी दु:खद दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो। प्रसपा कार्यकर्ता पैदल चल कर घर वापसी कर रहे मजदूरों के भोजन, वस्त्र व हवाई चप्पल का प्रबंध करें। प्रसपा ने मजदूरों की मदद के लिए हेल्प लाइन नंबर 7317356789 जारी किया है।

होम क्वेरंटाइन के लिए सभी जिलाधिकारियों एवं सीएमओ को दिशा-निर्देश जारी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कोविड-19 हेतु होम क्वॉरेंटाइन के लिए सभी जिलाधिकारियों एवं सीएमओ को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण को सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की स्वच्छता एवं संदिग्ध रोगियों के होम क्वॉरेंटाइन जैसे महत्वपूर्ण उपायों के द्वारा काफी सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है।

प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा इन उपायों को क्रियान्वित करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। कोविड.19 के रोगियों के प्रबंधन के लिए विभिन्न स्तरों की चिकित्सा इकाइयां नामित की गई हैं, जहां पर इन रोगियों का समुचित प्रबंधन किया जा रहा है। प्रसाद ने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में संदिग्ध अथवा पुष्ट रोगियों के ऐसे संपर्कों जो इस आदेश की शर्तों को पूर्ण करने में सक्षम हो, कोरेंटिन करने का निर्णय लिया गया है। संपर्क एक ऐसा स्वस्थ व्यक्ति हो सकता है, जो एक कोविड.19 संक्रमित व्यक्ति के साथ या दूषित वातावरण में रहा हो, जिससे उस व्यक्ति में कोविड.19 रोग विकसित होने का खतरा बढ़ गया हो। जो व्यक्ति अथवा शर्तों को पूर्ण न कर सकते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से क्वॉरेंटाइन में ही रखा जाएगा। प्रसाद ने सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को शासनादेश के माध्यम से विभिन्न परिस्थितियों, सुविधाओं की उपलब्धता, शर्तों का अनुपालन करने पर 14 दिन के होम क्वॉरेंटाइन का विकल्प प्रदान किये जाने, होम क्वॉरेंटाइन में रखें गए व्यक्तियों, होम क्वॉरेंटाइन में रहने वाले व्यक्ति के परिजनों एवं वातावरण की स्वच्छता के संबंध में भी निर्देशित किया है।

कांग्रेस ने की मजदूरों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार द्वारा मजदूरों के ऊपर हुए बर्बर लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने मांग की है कि राजस्थान सरकार द्वारा यूपी बॉर्डर पर खड़ी 1000 बसों को योगी सरकार तत्काल अनुमति दें ताकि हम प्रवासी मजदूर भाइयों की मदद कर सकें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि यूपी के झांसी, मथुरा, यमुनानगर बॉर्डर पर पुलिस ने मजदूर भाइयों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज किया है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है देश निर्माताओं के ऊपर इस तरीके का बर्बर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को पत्र लिखकर 1000 बसों को चलाने की अनुमति मांगी थी। लेकिन सरकार किसी भी तरह का सहयोग लेने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और आराधना मिश्रा मोना ने सरकार से मांग किया कि प्रदेश में अपने घरों को लौट रहे मजदूरों के लिए परिवहन तत्काल फ्री किया जाए।

प्रतिकूलता से निपटना और उसके आगे देखना ही नेतृत्व होता है

प्रकाश जावडेकर

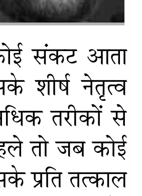

किसी देश पर कोई संकट आता है तो वह उसके शीर्ष नेतृत्व को एक से अधिक तरीकों से परखता है। सबसे पहले तो जब कोई संकट आता है तो उसके प्रति तत्काल प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड 19 के खतरे को बहुत पहले भांप लेने के साथ-साथ सतर्क, निर्णायक कदम उठाने से देश में इस वायरस के प्रसार को धीमा करने में मदद मिली और भारत को कई अन्य देशों से अलग भी खड़ा किया। अब तो प्रधानमंत्री द्वारा की गई देश को महत्वपूर्ण क्षति से बचाने की त्वरित कार्यवाही को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। कहा जाता है कि विपत्ति के दौरान ही लोगों का असली चरित्र सामने आता है। यही बात नेतृत्व पर भी समान रूप से लागू होती है। सामान्य काल में नेतृत्व प्रदान करना भले ही चुनौती न हो मगर कठिनाई के समय ही वह बाकी से अलग होकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता है। दुनिया भर में कोविड 19 महामारी नेतृत्व की परीक्षा ले रही है। इस परीक्षा में भारत और उसके प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल वायरस के खिलाफ एक उत्साही लड़ाई कर रहा हैए बल्कि संकट के बाद की कोविड दुनिया को भी देख रहा है और इसके लिए खुद को सावधानीपूर्वक तैयार कर रहा है ताकि वह अपना सर्वश्रेष्ठ कदम आगे रख सके। आत्मनिर्भर भारत के स्पष्ट आह्वान और उसके बाद पांच दिनों की अवधि में कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं जिन्हें भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद रखा जाएगा। आसन्न संकट से नहीं घबराने के प्रेरक संदेश के साथ ही वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के पुनर्गठन में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहने के संदेश ने हर भारतीय को उत्साह से भर दिया है। भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रत्येक क्षेत्र की कहानी में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गहन सुधार देखा जा सकता है। भारत के विकास के पहिये गरीब, रेहड़ी थाडी वालों (स्ट्रीट वेंडर्स) और प्रवासी मजदूरों के लिए कई उपायों की घोषणा की गई हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से लेकर सभी प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न, मामूली ऋण लेने वाले मुद्रा लाभार्थियों के लिए ब्याज में छूट से लेकर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रारंभिक कार्यशील पूंजी की सुविधा देने, मनरेगा आवंटन को बढ़ावा देने से लेकर स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को सशक्त बनाने तक के उपाय कर के आर्थिक पैकेज ने उन लोगों को मजबूत बनाने पर जोर दिया है जो कोविड19 के आर्थिक परिणामों से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र भारत के विकास के वाहनों में से एक है जो विशेष रूप से इस क्षेत्र की रोजगार की गहन प्रकृति के कारण महत्वपूर्ण है। रियायती ब्याज दरों पर इन उद्यमों को 3 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी, बिना किसी कोलेटरल के अपने आप दिये जाना इन उद्यमों को एक अतिरिक्त खुराक के रूप में हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा में आमूल चूल विस्तार यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी कंपनियां अपने विशिष्ट लाभों को खोने के डर से निरुत्साहित न हों। इन उद्यमों के लिए संदेश है- बड़ा सोचो और बढ़ो।

कई कृषि विशेषज्ञों ने हाल के कृषि सुधार उपायों को स्वतंत्रता आंदोलन के समान माना है। अभी की कृषि विपणन मॉडल ऐसा था कि जो उपभोक्ताओं और किसानों दोनों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा था जबकि बिचौलियों की पौ बारह थी। आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव से किसानों को अपनी उपज जिसे भी वे चाहें को बेचने की स्वतंत्रता मिली है। ये फार्म गेट बुनियादी ढांचे में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश और खेती और उद्योग को एक साथ लाने के लिए दिये गए समर्थन से कृषि को वास्तव में किसानोन्मुख बनाया गया है। याद रखें कि उपरोक्त दो क्षेत्र- कृषि और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम भारत में दो सबसे बड़े रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं। इन दोनों क्षेत्रों में व्यापक सुधार देश के लिए बहुत अनुकूल है।

दूसरी ओर, कोयला, खनन, रक्षा, विमानन और अंतरिक्ष जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सार्वभौमिक सुधारों ने सरकार के सुधारवादी रुझान को दर्शाया है। आरबीआई द्वारा इस साल की शुरुआत में किए गए भारी तरलता उपायों और 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज ने भारत के कोविड बाद के विकास की राह प्रशस्त की है। इस तरह के प्रभावशाली कदमों के बावजूदए कुछ नकारात्मक, कुछ टिप्पणीकार वर्ग और कुछ अन्य राजनीतिक दलों के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया है। सबसे पहले तो वे दावा करते हैं कि सरकार ने लोगों के हाथों में पैसा नहीं रखा है। शायद इन लोगों की याददाश्त थोड़ी कम है। सरकार द्वारा घोषित सबसे पहला राहत पैकेज गरीबों के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण पैकेज का 1.7 लाख करोड़ रुपये का था। यूपीए युग के विपरीत यह सिर्फ एक घोषणा नहीं रहा। अब तक 39 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को लगभग 35,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिल भी चुकी है। इसमें 8 करोड़ से अधिक किसान शामिल हैं जिन्होंने अपने खातों में 2,000 रुपये प्राप्त किए और 20 करोड़ से अधिक जन धन खाताधारी महिलाओं ने सहायता की पहली और दूसरी किस्त प्राप्त की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा कानून के तहत कवर किया जाता है, जिन्हें प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और प्रति परिवार 1 किलो दाल दी जाती है। ये बिना किसी लीकेज के सीधे लोगों तक पहुंच रहे हैं।

यह सही तरीके से सही फैसले लेने की बात भी है। यूपीए की तथाकथित ऋण माफी को हर कोई याद करता है जो किसानों तक किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से नहीं पहुंची बल्कि उसने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। जबकि यहां मोदी सरकार सीधे लोगों तक पहुंच रही है और जांच-परख कर उपाय कर रही है। सरकार के सबसे महत्वपूर्ण कदमों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% से बढ़ाकर 5% करने वाले राज्यों की उधार सीमा को बढ़ाना भी है। यह राज्यों के लिए अतिरिक्त 4 लाख करोड़ रुपये सुनिश्चित करता है।

फिर भी, कुछ टिप्पणीकार हैं जो इसे संघीय विरोधी भावना के विरुद्ध बता रहे हैं क्योंकि सरकार ने इस अतिरिक्त 1.5% (अतिरिक्त 0.5) स्वत: है, को राज्यों के सुधारों को पूरा करने से जोड़ा है। हमें याद रखना चाहिए कि राज्य पहले से ही अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% के हकदार थे और सरकार ने वास्तव में इन सुधारों से अपनी उधार सीमा को बढ़ा दिया है। यह संघवाद की वास्तविक भावना के अनुरूप सुधार को प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा इन सुधारों में से कई बिजली सुधार, व्यापार करने में आसानी, शहरी स्थानीय निकाय सुधार, आदि को सार्वभौमिक रूप से इन्हीं टिप्पणीकारों की मांग थी और वे अब इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। सच्चा नेतृत्व संस्थागत सुधार को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के बारे में होता है। परिवर्तनकारी नेतृत्व वह है जो न केवल तात्कालिक चुनौती से जूझता है बल्कि देश को पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए तैयार करता है। इतिहास ने दिखाया है कि इस तरह के वैश्विक संकट के बाद विश्व व्यवस्था बदल गई है। भारत सौभाग्यशाली है कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। जैसा कि पिछले सप्ताह के कार्यों ने दर्शाया है कि वे अवसर को पूरी तरह से समझते हैं।

(लेखक केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, सूचना और प्रसारण, और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री हैं)

पायनियर
नई दिल्ली, सोमवार, 18 मई 2020

लॉकडाउन से पंजाब को इस साल 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका : अमरिंदर

भाषा। नई दिल्ली

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण इस साल राज्य को 50,000 करोड़ रुपए का न्यूनतम नुकसान होने की आशंका है। राजस्व एकत्र करने के लिए कराधान के संबंध में कुछ कठोर फैसले किए जाने का संकेत दिया। सिंह ने एक साक्षात्कार में कहा कि शुरुआती अनुमान के अनुसार राज्य में करीब 10 लाख नौकरियों का नुकसान होगा और आर्थिक मोर्चे पर राज्य को हर महीने 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।

सिंह ने कहा कि कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि जुलाई और अगस्त में कोरोना वायरस महामारी चरम पर होगी। ऐसे में पंजाब खुद को सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि विदेश से प्रवासियों और भारतीयों की भारी संख्या में वापसी इस बीमारी के प्रबंधन के लिए प्रमुख चुनौती है। मुख्यमंत्री ने कहा, बंद के कारण सिर्फ अप्रैल में हमें अपने अनुमानित राजस्व के 88 प्रतिशत का नुकसान हुआ। त्वरित अनुमानों के अनुसार, हमें हर महीने 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और पूरे वर्ष में न्यूनतम 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। सिंह ने कहा कि वित्तीय स्थिति के अत्यंत गंभीर होने के मद्देनजर उन्होंने पहले ही सभी गैर-अनिवार्य विभागों को खर्चों में कटौती करने और अपनी राशि का विवेकपूर्ण तरीके से प्रबंधन करने के लिए कहा है। उन्होंने नए कराधान उपायों का जिक्र करते हुए कहा, स्वाभाविक रूप से, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमें कुछ कठोर निर्णय लेने होंगे। उन्होंने कहा कि विचार विमर्श जारी है और राज्य विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है तथा अगले कुछ दिनों में कोई निर्णय लेगा।

सिंह ने राज्यों के लिए तत्काल आर्थिक पैकेज की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि परिवहन से आने वाला वैट या उत्पाद शुल्क, उत्पाद एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं मिल रहे हैं। सभी संसाधन सूख गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार कदम नहीं उठाती तो पंजाब का अनुमान है कि आने वाले समय में स्थिति और खराब हो जाएगी। सिंह ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने अब तक राज्यों के लिए कोई राहत पैकेज या राजस्व अनुदान की घोषणा क्यों नहीं की है। हमें न केवल अपने नियमित खर्चों बल्कि कोविड की विशाल चुनौती का चिकित्सा और मानवीय दृष्टिकोण से प्रबंधन करने के लिए धन की आवश्यकता है। हमें तुरंत पैसों की आवश्यकता है। लेकिन यह अभी तक नहीं आ रहा है।

पंजाब द्वारा कोरोना वायरस लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाए जाने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जुलाई -अगस्त में यह महामारी चरम पर पहुंच सकती है और यह सितंबर तक जारी रह सकती है। ऐसे में राज्स सबसे खराब स्थिति की भी तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू में छूट और मामलों में तेजी के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है तथा अभी सबसे बड़ी चुनौती अन्य राज्यों और भारत के बाहर से आ रहे लोगों की बड़ी संख्या है।

बंगलुरू में आशा कार्यकर्ताओं के साथ कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए कर्नाटक के गृहमंत्री वी. सोमन्ना

4500 कैदी स्थानांतरित, बिहार मे किसी भी कैदी को रिहा नहीं किया गयाः अधिकारी

भाषा। पटना

बिहार सरकार ने अत्यधिक भीड़भाड़ वाले जेलों से करीब 4500 कैदियों को कम भीड़भाड़ वाली जेलों में भेज दिया है लेकिन किसी भी कैदी को पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा नहीं किया है। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। यह पूछने पर कि उच्चतम न्याायलय के आदेश के बावजूद किसी भी कैदी को अंतरिम जमानत पर रिहा क्यों नहीं किया गया तो महानिरीक्षक (कारागार) मिथिलेश मिश्रा ने कहा कि कैदियों को पैरोल पर इसलिए नहीं रिहा किया गया कि वे कोरोना वायरस से पीड़ित हो सकते हैं और बाद में जेल में लौटने पर वे महामारी फैला सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने 23 मार्च को सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को निर्देश दिया था कि उच्चस्तरीय समिति का गठन करें जो ऐसे कैदियों या विचाराधीन कैदियों को पैरोल या अंतरिम जमानत देने पर विचार करे जिन्हें सात वर्ष तक की सजा मिली हो। कोरोना वायरस के मद्देनजर जेलों में भीड़भाड़ कम करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय ने ये निर्देश जारी किए थे।

मिश्रा ने कहा, कैदियों को रिहा किए जाने के बाद यह जानना बहुत कठिन होगा कि वे कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आए अथवा नहीं। वे जेल के अंदर काफी सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि पटना के बेउर जेल से कम भीड़ वाली अन्य जेलों में कम से कम 1200 कैदियों को स्थानांतरित किया गया है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा सीतामढ़ी और छपरा के जेलों पांच-पांच सौ कैदी, मोतिहारी जेल से 350 कैदी, औरंगाबाद से 300 कैदी, मधेपुरा और बाढ़ जेल से दो-दो सौ कैदी, मुजफ्फरपुर से सौ कैदी और भभुआ से 70 कैदियों को स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने कहा कि भीड़भाड़ वाली अन्य जेलों से एक हजार कैदियों को भी स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने कहा कि भागलपुर और गया की जेलों से किसी भी कैदी को स्थानांतरित नहीं किया गया है क्योंकि दोनों जेलों में काफी स्थान है।

गुजरात में कोविड-19 मरीज का शव बस अड्डे पर मिला, मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश

भाषा। अहमदाबाद

गुजरात के अहमदाबाद स्थित दानीलिमडा इलाके में एक कोविड-19 मरीज का शव लावारिस हालत में एक बस अड्डे पर मिला। मृतक के परिजन ने इस स्तब्ध करने वाली घटना के लिए अस्पताल और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। सरकारी विज्ञाप्ति के मुताबिक मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) जेपी गुप्ता के नेतृत्व में जांच का आदेश दिया है और 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा है। 67 वर्षीय छगन मकवाना को जिले के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 13 मई को उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी जिसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों को भी पृथक-वास में भेजा दिया गया था। मकवाना के भाई गोविंद ने बताया, उनका शव सुरक्षाकर्मी को शुक्रवार सुबह बीआरटीएस बस अड्डे पर लावारिस हालत में मिला जिसके बाद उसने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर एक अन्य अस्पताल पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को उनकी जेब से एक पर्ची मिली जिसमें बेटे का फोन नंबर था जिसके आधार पर ही परिवार को सूचना दी गई। यह सूचना भी पोस्टमॉर्टम होने के बाद दी गई। उन्होंने कहा, हम पृथक-वास में हैं लेकिन अस्पताल प्रशासन ने हमारे भाई की मौत की जानकारी देना जरूरी नहीं समझा और उनका शव बस अड्डे पर फेंक दिया। पुलिस ने भी लाश पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने से पहले जांच पड़ताल नहीं की।

स्थानीय भाजपा नेता गिरीश परमार ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में जांच का आदेश देने का अनुरोध किया है। परमार ने कहा, अस्पताल प्रशासन ने परिवार के सदस्यों को उनकी स्थिति की जानकारी नहीं दी, जबकि वे घर में ही पृथक-वास में थे। पुलिस ने जांच पड़ताल भी नहीं की। मैंने मुख्यमंत्री को ई-मेल करके मामले की जांच करने के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने का अनुरोध किया है। इस बीच, सिविल अस्पताल में कोविड-19 के लिए विशेष ड्यूटी पर तैनात अधिकारी एमएम प्रभाकर ने कहा, हमने उनके मामले को घर में ही पृथक रहने की श्रेणी में पाया और सभी एहतियात की जानकारी देने के बाद घर जाने को कहा। हम कुछ नहीं कह सकते कि आखिर क्या हुआ क्योंकि वह सिटी बस से घर के लिए रवाना हुए थे।

सहायक पुलिस आयुक्त (के डिवीजन) एमएल पटेल ने कहा कि दुर्घटनावश मौत का मामला दानीलिमडा थाने में दर्ज किया गया है और विभिन्न घटनाओं की कड़ी जोड़ने के लिए जांच की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि मामले में अस्पताल प्रशासन से पूछताछ की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इसी तरह की स्तब्ध करने वाली घटना इस अस्पताल से पहले भी आ चुकी है। एक कैंसर पीड़ित के परिवार ने आरोप लगाया था कि कोविड-19 वार्ड में भर्ती उनके परिजन की मौत की जानकारी आठ दिन तक अस्पताल ने नहीं दी। बाद में कांग्रेस नेताओं के हस्तक्षेप से अस्पताल के मुर्दाघर में उनका शव मिला।

हिमाचल में कोविड-19 का एक और मरीज संक्रमण मुक्त हुआ

शिमला। हिमाचल प्रदेश मे कोविड-19 का एक और मरीज रविवार को संक्रमण मुक्त हो गया। वही, राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक कुल 79 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमण से अब तक चार लोगों की मौत हुई है। विशेष सचिव (स्वास्थ्य) निपुण जिंदल ने कहा कि बैजनाथ अस्पताल मे भर्ती कांगड़ा निवासी के संक्रमण से उबरने के साथ राज्य मे कोविड-19 के इलाजरत मरीजों की संख्या घट कर 31 रह गई है। जिले मे एक मरीज की मौत सहित अब तक 20 मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 44 लोग संक्रमण मुक्त हुए है। इलाजरत मरीजों मे कांगड़ा मे 14, हमीरपुर मे पांच, चंबा और बिलासपुर मे चार-चार, उना और सिरमौर मे दो-दो मरीज शामिल हैं।

बंगाल में बनी रहेगी यथास्थिति : गृह विभाग

कोलकाता। केन्द्र सरकार से लॉकडाउन के संबंध मे रविवार को कोई ताजा दिशा-निर्देश नही मिलने पर पश्चिम बंगाल सरकार ने तय किया है कि वह राज्य में यथास्थिति बनाए रखेगी। गौरतलब है कि कोविड-19 लॉकडाउन 3.0 रविवार मध्यरात्रि को समाप्त हो रहा है। गृह विभाग ने ट्वीट किया है कि राज्य मे यथास्थिति बनाए रखने के संबंध मे विस्तृत दिशा-निर्देश के संबंध मे अधिसूचना सोमवार को जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल मे शनिवार तक कोरोना वायरस संक्रमण से 160 लोगों की मौत हुई है जबकि कम से कम 2,576 लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं।

महिला की मौत, जम्मू कश्मीर में मृतकों की संख्या 13 हुई

श्रीनगर। कोरोना वायरस से संक्रमित एक महिला की रविवार को यहां मौत हो गई जिससे जम्मू कश्मीर मे मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। अधिकारियो ने यह जानकारी दी। सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) श्रीनगर, मे नोडल अधिकारी (कोविड-19) डा. सलीम खान ने बताया कि यहां सीडी अस्पताल में श्रीनगर के हब्बा कदाल क्षेत्र की रहने वाली 29 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। उन्होने बताया कि महिला का पूर्व मे यहां एसएमएचएस अस्पताल मे ईएनटी सर्जन द्वारा लुडविग एनजाइना के लिए ऑपरेशन किया गया था। खान ने बताया, उन्हें वहां सर्जिकल आईसीयू मे स्थानांतरित किया गया था और वह कोरोना वायरस से संक्रमित मिली।

20 लाख प्रवासियों ने गृहराज्य लौटने के लिए पंजीकरण कराया

मुंबई। महाराष्ट्र में 20 लाख प्रवासी श्रमिकों ने अपने गृह राज्य लौटने के लिए राज्य सरकार के समक्ष पंजीकरण कराया है। इनमे से अधिकतर बिहार और पश्चिम बंगाल के रहने वाले है। यह जानकारी महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रविवार को दी। देशमुख ने कहा कि उनके कार्यालय को 20 लाख ऐसे लोगों के आवेदन मिले है जो अपने गृह प्रदेश लौटने को इच्छुक है। उन्होंने कहा, गृह विभाग मे 20 लाख लोगों ने अपने गृह राज्यों मे लौटने के लिए पंजीकरण कराया है। अधिकतर बिहार और पश्चिम बंगाल के रहने वाले है। देशमुख ने पत्रकारों से कहा, समस्या यह है कि बंगाल और बिहार जैसे राज्य रेलगाड़ियों को चलाने के लिए जरूरी मंजूरी नही दे रहे हैं।

150 रुपए के लिए मछुआरे ने साथी की जान ली, गिरफ्तार

मुंबई। महानगर के सेवरी में डेढ़ सौ रुपए को लेकर हुए विवाद मे 22 वर्षीय मुछआरे को अपने साथी की कथित तौर पर हत्या करने के मामले मे गिरफ्तार किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हुसैन शेख (22) ने रियाज शेख (28) की शनिवार को हत्या कर दी जब रियाज ने मछली बिक्री से मिले पैसे मे उसका 150 रुपए का हिस्सा देने से इनकार कर दिया। अधिकारी ने बताया, यह घटना मझगांव के ओरेंज गेट के पास हुई। हुसैन को फेरी वार्फ मे एक नौका से गिरफ्तार किया गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसपर हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

चंडीगढ़ से हिमाचल के 60 छात्रों को वापस लाया गया

धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश)। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच चंडीगढ़ से 60 छात्र रविवार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले मे लौटे। कांगड़ा पहुंचने के बाद छात्रो को स्वास्थ्य जांच के बाद हिमाचल प्रदेश रोडवेज की बसो से उनके घरो तक भेजा गया। छात्रो ने वापसी का बंदोबस्त करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का शुक्रिया अदा किया। हिमाचल प्रदेश से बड़ी संख्या मे छात्र अनेक प्रवेश परीक्षाओ की तैयारी के लिए कोचिंग करने चंडीगढ़ जाते है। वे वहां किराए के कमरो और छात्रावासो मे रहते है। इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने देश के अन्य हिस्सो मे फंसे हुए राज्य के विद्यार्थियो तथा अन्य लोगो को वापस लाने के लिए कार्ययोजना तैयार की है।

संक्रमित सुअरों को मारने के लिए केंद्र से 1.6 करोड़ का पैकेज मांगा

ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के ईस्ट सियांग और पापुम पारे जिलो मे पहले चरण मे अफ्रीकन स्वाइन फीवर (एएफएस) से संक्रमित 4500 सूअरो को मारने के लिए केंद्र सरकार से 1.6 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की मांग की है। एक वरिष्ठ मंत्री ने रविवार को यह जानकारी दी। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री तागे ताकी ने कहा कि राज्य मे अप्रैल मे एएफएस से कई हजार पालतू और जंगली सूअरो की जान गई है।

रांची में हटिया रेलवे स्टेशन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचने के बाद अपने घरों को जाने के लिए बसों का इंतजार करते हुए प्रवासी श्रमिक

संक्रमित नहीं पाए जाने पर ही रिमांड पर भेजे गए कैदियों को जेलों मे रखा जाएगा

भाषा। तिरुवनंतपुरम

केरल की जेलों में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के प्रयास में राज्य सरकार रिमांड पर भेजे गए कैदियों को जेलों में तभी रखेगी जब उनकी कोविड-19 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आएंगी। सरकार पहले ही कई अन्य कैदियों को पैरोल दे चुकी है।

जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रिमांड पर भेजे गए कैदियों के नमूने लिए जाएगे और जांच होने तथा रिपोर्ट आने तक उन्हें या तो अस्पतालों में या जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए पृथक केन्द्रों में रखा जाएगा। उन्होंने कहा, लॉकडाउन के चौथे चरण में हमने राज्य की सभी जेलों में केवल कोविड-19 से मुक्त कैदियों को ही रखने का फैसला किया है।

यदि किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके नमूनों की जांच की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि वह इस वायरस से संक्रमित है या नहीं। ऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में सभी जेलों के 6,250 कैदी और ।,600 से अधिक कर्मचारी परेशानी में पड़ जाएंगे।

जेल और सुधारात्मक सेवाओं के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) संतोष कुमार ने कहा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। उन्होंने कहा इस समय राज्य की लगभग 54 जेलों में 6,250 कैदी बंद हैं। कुमार ने कहा कि जेलों में भीड़ कम करने की योजना है और इसलिए पात्र कैदियों को पैरोल दी गई या अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। जेल विभाग ने सेनिटाइजर और मास्क का उत्पादन कर महामारी से निपटने में सक्रिय रूप से भाग लिया है। उन्होंने कहा, हमने आठ लाख मास्क और 15 हजार लीटर से अधिक सेनिटाइजर का उत्पादन किया है। लॉकडाउन की इस अवधि के दौरान हमने 1.25 करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादों की बिक्री की।

जम्मू-कश्मीर मे भूस्खलन मे मृतक संख्या दो हुई, राजमार्ग पर यातायात बहाल

भाषा। बनिहाल/जम्मू

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में शनिवार शाम जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए भूस्खलन के बाद बचावकर्ताओं को एक शव और मिला है जिसके कारण इस घटना में मरने वाले लोगों की संख्या दो हो गई है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक आठ लोगों को बचाया गया है।

अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले एकमात्र 270 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस मार्ग पर करीब 12 घंटों तक यातायात बंद रहा। यह भूस्खलन रामबन के निकट सीरी में राजमार्ग पर शनिवार शाम करीब सवा छह बजे हुआ। इस दौरान 10 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें अधिकतर ट्रक और मिट्टी की खुदाई करने वाले वाहन थे जो चार लेन की राजमार्ग परियोजना पर काम कर रहे थे। कई वाहन मलबे में दब गए जिससे बड़े पैमाने पर राहत कार्य शुरू किया गया। रामबन के उपायुक्त नाजिम जई खान और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हसीब-उर-रहमान इस अभियान की निगरानी कर रहे थे। भूस्खलन के तुरंत बाद 25 वर्षीय राजकुमार का शव मिल गया था वहीं शनिवार देर रात 19 वर्षीय खालिद हसन का शव मलबे में दबा मिला।

अधिकारियों ने बताया कि दोनों स्थानीय मजदूर थे जो चार लेन परियोजना में काम कर रहे थे। बचावकर्ताओं ने बताया कि जिन आठ लोगों को बचाया गया है उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मलबे के नीचे किसी और के नहीं दबे होने की सूचना के बाद राहत अभियान को बंद कर दिया गया। आवश्यक वस्तुएं लेकर घाटी जा रहे करीब 800 वाहन इस भूस्खलन के बाद राजमार्ग पर फंस गए थे।

मोटरसाइकिल पर पलटा टैंकर, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, तीन घायल

भाषा। बड़वानी (मध्यप्रदेश)

बड़वानी जिले के बिजासन घाट में मुंबईआगरा राष्ट्रीय राजमार्ग3 पर रविवार को तेज गति से जा रहा तेल से भरा एक टैंकर अनियंत्रिक होकर दूसरी ओर से आ रहे मोटरसाइकिल के ऊपर पलट गया, जिससे एक ही परिवार की दो बच्चियों सहित चार लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। इस मोटरसाइकिल पर छह लोग सवार थे, जिनमें एक दंपति एवं उसकी दो बेटियों की मौत हो गई है, जबकि उनकी दो मासूम बेटियां घायल हुई हैं। तीसरा घायल टैंकर चालक है। यह दंपति मजदूर थे।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी जिले के नेवाली ब्लॉक के साकड़ गांव की इस मजदूर दंपति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर उनके बच्चों को कुल 14 लाख रूपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है। बड़वानी जिले के पुलिस अधीक्षक डी आर तेनिवार ने बताया कि मृतकों की पहचान कमल (32), उसकी पत्नी नूरजा(30) एवं उनकी दो बेटियां गोरी (5) और नानी (3) के रूप में की गई है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में कमल की दो अन्य मासूम बेटियों-- गुंजा (दो साल) और गुड़िया (एक साल) के साथसाथ टैंकर चालक भी घायल हो गया। घायलों को सेंधवा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

तेनिवार ने बताया कि हादसे में हताहत हुए सभी लोग बड़वानी जिले के सेंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र के साकड गांव के निवासी थे। कमल अपनी पत्नी एवं चार बच्चियों के साथ मोटरसाइकिल से महाराष्ट्र के पनाखेड़ स्थित ससुराल से अपने घर लौट रहा था। उन्होंने कहा कि तेल से भरा टैंकर मंदसौर से तमिलनाडु जा रहा था। तेनिवार ने बताया कि इस संबंध में सेंधवा ग्रामीण पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और विस्तृत जांच जारी है। इसी बीच, मुख्यमंत्री ने इस मजदूर परिवार में पति-पत्नी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर उसके बच्चों को कुल 14 लाख रूपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही कहा है कि हम उन मासूम बच्चों के संरक्षक हैं तथा उनका पूरा ध्यान रखेंगे।

चौहान ने कहा कि दिए जाने वाली राशि में से एक लाख रूपए बच्चों की तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए तथा 13 लाख की सावधि जमा (एफडी) उनकी पढ़ाईलिखाई सहित भविष्य की अन्य आवश्यकताओं के लिए रहेगी। मुख्यमंत्री ने बच्चों के चाचा राजेश से भी दूरभाष पर चर्चा कर बच्चों की समुचित देखभाल करने के लिए कहा। चौहान ने कहा कि यह अत्यंत दुःखद घटना है।

बीरभूमि में पश्चिम बंगाल के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा और विश्व भारतीय विवि के वाइस चांसलर विद्युत चक्रवर्ती खाद्य सामग्री वितरित करते हुए

चक्रवात अम्फान : ओडिशा के 12 तटीय जिलों को सतर्क किया गया

भाषा। भुवनेश्वर

ओडिशा सरकार ने चक्रवात अम्फान के मद्देनजर किसी भी खतरे से निपटने के लिए अपने 12 तटीय जिलों के प्रशासन को पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निर्देश पर गंजम, गजपति, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, कटक, खुर्दा और नयागढ़ के जिलाधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) पी के जेना ने कहा, इसके अलावा, हम चार तटीय जिलों जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर पर करीबी नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चक्रवाती तूफान की गति पर करीबी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का फैसला स्थिति की समीक्षा के बाद लिया जाएगा।जेना ने कहा कि लगभग 11 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के प्रबंध किए गए है। उन्होंने कहा कि 12 तटीय जिलों में 809 चक्रवात आश्रय स्थल हैं और इनमें से 242 का इस्तेमाल कोरोना वायरस के बीच विभिन्न राज्यों से लौटने वाले लोगों के लिए अस्थाई चिकित्सा शिविरों के रूप में किया जा रहा है। जेना ने कहा, हमारे पास 567 चक्रवात और बाढ़ आश्रय स्थल उपलब्ध हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों को इनमें रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, हमने 7,092 इमारतों की व्यवस्था की है ताकि जरूरत पड़ने पर इनमें भी लोगों को रखा जा सके। उन्होंने कहा, ओडिशा आपदा त्वरित प्रतिक्रिया बल (ओडीआरएएफ), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और दमकलकर्मियों को पहले से ही इन जिलों में भेजा जा चुका है। हम भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय मौसम विभाग और एनडीआरएफ के संपर्क में भी हैं। एनडीआरएफ के महानिदेशक एस एन प्रधान ने कहा कि 10 टीमों को ओडिशा के सात जिलों में भेजा गया है और 10 अन्य को तैयार रखा गया है। राज्य में चक्रवात का प्रभाव कम होने के तुरंत बाद बिजली, पानी की आपूर्ति, सड़कें साफ करने, बचाव और राहत अभियान शुरू करने की व्यवस्था की गई है।अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासियों के ओडिशा लौटने के बारे में जेना ने कहा कि सीमा जांच चौकियों पर जवानों को चक्रवात की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाने को कहा गया है।चक्रवात अम्फान दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर और आसपास मंडरा रहा है। चक्रवात के चलते ओडिशा के कई जिलों और पश्चिम बंगाल के हिस्सों में भीषण बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं।

● एनडीआरएफ के महानिदेशक एस एन प्रधान ने कहा कि 10 टीमों को ओडिशा के सात जिलों में भेजा गया है और 10 अन्य को तैयार रखा गया है

पुरी तट पर चक्रवात अम्फान को लेकर पेट्रोलिंग करते तट रक्षक बल के जवान।

क्विक न्यूज

तीन श्रमिक विशेष ट्रेनों से लगभग चार हजार प्रवासी झारखंड पहुंचे

रांची । कर्नाटक और महाराष्ट्र से 4,088 प्रवासी श्रमिक तीन श्रमिक विशेष ट्रेनों से शनिवार को झारखंड पहुंचे। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार 2,663 प्रवासी कर्नाटक से दो विशेष ट्रेनों से देवघर जिले के जसीडीह रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि,425 प्रवासी श्रमिकों को ला रही तीसरी ट्रेन महाराष्ट्र के रत्नागिरि से कोडरमा रेलवे स्टेशन पहुंची। इसमें कहा गया है कि राज्य में पहुंचे लोगों की जांच की गई और उन्हें भोजन उपलब्ध कराया गया। इसके बाद उन्हें पृथक केन्द्रों में भेजा गया।

कर्मी के संक्रमित होने के बाद मुंबई के एसीपी पृथक-वास में

मुंबई। मुंबई पुलिस के एक अतिरिक्त आयुक्त (एसीपी) को एहतियाती तौर पर पृथक-वास में भेज दिया गया है। इससे पहले उनके रीडर के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी।एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रीडर निरीक्षक स्तर के अधिकारी है और उनके मंगलवार को इस घातक वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। उन्हें सांता क्रूज ईस्ट के एक पुलिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी ने बताया कि रीडर के संक्रमित होने के बाद एसीपी सहित चार लोगो को एहतियात बरतते हुए दो हफ्तों के लिए पृथक-वास में भेज दिया गया है। जिस व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, उन्होंने कहा कि उनमें इसका कोई लक्षण नही दिख रहा था लेकिन उनके वरिष्ठ अधिकारी ने जांच कराने को कहा। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने पर वह चकित रह गए।

महाराष्ट्र के छात्रों ने रेलवे पर कुप्रबंध का आरोप लगाया

मुंबई। दिल्ली मे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे महाराष्ट्र के करीब 1000 छात्रों ने रविवार को आरोप लगाया कि रेलवे के कुप्रबंध से उन्हे असुविधा हुई। कई छात्रो ने एक वीडियो साझा कर दावा किया है कि रेलवे ने दिल्ली से मुंबई के बीच एक ट्रेन चलाई लेकिन संवाद और स्वच्छता की कमी के कारण उन्हे परेशानियां हुई।दिल्ली मे यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही स्नेहल चव्हाण ने कहा, यह एक विशेष ट्रेन थी, हमें सामान्य डिब्बे मे बैठने के लिए कहा गया, जिसे ठीक से साफ भी नही किया गया था।

अंतरिक्ष रणनीतिक क्षेत्र है, उचित सुरक्षा उपायों की जरूरत : के. कस्तूरीरंगन

भाषा। बेंगलुर

वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष क्षेत्र और इसरो को निजी क्षेत्रों के लिए खोले जाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है लेकिन संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को गलत हाथों में पड़ने से रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की मांग की है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन ने 1963 में शुरू भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगामी वर्षों में अगले चरण तक पहुंचाने के लिए इस कदम को बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक करार दिया। उन्होंने रेखांकित किया कि यह क्षेत्र भारत की आर्थिक क्षेत्र की महत्वकांक्षाओं को पूरा करने में अहम जरिया है। कस्तूरीरंगन ने कहा, इसलिए हमें उन रास्तों को भी देखना चाहिए जिससे दायरे और पैमाने के संदर्भ में इस क्षेत्र का विस्तार किया जा सके। उल्लेखनीय है कि कस्तूरीरंगन योजना आयोग के भी सदस्य थे जिसे सरकार ने अब भंग कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में अंतरिक्ष संबंधी सेवाओं की बड़ी मांग है जो उपग्रहों को लॉन्च करने और उनके निर्माण के क्षेत्र में किफायती सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसरो के पूर्व प्रमुख जी माधवन नायर ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों में निजी भागीदारी का स्वागत किया लेकिन कहा कि कुछ नीतिगत मामलों पर सतर्कता से विचार किया जाना चाहिए। नायर ने कहा, पहली बात, हमारे पास राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून होना चाहिए जिसमें जिम्मेदारी और जवाबदेही परिभाषित हो। संवेदनशील और जोखिम वाली तकनीक गलत हाथों में नहीं पड़े यह सुनिश्चित करने के लिए एक बेहतर नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए। उनके मुताबिक भारत में साध्य एयरोस्पेस उद्योग नहीं होने के बावजूद इसरो ने अपने कार्यक्रमों में औद्योगिक भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल की। नायर ने कहा, इसरो के 60 प्रतिशत बजट व्यय उद्योगों के जरिए होना इसका सबूत है। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि अंतरिक्षे से अधिक राजस्व प्राप्ति या लाभ नहीं होगा। इसलिए कितने यह चुनौती स्वीकार करेंगे? अंतरिक्ष अन्वेषण अभी भी जटिल है क्योंकि इसमें लाभ नहीं होता और यह दीर्घकालिक निवेश है। नायर ने कहा, संवेदनशील अंतरराष्ट्रीय नियामकों जैसे मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (एमटीसीआर) और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून को ध्यान में रखकर इसे लागू किया जाना चाहिए। कस्तूरीरंगन के मुताबिक, यह भविष्य को देखने का बहुत ही संतुलित तरीका है।

बांग्लादेश, रूस और यूक्रेन में फंसे पूर्वोत्तर के 400 से अधिक लोगों की वापसी होगी

अगरतला। त्रिपुरा के मंत्री ने बताया कि बांग्लादेश, रूस और यूक्रेन में फंसे पूर्वोत्तर के 400 से अधिक लोगों की वापसी के लिए केंद्र सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर के इन लोगों में 87 त्रिपुरा के रहने वाले हैं। राजधानी स्थित सचिवालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए त्रिपुरा के शिक्षामंत्री रतन लाल नाथ ने बताया कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते लागू लॉकडाउन की वजह से फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ समन्वय कर सभी कदम उठा रहा है। नाथ ने शनिवार को बताया कि ढाका स्थित भारतीय उच्चायुक्त बांग्लादेश में फंसे त्रिपुरा के 53 लोगों की वापसी की व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार से समन्वय कर रहे हैं। मंत्री ने बताया कि त्रिपुरा के 25 निवासियों सहित पूर्वोत्तर के 198 लोग यूक्रेन में फंसे हैं, जिन्हें वापस लाया जाएगा।

नर्सें नौकरी छोड़कर घरों के लिए रवाना हुईं

भाषा। कोलकाता

बंगाल का स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र संकट की स्थिति में है क्योंकि निजी अस्पतालों से 300 से अधिक नर्सें नौकरी छोड़कर मणिपुर समेत देश के अन्य हिस्सों में स्थित अपने घरों के लिए निकल गई हैं। कोलकाता के 17 निजी चिकित्सा संस्थानों की संस्था दी एसोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया (एएचआईई) ने मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को पत्र लिख इस संकट को दूर करने के लिए दखल की मांग की है। निजी अस्पतालों के सूत्रों ने बताया कि इस हफ्ते की शुरुआत में कम से कम 185 नर्सें मणिपुर के लिए निकल गईं। इसके बाद, शनिवार को कुल 169 नर्सें मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा और झारखंड के लिए रवाना हो गईं। एएचआईई के अध्यक्ष प्रदीप लाल मेहता ने अपने पत्र में कहा, वे क्यों छोड़कर जा रही हैं, इसका सही-सही कारण तो हमें नहीं पता लेकिन जो नर्सें अब भी यहां हैं उनका कहना है कि इस मणिपुर सरकार उन्हें घर वापसी के लिए लुभावने प्रस्ताव दे रही है। हालांकि मणिपुर के मुख्यमंत्री नांगथोमबम बीरेन सिंह ने फेसबुक पोस्ट पर इस दावे को खारिज किया और कहा, राज्य ने ऐसा कोई परामर्श जारी नहीं किया है। हम किसी को भी लौटने को नहीं कह रहे। हमें उन पर गर्व है कि वे कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में मरीजों की सेवा कर रही हैं। उन्होंने वीडियो संदेश में कहा, हमने उन्हें पहले ही कहा है कि कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने पर हम उन्हें मुआवजा और ईनाम देंगे। लेकिन अगर नर्सें और चिकित्सक जहां काम कर रहे है वहां उन्हें ठीक नहीं लग रहा है तो यह उनका फैसला है। मैं उन पर वहां बने रहने के लिए दबाव नहीं बना सकता।

पेज एक का शेष

लॉकडाउन-4...

लिया है। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दिया गया है। बहरहाल गृह मंत्रालय ने कहा कि पूरे देश में 65 साल से अधिक के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल के कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतों के अलावा घरों में ही रहने की सलाह दी जाती है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, सिगरेट पीना और पान खाना पूरे देश में प्रतिबंधित रहेगा। सभी रेस्टोरेंट को अपनी किचेन सर्विस चलाने तथा खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी गई है। केवल रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों और सरकारी दफ्तर के परिसरों में ही रेस्टोरेंट और कैंटीन को पूरी तरह से चलाने की अनुमति दी जाएगी। सिनेमा हाल, शॉपिंग माल, जिम, बार 31 मई तक बंद रहेंगे। स्टेडियम और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स को खोलने की अनुमति है लेकिन बगैर दर्शकों के। अगले नोटिस तक सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभाओं पर रोक जारी रहेंगे तथा धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे लेकिन उनके अपने रीति रिवाज जारी रहेंगे। शादियों में 50 तथा शोक सभाओं में 20 से ज्यादा लोग भाग नहीं ले सकेंगे। सैलूनों को खोले जाने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के सख्ती से पालन के साथ प्राइवेट समेत सभी दफ्तरों को खोलने की मंजूरी दे दी गई है और मैनेजरों से कहा गया है कि वे बाथरूम, दरवाजों, दरवाजों के हैंडलों की नियमित अंतराल पर साफ सफाई तथा कार्यस्थल एक साथ कर्मचारी इकट्ठा न हो यह सुनिश्चित करेंगे। ऑफिस मैनेजरों से यह भी कहा गया है कि वे थर्मल स्क्रीनिंग तथा प्रत्येक जरूरी स्थानों की सफाई और कर्मचारियों के लिए अलग अलग काम के घंटे निर्धारित करें जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिक संख्या में कर्मचारी इकट्ठा न हों। सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के साथ सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है और राज्यों से कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें दुकान में एक बार में पांच से ज्यादा ग्राहक न हों।

मनरेगा को...

लिए मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। यह बजट में आवंटित 61,000 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त है। उन्होंने कहा कि इससे कुल मिलाकर 300 करोड़ दिहाड़ियों के बराबर रोजगार का सृजन होगा। सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण कर्ज की किस्तें चुकाने में अपने को असमर्थ पा रही कंपनियों पर एक साल तक दिवाला कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत एक साल तक कोई नई दिवाला कार्रवाई शुरू नहीं होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही, कोरोनो वायरस से संबंधित ऋण को डिफ़ॉल्ट या चूक की परिभाषा से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि लघु, सूक्ष्म एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) उपक्रमों के लाभ के लिए दिवाला शोधन प्रक्रिया शुरू करने के लिए फंसे कर्ज की न्यूनतम राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिये अध्यादेश लाया जायेगा। उन्होंने कंपनी कानून के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को गैर-आपराधिक बनाये जाने की भी घोषणा की। इसके तहत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के बारे में जानकारी देने में चूक, निदेशक मंडल की रिपोर्ट अपर्याप्त होने, बाजार को सूचना देने में देरी और सालाना आमसभा में देरी समेत कई प्रक्रियात्मक चूकें तथा मामूली तकनीकी दिक्कतें शामिल हैं। अर्थ दंड या हर्जाने के साथ समाधान योग्य उल्लंघनों में अधिकांश को आंतरिक न्याय निर्णय प्रक्रिया (आईएएम) के तहत रखा जाएगा। इस संबंध में अध्यादेश जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंपनी कानून के तहत सात समाधान योग्य अपराधों को एक साथ हटाया जायेगा और इनमें से पांच को वैकल्पिक नियमों के तहत रखा जाएगा। इसके अलावा, सरकार ने कंपनियों को सीधे विदेशी बाजार में प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां, जो शेयर बाजारों में गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर सूचीबद्ध कराती हैं, उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों के रूप में नहीं माना जायेगा। वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए एक अनुकूल नीति लाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके तहत रणनीतिक क्षेत्रों को परिभाषित किया जाएगा, जिनमें चार से अधिक सार्वजनिक उपक्रम नहीं होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में जनहित में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की मौजूदगी की जरूरत है, उन्हें अधिसूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रणनीतिक क्षेत्रों में कम से कम एक सार्वजनिक उपक्रम होगा। इसमें निजी क्षेत्र को भी अनुमति होगी। वहीं अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बेकार जाने वाली प्रशासनिक लागत को कम करने के लिए रणनीतिक क्षेत्रों में सिर्फ एक से चार सार्वजनिक उपक्रम होंगे। शेष का निजीकरण-विलय किया जाएगा और उन्हें होल्डिंग कंपनी के तहत लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों की मांग को स्वीकार करते हुए चालू वित्त वर्ष (2020-21) के लिये कुल कर्ज उठाने की उनकी सीमा को तीन से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। अभी तक राज्य के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के तीन प्रतिशत तक ही बाजार से कर्ज ले सकते थे। इस कदम से राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त धन उपलब्ध होगा। राज्यों के लिये 2020-21 के दौरान उधार जुटाने की पहले से स्वीकृत कुल सीमा 6.41 लाख करोड़ रुपये (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत) है। राज्यों ने अब तक अधिकृत सीमा का केवल 14 प्रतिशत उधार लिया है। 86 प्रतिशत अधिकृत कर्ज सीमा को अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है। उन्होंने कर्ज की सीमा बढ़ाने का ब्योरा देते हुए कहा कि अतिरिक्त उधार की छूट विशिष्ट सुधारों से जुड़ी होंगी। तीन प्रतिशत की सीमा से ऊपर उधार की सीमा में 0.50 प्रतिशत की वृद्धि बिना शर्त की जा सकेगी। इसके अलावा 0.25-0.25 प्रतिशत की चार किस्तों में कुल मिला कर एक प्रतिशत बढ़ा हुआ कर्ज स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट, तुलनीय और व्यवहार्य सुधारों से जुड़ा हुआ होगा। यदि चार सुधारों में से तीन के लक्ष्यों को पा लिया जाता है तो और 0.50 प्रतिशत कर्ज जुटाने की छूट होगी।' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनो वायरस महामारी के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को राहत देने के लिये सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 10 प्रतिशत यानी 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की इस सप्ताह की शुरुआत में घोषणा की थी। इसमें 1.7 लाख करोड़ रुपये का पूर्व में घोषित पैकेज शामिल है। इसके तहत गरीबों को खाद्यान्न और मुफ्त रसाई गैस के अलावा उनके खातों में तीन माह तक नकदी का स्थानांतरण शामिल है। साथ ही इसमें रिजर्व बैंक द्वारा मार्च से किए गए 8.01 लाख करोड़ रुपये की तरलता के उपाय और महामारी से निपटने को स्वास्थ्य क्षेत्र को किया गया 15,000 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है।

नाटक कर...

के साथ बातचीत किए जाने का जिक्र कर रही थीं। उन्होंने सवाल किया कि वे हमें ड्रामेबाज कह रहे हैं। कल प्रवासियों को रोककर और सड़क पर उनके साथ बातचीत करके और उनका समय बर्बाद करने से क्या हुआ? क्या वे ड्रामेबाज नहीं हैं?' उन्होंने कहा कि इसके बदले वे पैदल ही अपने घर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोककर और उनसे बातचीत कर उनके दुखों को बढ़ा रहे हैं। बेहतर होता कि वे उनके साथ-साथ पैदल चलते और उनके सामान या उनके बच्चों को भी ढोते। वित्त मंत्री ने कहा कि इस हफ्ते की शुरुआत में कांग्रेस ने कहा था कि सरकार का आर्थिक पैकेज प्रधानमंत्री द्वारा देश से किए गए वादे से काफी दूर है। उन्होंने इसे 'जुमला पैकेज' करार दिया था। उन्होंने कहा, 'मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अनुरोध करती हूं कि हम जिम्मेदारी से बोलें और अपने प्रवासी कामगारों के साथ अधिक जिम्मेदारी से पेश आएं।' सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद कहा कि सरकार इस मुद्दे के हल के लिए कांग्रेस सहित सभी दलों से सहयोग मांगेगी।

वित्त मंत्री...

निशाना साधा और कहा कि देश को वित्त मंत्री से कुछ गंभीरता की उम्मीद है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'कथनी और करनी' एक समान रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम उपक्रमों तथा गरीबों के हाथों में पैसे देने की घोषणा की जानी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था में फिर से नयी जान आ सके। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना और लोगों को केवल ऋण दिए जाने के बीच अंतर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शर्मा ने प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए पैकेज पर बहस के लिए वित्तमंत्री को चुनौती दी। शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, 'सरकार का आर्थिक पैकेज सिर्फ 3.22 लाख करोड़ रुपये का है और यह भारत की जीडीपी का सिर्फ 1.6 प्रतिशत है और यह 20 लाख करोड़ रुपये नहीं है, जैसा प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी।' उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार की योजना के अभाव में सड़कों पर पैदल चलने के लिए मजबूर प्रवासियों की दुर्दशा पर सरकार को देश को जवाब देना चाहिए।

देश में...

5012 लोग ठीक हुए हैं। बीते 24 घंटे में आंध्र प्रदेश में कोरोना के 25 नए केस सामने आए हैं जिसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या 2,230 हो गई है। दिल्ली में कोरोना की वजह से अब तक 148 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 422 नए केस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में रविवार को कोरोना संक्रमण के 213 नए मामले आने के साथ ही राज्य में इस संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़कर 4353 हो गई है। रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में अभी 1805 कोरोना मरीज सक्रिय हैं। दुनियाभर में कोरोना की वजह से अब तक तीन लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

राष्ट्रपति भवन...

एसीपी (58) राष्ट्रपति भवन पुलिस लाइंस में तैनात थे, जो राष्ट्रपति भवन के मुख्य क्षेत्र से दूर है, जहां राष्ट्रपति का आवासीय परिसर है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि एसीपी को 13 मई को पृथक किया गया था। उनके संपर्क में आये पांच अन्य कर्मियों को भी एहतियात के तौर पर अलग रखा गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उनकी रिपोर्ट के बारे में हमें आज सूचना मिली है। उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई है लेकिन उनमें संक्रमण के लक्षण नजर नहीं आ रहे। राष्ट्रपति भवन परिसर में एसीपी की ड्यूटी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाने एवं उनके प्रबंधन संभालने की है।

यूपी की...

में आए 14 अन्य कैदियों को अलग रखा गया है। उन्होंने बताया कि उस बैरक की देखभाल कर रहे करीब 13 जेल अधिकारियों की जांच रिपोर्ट में संक्रमण नहीं मिला अब हम राज्य के सभी कारागारों में रैंडम सैंपलिंग करा रहे हैं। कुमार ने बताया कि राज्य में इस वर्ष कुल 71 कारागारों में 94 हजार से ज्यादा कैदी रखे गए हैं। अब तक 16000 से ज्यादा बंदियों को जमानत या पैरोल पर छोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि कैदियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए इच्छुक कैदियों को प्राणायाम सिखाया जा रहा है और काढ़े का सेवन कराया जा रहा है। कुमार ने बताया कि कारागारों में जहां तक मुमकिन हो आपस में दूरी रखने के नियम का पालन कराया जा रहा है। हालांकि राज्य की जेलों में 60000 कैदियों को ही रखने की क्षमता है, मगर इस वक्त उनमें 94000 कैदी मौजूद हैं। क्षमता से ज्यादा कैदी रखने से समस्या उत्पन्न हो रही है।

हिंसा पर...

भेजे जाने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन किया। वहीं गुजरात में राजकोट के पास रविवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवासी मजदूरों ने तत्काल गृह राज्य भेजे जाने का प्रबंध किए जाने की मांग करते हुए पुलिस पर पत्थर फेंके और वाहनों को क्षतिग्रस्त किया। पुलिस ने कहा कि अहमदाबाद से करीब 215 किलोमीटर दूर राजकोट के पास शापर इलाके में हुई इस घटना में कुछ पुलिसकर्मियों समेत एक स्थानीय पत्रकार भी घायल हो गया। राजकोट (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक बलराम मीणा ने कहा कि घटना की वीडियो फुटेज के जरिए पहचान करने के बाद एक उकसाने वाले व्यक्ति समेत 25 प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'स्थानीय प्रशासन से अपने गृह राज्य भेजे जाने का इंतजाम किए जाने की मांग करते हुए प्रवासियों का एक प्रदर्शनकारी समूह उग्र हो गया और उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों को क्षतिग्रस्त किया।' मीणा ने कहा कि दंगा करने के आरोप समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

भारत की...

बुनियादी ढांचे में काफी सुधार किया है।संयोग से, चीनी हेलीकॉप्टरों ने इस साल 5 और 6 मई को संघर्ष के दौरान पूर्वी लद्दाख में एलएसी के करीब उड़ान भरी थी। भारतीय वायुसेना के एसयू-30 फाइटर जेट्स ने भी इस क्षेत्र में उड़ान भरी थी। हालांकि, दोनों पक्षों ने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया। दोनों देशों के बीच एक समझौता है कि दोनों के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट एलएसी से कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी बनाए रखेंगे। इस बीच, कुछ दिन पहले ही खत्म हुए गतिरोध के मद्देनजर भारत लद्दाख में कड़ी नजर रखे हुए है। चीन ने पैंगोंग झील पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ा दी है और भारतीय सेना ने भी एहतियाती कदम उठाए हैं। हालांकि सेना ने कहा कि उसने वहां अधिक सैनिकों को नहीं उतारा है। इसके अलावा, सुरक्षा एजेंसियां लद्दाख में गालवान नदी के पास एलएसी के पास अपने क्षेत्र में चीनी गतिविधियों की निगरानी कर रही हैं। सूत्रों ने कहा कि चीनी सेना ने यहां तंबू गाड़ दिए हैं। सेना प्रमुख एमएम नरवाणे ने हाल ही में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष के बारे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिंगपिंग ने अपने दो अनौपचारिक शिखर सम्मेलनों के दौरान रणनीतिक दिशानिर्देशों के अनुसार मुद्दों को स्थानीय स्तर पर हल किया था।

मुठभेड़ में...

तीन मंजिला मकान के मलबे में सुरक्षाबल तलाशी अभियान चला रहे हैं। जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक मुकेश सिंह ने जम्मू में संवाददाताओं से कहा, हमने मुठभेड़ स्थल से अब तक एक आतंकवादी का शव बरामद किया है, जिसकी पहचान ताहिर अहमद भट के रूप में हुई है। वह दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले के मलंगपुरा गांव का रहने वाला था। उन्होंने कहा, वह हिज्बुल मुजाहिदीन के नवनियुक्त सरगना सैफुल्ला का करीबी सहयोगी था और उसे चिनाब घाटी क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को नए सिरे से तेज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सिंह ने उसके मारे जाने को हिज्बुल के लिए एक बड़ा झटका और सुरक्षाबलों के लिए बड़ी सफलता करार देते हुए कहा कि मारा गया आतंकवादी उस समूह का हिस्सा था, जिसने पिछले साल अप्रैल में किश्तवाड़ जिले में आरएसएस के एक पदाधिकारी और उनके पीएसओ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अधिकारी ने बताया कि वह एक आईईडी बनाने में भी शामिल था, जिसका इस्तेमाल जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले साल मार्च में सीआरपीएफ के एक काफिले पर नाकाम हमले में किया गया था। सिंह ने कहा कि भट के मारे जाने से चिनाब घाटी में आतंकवाद के फिर से सिर उठाने को एक बड़ा झटका लगेगा। डोडा जिले को एक बार फिर से आभासी तौर पर आतंकवाद से मुक्त करा लिया गया है और सुरक्षाबलों पर हमले की आतंकवादियों की योजना नाकाम कर दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मारे गए आतंकवादी के पास से जब्त एके राइफल वही हथियार है जिसे आतंकवादी आरएसएस पदाधिकारी एवं उनके पीएसओ की हत्या के बाद लेकर भाग गए थे। मुठभेड़ के बारे में उन्होंने कहा कि गांव के एक मकान में हिज्बुल के कमांडर की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद शनिवार देर रात एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि यह गांव वाहन चलने योग्य सड़क से करीब छह घंटे की पैदल यात्रा की दूरी पर है।

चीन छोड़...

घुटनों और पीठ दर्द से राहत देने वाले और झटकों के खिलाफ जोड़ों और मांसपेशियों की सुरक्षा करने वाली जूते की एक अग्रणी है। यह ब्रांड 80 से अधिक देशों में बेचा जाता है और दुनिया भर में 10 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं। यह 2019 में भारत में लॉन्च किया गया था और यह 500 से अधिक शीर्ष खुदरा स्थानों और ऑनलाइन पर उपलब्ध है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई राज्य मंत्री उदयभान सिंह ने कहा, हम बहुत खुश हैं। कासा एवरेज जीएमबीएच से निवेश भारत आ रहा है। जो इतने सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। चीन से विशेष रूप से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। इराट्रिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और सीईओ आशीष जैन ने कहा कि हम इस सहयोग से 10,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन करने में उत्तर प्रदेश सरकार की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कंपनी को हर तरह से सहयोग करेगी उसे किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होने देगी।

अमेरिकी कंपनियों...

उन्हें नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास इकाई लगाने की पेशकश की है ताकि यहां से उन्हे अपने काम करने के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो सके। उम्मीद है जल्द ही उक्त 100 अमेरिकी कंपनियों में से ज्यादातर अपनी इकाई यहां स्थापित करेगी।

पायनियर
नई दिल्ली, सोमवार, 18 मई, 2020

बुंदेसलीगा बहाल होने पर स्काई जर्मनी पर रिकार्ड दर्शकों ने देखे मैच

बर्लिन। खाली स्टेडियम में दर्शकों के बिना शनिवार को शुरू हुई बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग को जर्मनी में टीवी पर 60 लाख से ज्यादा दर्शकों ने देखा जो प्रसारक स्काई के लिए नया रिकार्ड है। विशेषज्ञ वेबसाइट डीडब्ल्यूडीएल डाट डीई ने आंकड़े बताए है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते दो महीने के ब्रेक के बाद शुरू हुई जर्मन लीग को जर्मनी में सबस्क्राइब टीवी चैनलों में 36.8 लाख लोगों ने देखा। शनिवार को हुए लीग राउंड के मैचों के आम दर्शक देखने से ज्यादा संख्या में थे।

गले मिलने और चुंबन लेने की घटनाओं के बाद बुंदेसलीगा में बरती जा सकती है सख्ती

बर्लिन। जर्मनी के एक वरिष्ठ राजनेता ने उम्मीद जताई कि बुंदेसलीगा गोल का जश्न मनाने को लेकर नियमों को सख्ती से लागू करेगा क्योंकि इस सप्ताहांत फिर से शुरू हुई इस लीग में खिलाड़ियों ने पहले दिन गले लगकर और चुंबन लेकर नियमों का खुलकर उल्लंघन किया। जर्मन लीग कोरोना वायरस के कारण दो महीने तक ठप्प रहने के बाद शनिवार को फिर से शुरू हुई तथा क्लबों ने जर्मन सरकार के स्वच्छता को लेकर अपनाए गए नियमों का पालन करने पर सहमति जताई थी।

कोविड-19 के बाद पहले एलपीजीए गोल्फ टूर्नामेंट की विजेता रहीं पार्क हुन

सोल। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के बाद खेला गया गोल्फ टूर्नामेंट रविवार को समाप्त हुआ जो दर्शकों के बिना खेला गया और इस महिला पीजीए प्रतियोगिता में कड़े सुरक्षा संबंधित दिशानिर्देशों का पालन किया गया। कोरियाई एलपीजीए चैम्पियनशिप में दुनिया की शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में से तीन गोल्फर शामिल थी। इस प्रतियोगिता पर दुनिया भर की निगाहें लगी थी, जिसके प्रसारण अधिकार अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया को बेचे गए।

अंकिता और शरण को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित करेगा एआईटीए

नई दिल्ली। अखिल भारतीय टेनिस महासंघ (एआईटीए) एशियाई खेलों के पदक विजेता अंकिता रैना और दिविज शरण को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित करेगा जबकि पूर्व डेविस कप कोच नंदन बाल के नाम की सिफारिश ध्यानचंद पुरस्कार के लिए करेगा। अंकिता (27 वर्ष) ने 2018 एशियाई खेलो मे महिला वर्ग का कांस्य पदक जीता था, उन्होंने फेड कप में भी शानदार प्रदर्शन दिखाया और भारत के पहली बार विश्व ग्रुप प्ले आफ के लिए क्वालीफाई करने में अहम भूमिका अदा की थी।

अफरीदी को गंभीर, युवी व भज्जी ने कोसा

चैरिटी अपील पर अब खेद जताया, कहा फिर कभी नहीं करेंगे

भाषा। नई दिल्ली

शाहिद अफरीदी के भारत के खिलाफ दिए गए बयान पर निराशा व्यक्त करते हुए हरभजन सिंह ने रविवार को कहा कि यह पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दोस्ती के लायक नहीं है जबकि युवराज सिंह ने उसकी चैरिटी की मदद के लिए अपील करने पर खेद जताया। पिछले महीने हरभजन और युवराज ने शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के सहयोग के लिए वीडियो पोस्ट किया था। यह फाउंडेशन कोविड-19 महामारी से प्रभावित लोगों के लिए धनराशि जुटा रहा था। हरभजन ने पीटीआई-भाषा से कहा, वह अफरीदी था जिसने मुझसे और युवी से अपने फाउंडेशन के सहयोग के लिए वीडियो पोस्ट करने को कहा था क्योंकि महामारी का प्रकोप धर्म या सीमाएं नहीं देखता। लेकिन उसने फिर से भारत विरोधी टिप्पणियां की हैं। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने उसे दोस्त तक कहा था। वह इस तरह का इंसान नहीं है कि जिसे दोस्त कहा जा सकता है। युवराज ने भी ट्वीट करके इसी तरह के विचार व्यक्त किए। शाहिद अफरीदी की हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में टिप्पणी से वास्तव में निराशा हुई। एक जिम्मेदार भारतीय के रूप में जो देश की तरफ से खेला है, मैं कभी इस तरह के शब्दों को स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने मानवता के लिए आपके कहने पर अपील की लेकिन अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। अफरीदी ने एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धार्मिक भेदभाव करने के आरोप लगाए थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर चलन में आ गया था। हरभजन से पूछा गया कि उन्हें लगता है कि भारत और पाकिस्तान रिश्तों की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए क्या अफरीदी के एनजीओ के लिए अपील करना गलत था, उन्होंने कहा, हमारा इरादा अच्छे कार्य का समर्थन करना था लेकिन इसके बाद मैंने सुना कि उसने मेरे देश के लिए गलत बयानबाजी की है।

मोदी पर बयान के लिए गंभीर ने लताड़ा

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए रविवार को कड़ी आलोचना की। अफरीदी सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए दिख रहे है। गंभीर ने इस बार भी पिछली बार की तरह अफरीदी को लताड़ा जो पहले भी कई बार भारत के खिलाफ बयान दे चुके है। इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने अफरीदी के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए ट्वीट किया, पाकिस्तान के पास सेना के सात लाख जवान है जिनके 20 करोड़ लोगों का समर्थन है, यह कहना है 16 साल के शाहिद अफरीदी का। फिर भी 70 साल से कश्मीर की भीख मांग रहे है। उन्होंने लिखा, अफरीदी, इमरान (खान) और (कमर जावेद) बाजवा जैसे जोकर भी पाकिस्तान के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगल सकते है लेकिन आखिर तक उन्हें कश्मीर नहीं मिलेगा, याद है न बांग्लादेश? गंभीर और अफरीदी के बीच क्रिकेट खेलने के दिनों से ही कड़ी प्रतिद्वंदिता रही है, दोनों कई बार मैदान में एक दूसरे से भिड़ चुके है। 2007 में पाकिस्तान के भारत के दौरे के दौरान गुवाहाटी में वनडे मैच के दौरान दोनों के बीच शाब्दिक जंग छिड़ गई थी। पूर्व पाकिस्तानी आल राउंडर ने अपनी आत्मकथा द गेमचेंजर में भी गंभीर के मैदानी रवैए के बारे में लिखा था।

तेंदुलकर को चुनौती देकर बुरे फंसे युवराज

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय हरफनमौला युवराज सिंह, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को सोशल मीडिया पर एक चुनौती देकर बुरी तरह फंस गए। युवराज ने बल्ले को आड़ा करके गेंद को लगातार मारते हुए ट्विटर पर वीडियो पोस्ट किया और तेंदुलकर के साथ रोहित शर्मा और हरभजन सिंह को ऐसा करने की चुनौती दी। मास्टर ब्लास्टर ने इस चुनौती ना सिर्फ स्वीकार किया बल्कि आंखों पर काली पट्टी बांध कर इसे आराम से पूरा किया। उन्होंने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर इसका वीडियो पोस्ट किया। इस चुनौती को करते हुए वह कह रहे थे, युवी, तुमने मुझे बहुत आसान विकल्प दिया था, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा मुश्किल विकल्प दे रहा हूं। मैं इसके लिए तुम्हे पूरा लगा हूं मेरे दोस्त। इसे मेरे लिए करके दिखाओ। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वापस चुनौती दे रहा हूं लेकिन ऐसी पट्टी को लगाकर करना। तेंदुलकर के इस कारनामे से युवराज चौक गए।उन्होंने तेंदुलकर के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, मर गए।

टी20 विश्व कप के स्थगित होने से आईपीएल के लिए रास्ते खुलेंगे: टेलर

मेलबर्न। आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान मार्क टेलर का मानना है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल के आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) टी20 विश्व कप के स्थगित होने से उसी समय भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के लुभावनी इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने का रास्ता साफ होगा। आस्ट्रेलिया में इस साल 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होने वाले टी20 विश्व कप को लेकर अनिश्चितता बरकरार है। कड़े नियमो के साथ आस्ट्रेलिया में हालांकि कुछ खेल दोबारा शुरू हो रहे है। टेलर ने कहा कि अगर आईपीएल होता है तो यात्रा करना खिलाड़ी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी और राष्ट्रीय बोर्ड की कोई जिम्मेदारी नही होगी। टेलर ने चैनल नाइन स्पोर्ट्स से कहा, मुझे लगता है कि यह सबसे संभावित स्थिति है (टी20 विश्व कप का स्थगित होना) क्योंकि हम इस समय जिन हालात में जी रहे है उनमें अक्टूबर और नवंबर के बीच में 15 टीमों का आस्ट्रेलिया आना, सात प्रस्तावित स्थलों पर 45 मैच खेलना, देश में यात्रा करना बेहद मुश्किल होगा। इससे पहले 14 दिन तक पृथक रहने से स्थिति और मुश्किल हो जाती है। पूरी संभावना है कि यह टूर्नामेंट नही हो पाएगा। इसलिए अगर आईसीसी टूर्नामेंट को स्थगित करने का फैसला करता है तो इससे बीसीसीआई के लिए रास्ते खुल जाएंगे कि वह कहे कि हम भारत में आईपीएल का आयोजन करा रहे है जिससे किसी देश में टीमों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड की नही बल्कि व्यक्तिगत लोगों की होगी।

हेसन को इस साल आईपीएल के आयोजन की उम्मीद

मुंबई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) के क्रिकेट संचालन निदेशक माइक हेसन को अब भी उम्मीद है कि कोरोना वायरस महामारी के बावजूद इस साल इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) आईपीएल का आयोजन होगा। उन्होंने साथ ही कहा कि टूर्नामेंट जब भी होगा तो उनकी टीम इसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार होगी। आईपीएल का आयोजन 29 मार्च से 24 मई तक तक होना था लेकिन भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने के कारण इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बाद में सरकार ने भी देश भर में लॉकडाउन लागू कर दिया। हेसन ने स्टार स्पोर्ट्स के कार्यक्रम क्रिकेट कनेक्टेड में कहा, हमें अब भी उम्मीद है कि चीजों में सुधार होगा और इस साल आईपीएल का आयोजन होगा। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आरसीबी इसके लिए तैयार रहेगा। न्यूजीलैंड के कोच रह चुके हेसन ने कहा कि अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकट को देखते हुए क्रिकेट गतिविधियों को रोककर सही फैसला किया गया। सभी की तरह हम भी शिविर के आयोजन से एक हफ्ता दूर थे, हमारी योजना भी तैयार थी। हेसन ने कहा, सभी चीजो को रोककर सही फैसला किया गया। बेशक इस समय अन्य प्राथमिकताएं है जिन पर लोगों का ध्यान है। इस महामारी के कारण दुनिया भर में अधिकांश खेल प्रतियोगिताओं को रद्द या स्थगित किया गया है जिसमें तोक्यो ओलंपिक भी शामिल हैं जिनका आयोजन इस साल होना था। आरसीबी की टीम 2008 में शुरू हुए आईपीएल का खिताब अब तक जीतने में नाकाम रही है।

स्टेन का दावा, भारतीय दर्शकों के डर से गोल्ड ने ग्वालियर में तेंदुलकर को आउट नहीं दिया था

लंदन। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने दावा किया है कि अंपायर इयान गोल्ड ने 2010 में भारतीय दर्शकों की कड़ी प्रतिक्रिया के डर से उस समय सचिन तेंदुलकर को जान बूझकर आउट नही दिया था जब वह वनडे क्रिकेट में ऐतिहासिक दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे थे। स्टेन ने कहा कि तेंदुलकर जब दोहरे शतक से दस रन दूर थे तब उन्होंने भारत के इस स्टार बल्लेबाज को पगबाधा आउट कर दिया था लेकिन मैदानी अंपायर गोल्ड ने उन्हें आउट नही दिया। उन्होंने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन के साथ स्काई स्पोर्ट्स के पॉडकास्ट में कहा , तेंदुलकर ने ग्वालियर में हमारे खिलाफ वनडे क्रिकेट में पहला दोहरा शतक बनाया। मुझे याद है कि जब वह 190 के आसपास था तब मैंने उसे आउट कर दिया था। इयान गोल्ड अंपायर थे और उन्होंने उसे नॉटआउट दिया था। स्टेन ने कहा, मैंने उनसे कहा कि आपने उसे आउट क्यों नही दिया? वह साफ आउट था। और उन्होंने कहा कि अपने चारों तरफ देखो- अगर मैंने उसे आउट दे दिया तो होटल वापस नही जा पाऊंगा।

खाली स्टेडियम में खेलने का अभ्यस्त होना होगा : नीशाम

वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के हरफनमौला खिलाड़ी जिम्मी नीशाम ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण दुनियाभर में क्रिकेट को हो रहे वित्तीय नुकसान से निपटने के लिए खिलाड़ियों को खाली स्टेडियम में खेलने का अभ्यस्त होना पड़ेगा। भारत के अलावा दुनियाभर में क्रिकेट की आर्थिक स्थिति पर नयंत्रण रखने वाले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड को डर है कि मैचों के रद्द होने के कारण राजस्व में कमी से उन्हें गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। शीर्ष स्तर के क्रिकेट के जल्द वापसी के आसार नही है और अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला टी20 विश्व का भविष्य भी अधर में है। नीशाम ने ईएसपीएनक्रिकइन्फो से कहा, अगर स्थिति यही रही तो क्रिकेट खेलने का एकमात्र तरीका है कि स्टेडियम में दर्शकों के बिना इसका आयोजन हो। हम

आईओए ने खेल मंत्रालय से 200 करोड़ रुपए से अधिक वित्तीय मदद का आग्रह किया

भाषा। नई दिल्ली

महामारी के कारण पैदा हुए संकट से पार पाने के लिए रविवार को खेल मंत्रालय से आईओए, राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) और राज्य ओलंपिक संघों को एकमुश्त वित्तीय सहायता देने का आग्रह किया। आईओए ने कहा कि प्रायोजक अगले साल तक खेल संघों की मदद के लिए आगे नहीं आ पाएंगे और ऐसे में सरकारी सहायता बेहद जरूरी हो गई है। आईओए अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने खेल मंत्री किरेन रीजीजू को पत्र लिखकर कोविड-19 के कारण खेल गतिविधियां ठप्प होने का हवाला देते हुए कहा है कि अगर सहायता नहीं मिलती है तो फिर वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के हटने के बाद खेलों को सुचारू रूप से शुरू करना मुश्किल होगा। बत्रा ने मंत्रालय से आईओए को 10 करोड़ रुपए, प्रत्एक ओलंपिक एनएसएफ को पांच करोड़ रुपए, प्रत्एक गैर ओलंपिक एनएसएफ को 2.50 करोड़ रुपए और प्रत्एक राज्य ओलंपिक संघ (एसओए) को एक करोड़ रुपए देने का आग्रह किया है। इन सभी को मिलाकर यह धनराशि लगभग 220 करोड़ रुपए हो जाती है। बत्रा ने लिखा है, इस महामारी और लॉकडाउन के कारण खेल संस्थाओं को किसी तरह का प्रायोजन मिलने की संभावना नहीं है और ऐसे में हमारे लिए अपनी गतिविधियां प्रभावशाली तरीके से शुरू करना बेहद मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, हमें 2021 ओलंपिक तक या उसके बाद किसी तरह के प्रायोजन की उम्मीद नहीं है और ऐसे में हमें केंद्र सरकार से सहायता की जरूरत होगी। बत्रा ने कहा कि यह मदद उन्हें वर्तमान समय के वित्तीय संकट से बाहर निकलने में सक्षम बनाएगी। उन्होंने कहा, कोविड-19 महामारी के कारण विश्व इस समय सबसे मुश्किल समय का सामना कर रहा है। इससे (महामारी) व्यवसाय, रोजगार के साथ साथ संबंधित देशों में खेल गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं। सभी प्रतियोगिताएं और संबंधित गतिविधियां ठप्प पड़ी हैं और इन्हें फिर से शुरू करने के लिए आईओए, एनएसएफ और एसओए को वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ेगी। अंतरराष्ट्रीय हाकी महासंघ (एफआईएच) के भी प्रमुख बत्रा ने कहा कि धनराशि आवंटित होने पर आईओए उसका ऑडिट करने के लिए तैयार है।

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के चौथे चरण में खेल परिसर और स्टेडियम खोलने की अनुमति दी

भाषा। नई दिल्ली

गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के चौथे चरण में खेल परिसरों को खोलने की अनुमति दी जिससे संभवत: खिलाड़ियों का अभ्यास शुरू करने का रास्ता साफ हो गया जो मार्च के मध्य से ही बंद है। लॉकडाउन के दौरान पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों में से एक में लिखा, खेल परिसर और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि दर्शकों को अनुमति नहीं होगी। तीसरे चरण का लॉकडाउन सोमवार को समाप्त हो गया लेकिन इसे 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। भारत में अभी तक 90,000 से ज्यादा कोविड-19 मामले सामने आए हैं जिसमें करीब 3000 लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि खेलों को उन कार्यक्रमों और जश्न में शामिल किया गया है जिन्हें अब तक अनुमति नहीं मिली है। देशव्यापी लॉकडाउन मार्च के मध्य से शुरू हुआ था और भारतीय खेल प्राधिकरण के पटियाला और बेंगलुरू में परिसरों में शीर्ष खिलाड़ी अभ्यास शुरू करने की मांग कर रहे हैं।

जनधन खाता वाले जूनियर खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि देने में बीसीसीआई को हुई परेशानी

भाषा। नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) को उन खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि जारी करने में परेशानी हुई जिनका बैंक खाता जनधन योजना के तहत खुला है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि उन्हें लगभग छह जूनियर क्रिकेटरों को पुरस्कार की राशि देने में परेशानी हुई क्योंकि उनका बैंक खाता जनधन योजना के तहत खुला है। ऐसे खातों में अधिकतम 50,000 रूपए की राशि जमा की जा सकती है। बीसीसीआई शीर्ष समिति के इस अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, बीसीसीआई वार्षिक समारोह में पुरस्कार पाने वाले सभी आयु वर्ग के क्रिकेटरों को डेढ़ लाख रुपए दिए जाने थे। सीनियर खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि का हस्तांतरण 11 जनवरी को समारोह के तुरंत बाद कर दिया गया था। लेकिन पांच जूनियर क्रिकेटरों के खाते में डेढ लाख रुपए की लेनदेन को अस्वीकार कर दिया। इन खातों में कई बार रकम डालने की कोशिश विफल होने के बाद हमने अपने बैंक से इस बारे में पूछा तो पता चाला कि इन क्रिकेटरों का खाता जनधन योजना के तहत खुला है। ऐसे में एक बार में 50,000 हजार रुपए ही जमा हो सकते है। इसके बाद बीसीसीआई ने अपने बैंक (बैंक ऑफ महाराष्ट्र) से सभी खिलाड़ियों के खाते वाले बैंकों से संपर्क करने को कहा ताकी मुद्दे को सुलझाया जा सके। इस मुद्दे को जन धन खातों को बचत खातों में परिवर्तित करके हल किया जा सकता है, जिसमें नकद जमा पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। अधिकारी ने कहा, दरअसल, जूनियर क्रिकेटरों के लिए मैच फीस काफी कम है। अंडर-16 खिलाड़ियों को प्रति मैच 10,000 रुपए (प्रति दिन 2500 रुपए) और अंडर-19 खिलाड़ियों को 40,000 रुपए (प्रति दिन 10,000 रुपए) मिलते हैं। उन्होंने कहा, इसलिए सामान्य समय में, जब मैच फीस इन खातों में स्थानांतरित की जाती है तो कोई समस्या नहीं आती। चूंकि इस बार राशि अधिक थी, इसलिए परेशानी हुई।

जनरल अटलांटिक ने रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स में 6,598 करोड़ रुपए का निवेश किया

नई दिल्ली। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक के बाद अब अमेरिका की अग्रणी निवेश कंपनी जनरल अटलांटिक ने भी अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में अल्पांश हिस्सेदारी के लिए करीब छह हजार छह सौ करोड़ रुपए का निवेश किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रविवार को एक बयान में बताया कि जनरल अटलांटिक ने उसकी डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.34 प्रतिशत हिस्सेदारी के बदले 6,598.38 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यह जनरल अटलांटिक का एशिया की किसी भी कंपनी अभी तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। जियो प्लेटफॉर्म्स ने अब तक चार हफ्तों से भी कम समय में फेसबुक, सिल्वर लेक पार्टनर्स, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स और जनरल अटलांटिक सहित प्रमुख प्रौद्योगिकी निवेशकों से 67,194.75 करोड़ रुपए जुटाए है।

नए सुधारों से विमानन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत होगी भारत की स्थिति: जीएमआर

नई दिल्ली। दिल्ली हवाई अड्डे समेत कई हवाई अड्डों का संचालन करने वाली कंपनी जीएमआर ग्रुप ने विमानन क्षेत्र मे किए गए सुधारों का स्वागत करते हुए शनिवार को कहा कि इससे वैश्विक स्तर पर विमानन क्षेत्र मे भारत की स्थिति मजबूत होगी। कंपनी के चेयरमैन जी एम राव ने एक बयान में कहा, भारत वैश्विक स्तर पर नागरिक उड्डयन क्षेत्र की वृद्धि की अगुवाई कर रहा है और महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पैदा कर रहा है। वित्त मंत्री द्वारा आज की घोषणाओं से वैश्विक विमानन क्षेत्र में भारत की स्थिति के और मजबूत होने की उम्मीद है। भारतीय हवाई क्षेत्र को युक्तिसंगत बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे न केवल पूरे क्षेत्र को फायदा होगा बल्कि यात्रियो के लिए यात्रा का समय भी कम होगा।

वृद्धि दर शून्य से ऊपर रखने के लिए तीन से पांच प्रतिशत अतिरिक्त सार्वजनिक खर्च की जरूरत: एनसीएईआर

नई दिल्ली। अर्थशास्त्र के मामलो मे शोध एवं परामर्श देने वाले एक सरकारी संस्थान का कहना है कि 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर शून्य से ऊपर बनाए रखने के लिए सरकार को तीन से पांच प्रतिशत अतिरिक्त सार्वजनिक खर्च करने की जरूरत है। संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के लिए जारी अपनी पहली कोरोना वायरस रिपोर्ट में यह कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनो वायरस महामारी और इसकी रोकथाम के लिए देश भर में करीब दो महीने से लागू लॉकडाउन के असर से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 12 मई को देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 10 प्रतिशत यानी 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की।

आरबीएल का अनुमान, 2020-21 में नए क्रेडिट कार्डों, खर्च में कमी आएगी

मुंबई। आरबीएल बैंक का मानना है कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 में नए क्रेडिट कार्डों की संख्या घटकर आधी रह जाएगी। साथ ही उपभोक्ताओं का क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च भी घटेगा। आरबीएल बैंक के ऋण पोर्टफोलियो में क्रेडिट कार्ड का हिस्सा करीब 18 प्रतिशत है। बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हालांकि उम्मीद जताई कि इस खंड में उसकी कुल आय कायम रहेगी। अधिकारी ने कहा कि मौजूदा आर्थिक माहौल में क्रेडिट कार्ड खंड मे ऋण की लागत 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ेगी। यानी संभावित ऋण नुकसान के लिए अधिक राशि का प्रावधान करने की जरूरत होगी।

अवैध फास्टैग वाले वाहनों से वसूला जाएगा दोगुना टोल

नई दिल्ली। अवैध या काम नही कर रहे फास्टैग वाले वाहनो के प्रतिबद्ध फास्टैग लेन में घुसने पर दोगुना टोल वसूला जाएगा। सरकार ने रविवार को यह जानकारी दी। इससे पहले राष्ट्रीय राजमार्गों पर केवल उन्ही वाहनों से दोगुना टोल टैक्स शुल्क वसूला जाता था जो बिना फास्टैग लगाए टोल बूथ पर फास्टैग प्रतिबद्ध लेन में प्रवेश करते थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा, बिना फास्टैग या काम नही कर रहे या अवैध फास्टैग वाले वाहनों के प्रतिबद्ध फास्टैग लेन मे घुसने पर दोगुना शुल्क वसूला जाएगा।

कोविड-19 बना सकती है भारत में 13.5 करोड़ को बेरोजगार

12 करोड़ गरीबी की गर्त में जा सकते है : रिपोर्ट

भाषा। नई दिल्ली

कोरोना वायरस महामारी (कोविड-19) के कारण भारत में 13.5 करोड़ लोगों की नौकरियां समाप्त हो सकती हैं और 12 करोड़ लोग गरीबी के गर्त में गिर सकते हैं। एक रिपोर्ट में यह आशंका व्यक्त की गई है। परामर्श कंपनी आर्थर डी लिटिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस महामारी का उपभोक्ताओं की आय, उनकी बचत और खर्च पर व्यापक असर हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 का सबसे बुरा असर नौकरियों के नुकसान, गरीबी में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के रूप में निचले पायदान के लोगों पर पड़ेगा। इसके कारण सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भी तेज गिरावट हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया, कोविड-19 के मामलों की निरंतर वृद्धि को देखते हुए हमारा मानना है कि भारत में डब्ल्यू-शेप्ड रिकवरी अर्थात आर्थिक हालत में सुधार के बाद गिरावट और फिर सुधार की अधिक संभावनाएं हैं। इसके अनुसार 2020-21 में जीडीपी में 10.8 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है और 2021-22 में जीडीपी की वृद्धि दर 0.8 प्रतिशत रह सकती है। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों की संख्या अब तक नब्बे हजार के पार जा चुकी है। इस महामारी के कारण अब तक देश में करीब 28 सौ लोगों की मौत भी हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार, इस महामारी के कारण भारत में बेरोजगारी की दर 7.6 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।

20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का राजकोषीय प्रभाव 1.50 लाख करोड़ रुपए : रिपोर्ट

मुंबई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को घोषित आर्थिक पैकेज की पांचवी किस्त की लागत 40,000 करोड़ रुपए बैठेगी। इस तरह पिछले कुछ दिन मे घोषित उपायों का राजकोषीय प्रभाव 1.50 लाख करोड़ रुपए या सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.75 प्रतिशत बैठेगा। एक रिपोर्ट मे यह अनुमान लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए या जीडीपी के 10 प्रतिशत के बराबर पैकेज की घोषणा की थी। इनमे से कई उपायो ऋण गारंटी आदि है जिनकी तत्काल कोई राजकोषीय लागत नही बैठेगी। बार्कलेज के भारत में मुख्य अर्थशास्त्री राहुल बजोरिया ने कहा, हमारा अनुमान है कि इस 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का बजट पर राजकोषीय प्रभाव सिर्फ 1.50 लाख करोड़ रुपए या जीडीपी का 0.75 प्रतिशत बैठेगा। हमने यह निष्कर्ष अपनी गणना और अनुमानो के आधार पर निकाला है। केंद्र सरकार इन घोषणाओं के क्रियान्वयन के बाद चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के छह प्रतिशत तक सीमित रख पाएगी। हालांकि, राजकोषीय घाटे का बजटीय लक्ष्य 3.5 प्रतिशत का है।

सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से आठ कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1.37 लाख करोड़ रुपए घटा

नई दिल्ली। सेंसेक्स मे शामिल शीर्ष 10 में से आठ कंपनियों का बाजार पूंजीकरण शुक्रवार को समाप्त सप्ताह में कुल1,37,311.31 करोड़ रुपए घट गया। सबसे अधिक नुकसान में रिलायंस इंडस्ट्रीज रही। केवल भारती एयरटेल और आईटीसी का बाजार पूंजीकरण बढ़ा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 65,232.46 करोड़ रुपए घटकर 9,24,855.56 करोड़ रुपए रह गया। एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 22,347.07 करोड़ रुपए गिरकर 4,87,083.88 करोड़ रुपए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का 13,192.26 करोड़ रुपए घटकर 4,77,458.89 करोड़ रुपए, आईसीआईसीआई बैंक का 9,770.06 करोड़ रुपए घटकर 2,08,900.79 करोड़ रुपए, इंफोसिस का 9,518.84 करोड़ रुपए. गिरकर 2,77,814.09 करोड़ रुपए, एचडीएफसी का 9,370.38 करोड़ रुपए गिरकर 2,83,293.70 करोड़ रुपए, कोटक महिंद्रा बैंक का 7,805.20 करोड़ रुपए गिरकर 2,25,327.22 करोड़ रुपए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (टीसीएस) का 75.04 करोड़ रुपए घटकर 7,10,439 करोड़ रुपए रहा।

हिंदुजा, रियूबेन बंधु ब्रिटेन में दूसरे सबसे अमीर

लंदन। हिंदुजा परिवार और रियूबेन बंधु, भारतीय मूल के ए दोनों उद्यमी परिवार ब्रिटेन के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दोनों परिवारों की संपत्ति 16-16 अरब पौंड है। वही ब्रितानी नवोन्मेषक जेम्स डायसन 16.2 अरब पौंड की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर है। द संडे टाइम्स रिच लिस्ट-2020 के मुताबिक हिंदुजा समूह की कंपनियां चलाने वाले श्रीचंद हिंदुजा और गोपीचंद हिंदुजा की संपत्ति एक साल में छह अरब पौंड कम हूई है। पिछले साल वह सूची में पहले स्थान पर थे। मुंबई में जन्में डेविड और सिमॉन रियूबेन की संपत्ति पिछले एक साल में 2.66 अरब पौंड घटी है। लेकिन वह 2019 की भांति दूसरे स्थान पर बने रहे।

मार्च में रत्नाभूषण निर्यात 38.8 प्रतिशत नीचे, पूरे वित्त वर्ष में गिरावट 8.9 प्रतिशत

नई दिल्ली। भारत से रत्न और आभूषणों का निर्यात पिछले वित्त वर्ष के अंतिम मास मार्च में एक साल पहले की तुलना में 38.81 प्रतिशत गिर कर 13,744.60 करोड़ रुपए के बराबर रहा। पिछले साल मार्च मे यह आंकड़ा 22,463.17 करोड़ रुपए के बराबर था।रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (जीजेईपीसी) के अनुसार वर्ष 2019-20 मे इस क्षेत्र का कुल निर्यात 2,51,096,30 करोड़ रुपए रहा।

सरसों, मूंगफली, बिनौला सहित विभिन्न तेल कीमतों में सुधार

नई दिल्ली। लॉकडाउन मे ढील दिए जाने के बाद बाजार की मांग बढ़ने के कारण सोयाबीन डीगम को छोड़कर विभिन्न तेल-तिलहन कीमतों मे पिछले सप्ताहांत के मुकाबले सुधार आया। हालांकि, इस सुधार के बावजूद सरसों, सोयाबीन सहित विभिन्न देशी खाद्य तेलों के भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम चल रहे है और किसानों को इसका कोई फायदा नही है क्योंकि उनके लिए अपनी लागत निकालना मुश्किल हो रहा है। बाजार सूत्रों ने कहा कि हालांकि पिछले सप्ताहांत के मुकाबले सरसों में सुधार आया है लेकिन अगर इसके वायदा और हाजिर भाव को देखा जाए तो वह एक अप्रैल से लागू 4,425 रुपए क्विन्टल के भाव से काफी कम है।

राज्यों की कर्ज सीमा बढ़ी: 2020-21 अपनी जीडीपी के पांच प्रतिशत के बराबर कर्ज उठा सकते हैं राज्य

भाषा। नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष (2020-21) के लिए राज्यों की कुल कर्ज उठाने की सीमा बढ़ा कर पांच प्रतिशत करने की घोषणा की। अभी तक वे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के तीन प्रतिशत तक ही बाजार से कर्ज ले सकते थे। इस कदम से राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त धन उपलब्ध होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की पांचवीं और अंतिम किस्त जारी करते हुए यहां एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यों के लिए कर्ज लेने की सीमा में की गई वृद्धि विशिष्ट सुधारों से जुड़े होंगे। ए सुधार एक देश-एक राशन कार्ड को अपनाने, कारोबार सुगमता, बिजली वितरण और शहरी व ग्रामीण निकायों के राजस्व को लेकर हैं। अभी राज्यों के लिए उधार जुटाने की पहले से स्वीकृत कुल सीमा 6.41 लाख करोड़ रुपए (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत) है। हालांकि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर उधार जुटाने की सीमा बढ़ाने की मांग की थी। राज्यों ने अब तक अधिकृत सीमा का केवल 14 प्रतिशत उधार लिया है। 86 प्रतिशत अधिकृत कर्ज सीमा को अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है। हालांकि राज्य इसके बावजूद कुल उधार की सीमा को जीएसडीपी के तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने की मांग कर रहे थे।

घिसे-पिटे उपायों के बजाय अर्थव्यवस्था को उबारने के नए तरीके लाएं: बीएमएस

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) समर्थित श्रम संगठन भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने शनिवार को सरकार से कहा कि वह घिसे-पिटे उपायों के बजाय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के नए उपाय सामने लाए। बीएमएस ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने पर भी सुरक्षा की दृष्टि सेआपत्ति जताई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी तथा इसकी रोकथाम के लिए करीब दो महीने से लागू लॉकडाउन की मार से अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त के उपायों की यहां एक संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी।

विकास के विकेंद्रीकरण में प्रवासी मजदूरों की समस्या का है समाधान : गडकरी

भाषा। नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि शहरों के विकेंद्रीकरण और दूर-दराज के इलाकों का विकास करने से प्रवासी मजदूरों के संकट को कम करने में मदद मिल सकती है। गडकरी ने कहा, प्रवासी मजदूरों का संकट बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह समय है कि विकास के माध्यम से गांव, ग्रामीण, पिछड़े इलाकों और दूर-दराज के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है और वह अपने मूल निवास स्थानों की ओर लौटने को मजबूर हैं। इसमें भी कुछ लोग पैदल अपने घरों को लौट रहे हैं। इसके चलते कई लोगों की सड़क दुर्घटनाओं मृत्यु हो गई। गडकरी ने कहा, हमें कोरोना वायरस के साथ रहना सीखना होगा। कोई भी बड़े शहर में अपनी मर्जी से नहीं आता। बहुत गरीबी और अवसरों की कमी उसे बड़े शहर आने के लिए मजबूर करती है। दर्द और डर (रोजगार और भुखमरी का) की वजह से वह अपनी जड़ों की ओर लौटने को मजबूर हैं। हमने उनके लिए टोल बूथ पर खाना इत्यादि का प्रबंध किया है लेकिन हमें उनके अंदर सकारात्मकता भरनी है। नागपुर में अपने घर से एक टेलीफोन साक्षात्कार में गडकरी ने कहा कि डर ने ही इस भयावह स्थिति को खड़ा किया है। गडकरी ने कहा कि हमें उद्योगों का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है जिसके वजह से लोग गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, लुधियाना, चेन्नई, बेंगलुरू, हैदराबाद, मुंबई और पुणे आते हैं।

घर पहुंचने के लिए बेताब हैं इजराइल में फंसे भारतीय

कोविड-19

भाषा। यरूशलम

कोविड-19 महामारी के बीच इजराइल में फंसे अनेक भारतीयों को इस खबर से बड़ी राहत मिली है कि एयर इंडिया का एक विशेष विमान 25 मई को यहां फंसे भारतीयों को लेकर जाएगा।

भारत सरकार ने सात मई को वंदे भारत मिशन की शुरूआत की थी जिसके तहत कोरोना वायरस के कारण बंद के दौरान विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। मिशन के पहले चरण के तहत खाड़ी देशों और अमेरिका, ब्रिटेन, फिलीपीन, बांग्लादेश, मलेशिया तथा मालदीव आदि से कुल 6,527 भारतीयों को स्वेदश वापस लाया गया है। एयर इंडिया के कंट्री मैनेजर पंकज तिवारी नेकहा, एयर इंडिया ने इजराइल में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए 25 मई को दिल्ली-तेल अवीव-दिल्ली सेक्टर के लिए एक उड़ान की योजना बनाई है और हम सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने को प्रतिबद्ध हैं, मसलन इस बात का शपथपत्र देना कि लोग अनिवार्य पृथक-वास में रहेंगे। हम उन इजराइल वासियों को भी यहां लौटने का प्रस्ताव देंगे जो इस समय भारत में हैं और लौटना चाहते हैं। तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने 15 मई को घोषणा की थी कि वह यहां से लौटने के इच्छुक फंसे हुए भारतीय नागरिकों की वापसी की संभावना पर विचार कर रहा है, जो कोविड-19 के कारण लगी अंतरराष्ट्रीय यात्रा पाबंदियों के चलते पहले नहीं जा सके। घोषणा में कहा गया, यात्रियों को यात्रा का खर्च उठाना होगा और गंतव्य पर पहुंचकर अनिवार्य रूप से पृथक-वास में रहना होगा। दूतावास के अधिकारियों ने बताया, अभी तक वापसी के लिए करीब 140 लोगों ने संपर्क किया है जिनमें से 90 ने अपना विवरण दे दिया है और टिकट का भुगतान करने तथा पृथक-वास में रहने के लिए तैयार हैं। अधिकतर लोगों की केरल वापसी की इच्छा को देखते हुए बताया जा रहा है कि विदेश मंत्रालय दिल्ली से कोच्चि की कनेक्टिंग उड़ान पर भी विचार कर रहा है।केरल के इडुक्की जिले की रहने वाली अन्नमा सिबी 2013 में लोगों की देख-रेख के काम के लिए इजराइल आई थीं लेकिन अब जीवन-यापन के लिए तेल अवीव में लोगों के घरों की सफाई कर रही हैं। सिबी ने कहा, पिछल करीब चार महीने से मेरे पास काम नहीं हैं। मेरे पास पैसा भी नहीं है। मुझे कमरे का किराया देना है और इजराइल बहुत महंगा है।

तिराना: राष्ट्रीय नाट्य भवन के विध्वंस के दौरान इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों को रोकती पुलिस

चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के 17 नए मामले

बीजिंग। चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के 17 नए मामले सामने आए हैं जिनमें से 12 मामले ऐसे हैं जिनमें मरीज में संक्रमण के लक्षण नहीं हैं। इस बीच वुहान में कई क्षेत्रों में कोविड-19 के नए मामले सामने आने पर अधिकारियों ने 1.1 करोड़ लोगों की गहन पैमाने पर जांच जारी रखी है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने रविवार को कहा कि शनिवार को जिलिन प्रांत में संक्रमण के पांच नए मामले सामने आए जिनमें से तीन मरीज स्थानीय स्तर पर संक्रमित हुए। संक्रमण के नए मामले सामने आने पर जिलिन शहर में इस हफ्ते लॉकडाउन लगा दिया गया था। आयोग ने कहा कि बिना किसी लक्षण वाले 12 नए मामले सामने आने के साथ ही ऐसे संक्रमण के मामले 515 हो गए।बिना लक्षण वाले संक्रमण का एक मरीज विदेश से आया था। चीन में कोविड-19 संक्रमण के 82,947 मामले हैं। कुल मामलों में से 86 मरीजों का इलाज चल रहा है जबकि 78,227 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई।

इज़राइल में तीन चुनावों के बाद अब सरकार बनना तय

एपी। यरुशलम

गतिरोध और बिना किसी स्पष्ट नतीजे के तीन बार हुए चुनावों और डेढ़ साल तक कार्यवाहक सरकार रहने के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार रविवार को अंततः शपथ ले रही है। शपथ से पहले भी हालांकि तीन दिनों तक मंत्री पद को लेकर उनकी लिकुड पार्टी के अंदर काफी खींचतान चलती रही।

सप्ताहांत पर नेतन्याहू और उनके विरोधी से सहयोगी बने बेनी गांट्ज ने नई सरकार के गठन के लिए साथ आने की घोषणा की। नई सरकार में इज़राइल के इतिहास में सबसे ज्यादा 36 मंत्रियों और 16 उप मंत्रियों के होने की उम्मीद है। नेतन्याहू और पूर्व सेना प्रमुख गांट्ज ने पिछले महीने कहा था कि वे कोरोना वायरस संकट और गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अपने मतभेदों को दरकिनार कर साथ आ रहे हैं। सत्ता साझेदारी के विवादित समझौते के तहत सरकार गठन के पहले 18 महीने नेतन्याहू प्रधानमंत्री रहेंगे और उसके बाद अगले 18 महीने सरकार की बागडोर गांट्ज के हाथों में होगी। दोनों पक्षों के समान संख्या में मंत्री होंगे और अन्य प्रमुख मुद्दों पर वीटो करने की परोक्ष शक्ति भी। आलोचक ऐसे समय में सरकार में इतने मंत्री बनाए जाने की आलोचना कर रहे हैं जब कोरोना वायरस के कारण बेरोजगारी दर बढ़कर 25 प्रतिशत पहुंच गई है। नेतन्याहू के खेमे में कई छोटे दल भी शामिल हैं और ऐसे में लिकुड पार्टी के पदाधिकारियों को देने के लिए उनके पास सीमित संख्या में मंत्रीपद हैं और ऐसे में बृहस्पतिवार को निर्धारित शपथ ग्रहण समारोह से पहले पार्टी के नाराज वरिष्ठ सदस्यों के हल्के विरोध का भी उन्हें सामना करना पड़ा।

यह मामला समय पर नहीं सुलझा पाने के कारण नेतन्याहू ने पार्टी के अंदरूनी संकट के समाधान के लिए शपथग्रहण टालने को कहा था। सत्ता के लिए हुई साझेदारी की वजह से गांट्ज की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी पहले ही बंट गई है कि उसने नेतन्याहू के साथ काम नहीं करने के अपने मुख्य चुनावी वादे से समझौता कर लिया। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का आरोप है और उन्हें मुकदमे का सामना करना है। दोनों पार्टियों में यह समझौता होने से पहले देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि

● **नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का आरोप है और उन्हें मुकदमे का सामना करना है। दोनों पार्टियों में यह समझौता होने से पहले देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि उसके पास इसे रोकने का कोई कानूनी आधार नहीं है**

उसके पास इसे रोकने का कोई कानूनी आधार नहीं है।

आलोचनाओं के बावजूद गांट्ज की दलील है कि नेतन्याहू से हाथ मिलाना देश को लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक गतिरोध और इज़राइल को एक बार फिर खर्चीले चुनाव में ढकेलने से रोकने का एक मात्र रास्ता था। इज़राइल में अगर फिर चुनाव की नौबत आती तो लगभग एक साल में चौथा चुनाव होता।गांट्ज नई सरकार में रक्षा मंत्री होंगे जबकि उनके साथी सेवानिवृत्त पूर्व सेना प्रमुख गाबी अस्केनाजी विदेश मंत्री बनाए जाएंगे। लिकुड पार्टी में नेतन्याहू के शीर्ष सहयोगी निवर्तमान विदेश मंत्री इज़राइल काट्ज वित्त मंत्री बनाए जाएंगे। आलोचना की एक मुख्य वजह वैकल्पिक प्रधानमंत्री का नवसृजित पद है।

यह गांट्ज से पद बदलने के बाद भी नेतन्याहू को कार्यालय में बने रहने और भ्रष्टाचार के मुकदमे और संभावित अपील प्रक्रिया पर नजर रखने में मदद करेगा। इस बात को लेकर भी लोगों में संदेह है कि क्या नेतन्याहू मोलभाव के अपने पक्ष को बरकरार रखते हुए अंततः गांट्ज को पद सौंपेंगे। इसके बाद भी नया पद माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री को मिलने वाली सभी सुविधाओं से युक्त होगा जिसमें आधिकारिक आवास और सबसे महत्वपूर्ण कानून से यह छूट कि प्रधानमंत्री के आधिकारिक पद पर नहीं रहने वाले व्यक्ति को आरोप लगने पर इस्तीफा देना होता है। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार, विश्वास भंग और घूस लेने के कई आरोप हैं।

क्विक न्यूज

कोरोना वायरस: बीजिंग ने कहा कि बाहर निकलने पर मास्क पहनना आवश्यक नहीं

बीजिंग। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए महीनों तक मास्क पहनने को मजबूर बीजिंग के लोग अब बाहर निकलने पर खुली हवा में बिना मास्क के सांस ले सकेंगे क्योंकि यहां बाहर निकलने पर इसे पहनने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। कोविड-19 के दुनियाभर मे प्रकोप के बीच बीजिंग चीन का और शायद दुनिया का ऐसा कदम उठाने वाला पहला शहर है। इससे संकेत मिलते हैं कि चीन की राजधानी में कोरोना वायरस संबंधी हालात काबू में है। चाइना डेली की खबर के मुताबिक बीजिंग सेंटर फॉर डिसीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ने इस बारे में नए दिशा-निर्देशो की घोषणा की है। केन्द्र ने कहा है कि लोगो को बाहर निकलने पर मास्क पहनने की जरूरत नही है लेकिन अब भी उन्हें नजदीकी संपर्क से बचकर रहना चाहिए। संसद सत्र कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए स्थगित किया गया था लेकिन अब देश मे संक्रमण के मामलो मे आ रही कमी को देखते हुए इसका 22 मई को आयोजन किया जा सकता है।

स्पेन में दो महीनों में पहली बार कोरोना वायरस से एक दिन में मौतों की संख्या सबसे कम रही

मैड्रिड। स्पेन मे कोरोना वायरस से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा के बाद से पहली बार एक दिन मे इस महामारी से मृतको की संख्या 100 से कम रही। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस वायरस से 87 और लोगो की मौत हुई है जो 16 मार्च के बाद एक दिन मे मौतो की सबसे कम संख्या है।स्पेन में इस महामारी के चरम पर होने पर एक दिन में 900 से अधिक लोगो की मौत भी हुई है। देश मे इस वायरस से 27,650 लोगो की मौत हो चुकी है और 2,77,719 लोग संक्रमित हुए है।

यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट में आठ अन्य नाविक दोबारा पाए गए कोरोना वायरस से संक्रमित

वाशिंगटन। अमेरिका के विमान वाहक पोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट में आठ और नाविक कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमित पाए गए है।इसके साथ ही पोत मे ऐसे नाविको की संख्या बढ़कर 13 हो गई जो पोत में सेवाएं देते समय दोबारा संक्रमित हुए प्रतीत होते हैं। इससे पहले सभी नाविक संक्रमित पाए गए थे और उन्हें कम से कम दो सप्ताह के लिए पृथक-वास में रखा गया था। एक या दो दिन के अंतर मे लगातार दो बार जांच मे संक्रमण मुक्त पाए जाने के बाद ही उन्हे पोत पर जाने की अनुमति दी गई थी।

तिब्बत ने चीन से पंचेन लामा के बारे में जानकारी मांगी

बीजिंग। तिब्बत की स्वघोषित निर्वासित सरकार ने 11वें पंचेन लामा के तौर पर नामित किए गए एक लड़के के लापता होने के 25 वर्ष पूरे होने पर रविवार को चीन से उसके बारे में जानकारी देने के लिए कहा है।उत्तर भारत मे तिब्बती संसद कशाग ने कहा कि लड़के को 11वें पंचेन लामा के तौर पर नामित किया गया था। छह वर्ष की उम्र मे उन्हें उनके परिवार के साथ 1995 में उठा लिया गया और वह इस पद पर वैध रूप से वही विराजमान है।तिब्बत को अपना क्षेत्र मानने वाले चीन ने एक अन्य लड़के ग्याल्तसेन नोरबु को इस पद के लिए नामित किया और समझा जाता है कि चीन में वह सरकार के नियंत्रण में रहते है और कभी-कभी ही सार्वजनिक रूप से दिखते है। कशाग ने बयान जारी कर कहा, चीन द्वारा पंचेन लामा का अपहरण करना और उनकी धार्मिक पहचान से जबरन इंकार करना और मठ मे उन्हें पूजा-पाठ से रोकना न केवल धार्मिक आजादी का उल्लंघन है बल्कि मानवाधिकारो का भी गंभीर उल्लंघन है। बयान मे कहा गया है, अगर चीन का यह दावा सत्य है कि तिब्बत के लोगो को तिब्बत के अंदर धार्मिक आजादी है तो चीन को 11वें पंचेन लामा के बारे मे बताना चाहिए कि वह कहां है और कैसे है।

चीन में और स्कूलों को खोला गया, विमान संचालन शुरू

बीजिंग। चीन मे रविवार को कोरोना वायरस के पांच नए मामले सामने आए। वही वाणिज्यिक केंद्र शंघाई ने कुछ स्कूलो को फिर से खोलने और एयरलाइनो ने विमानो का संचालन शुरू करने की घोषणा की। नए मामलो मे से दो आयातित मामले है और तीन उत्तरपूर्वी प्रांत जिलिन से सामने आए। शंघाई मे छात्र वायरस की जांच कराने और स्कूलो मे सामाजिक दूरी बरतने के बजाय ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने का विकल्प अपना रहे है। बीजिंग और अन्य शहरो की तरह शंघाई ने परीक्षाओ की तैयारी कर रहे माध्यमिक और हाईस्कूलो के छात्रो के लिए कक्षाएं शुरू कर दी है। पिछले महीने मौत का कोई नया मामला सामने नही आया था लेकिन जिलिन मे एक व्यक्ति की मौत को संक्रमण से जोड़कर देखा गया है। इसके साथ ही चीन मे कोविड-19 से मरने वाले लोगो की संख्या 4,634 हो गई और 82,947 लोग संक्रमित पाए गए है। कोविड-19 के इलाज के लिए अब केवल 86 लोग अस्पताल मे भर्ती है जबकि इससे संक्रमित 519 अन्य लोग पृथक-वास मे है। देश मे गर्मियो की छुट्टियो को देखते हुए कई पर्यटक स्थल फिर से खोल दिए है। हालांकि सामाजिक दूरी के सख्त नियम अब भी लागू है।

भारतीय मूल के मंत्री ने ब्रिटेन में लाखों पाउंड के टीका केंद्र की योजना की घोषणा की

भाषा। लंदन

ब्रिटेन में भारतीय मूल के मंत्री आलोक शर्मा ने एक नए टीका उत्पादन केंद्र के निर्माण में तेजी के लिए नौ करोड़ 30 लाख पाउंड के निवेश की रविवार को घोषणा की। यह कदम कोरोना वायरस महामारी से लड़ने की व्यापक योजना का हिस्सा है। ब्रिटेन के व्यापार, ऊर्जा और औद्योगिक रणनीति मंत्री ने कहा कि निर्माण पूरा होने के बाद इस नए टीका उत्पादन एवं नवोन्मेष केंद्र (वीएमआईसी) में छह महीने के अंदर पूरी ब्रिटिश आबादी के लिए पर्याप्त टीकों के उत्पादन की क्षमता होगी। उन्होंने कहा कि इस रकम का निवेश यह सुनिश्चित करेगा कि यह केंद्र तय समय से करीब 12 महीने पहले अगले वर्ष की पहली छमाही में खुल जाए। इसके अलावा तीन करोड़ 80 लाख पाउंड का सरकारी निवेश एक त्वरित तैनाती केंद्र की स्थापना के लिए किया जाएगा, जो आने वाले महीनों में तैयार होगी। शर्मा ने कहा, टीके की खोज के लिए अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ में सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में ब्रिटेन वैश्विक कार्वाई का नेतृत्व कर रहा है। एक बार जब सफलता मिल जाएगी तो हमें लाखों की संख्या में इन टीकों के उत्पादन के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि नया वीएमआईसी और अस्थाई केंद्र टीके के लिए शुरू से अंत तक पूरी प्रक्रिया को तैयार करेगा और ब्रिटेन के टीका कार्यक्रम को खोज से वितरण तक एक साथ लाएगा। निर्माणाधीन नए केंद्र के बारे में कहा जाता है कि वह टीका विकसित करने और व्यापक स्तर पर उसके उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के ब्रिटेन के कोरोना वायरस कार्यक्रम का अहम हिस्सा है। यह केंद्र ऑक्सफोर्डशायर में हार्वेल साइंड एंड इनोवेशन कैंपस में स्थित होगा।

कराची स्थित एक चर्च में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सोशल डिस्टेंस व मास्क पहनकर बैठे लोग

कोविड-19 से मरीजों को दीर्घकालिक नुकसान चीन ने बीमा में बीमारी के बाद के प्रभावों को जोड़ा

भाषा। बीजिंग

चीन के स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कोविड-19 रोगियों के लिए चिकित्सा बीमा कवर का विस्तार करते हुए उसमें बीमारी के बाद विभिन्न अंगों पर पड़ने वाले प्रभावों को भी शामिल किया है। कोविड-19 से ठीक हुए रोगी अपनी इन समस्याओं के लिए सरकारी चिकित्सा बीमा कवर के अंतर्गत इलाज करा सकें।

चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग (एनएचसी) ने कोविड-19 से ठीक हुए लोगों को लेकर जारी अपने दिशा-निर्देशों में कहा कि ठीक हुए कुछ मरीजों को फेफड़ों और हृदय को हुए नुकसान के लिए उपचार की आवश्यकता होगी, साथ ही मांसपेशियों के नुकसान से जिन्हें चलने में, काम करने में समस्या हो

● **कोविड-19 से ठीक हुए रोगी अपनी इन समस्याओं के लिए सरकारी चिकित्सा बीमा कवर के अंतर्गत इलाज करा सकें**

रही है या जिनमें मनोवैज्ञानिक विकार की समस्याएं आ गई है, उन सभी को इलाज की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य कर्मचारियों को रोगियों की संभावित दीर्घकालिक उपचार आवश्यकताओं के बारे में सूचित करने के अलावा, अधिकारियों ने इन समस्याओं को भी पुरानी बीमारियों के रूप में वर्गीकृत किया है, जिससे कि निवासी सरकारी चिकित्सा बीमा योजनाओं के तहत चिकित्सा खर्च उपलब्ध कराने के लिए दावा कर सकें। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने एनएचसी के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए कहा, कोविड-19 के इलाज के बाद अस्पतालों से छुट्टी पाने वाले लोगों की संख्या बढ़ने के साथ, राहत व पुनर्वास कार्यों की जरूरतें महत्त्वपूर्ण हो गई हैं। शनिवार तक चीन में 78,227 लोग बीमारी से उबर चुके हैं। सरकार ने संक्रमण को रोकने के लिए 23 जनवरी से कार्रवाई शुरू की थी।

पिछले साल दिसंबर में चीन के वुहान में उभरी कोरोना वायरस महामारी दुनिया भर में अब तक 3,12,000 से अधिक लोगों की जान ले चुकी है और 46 लाख से अधिक लोगों संक्रमित हैं। चीन में शनिवार तक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 82,947 थी। कुल मामलों में से, 86 रोगियों का इलाज चल रहा है।

मालदीव से करीब 1,500 भारतीयों को निकाला गया

भाषा। माले

कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा पाबंदियों के कारण मालदीव में फंसे करीब ।,500 भारतीय नागरिकों को निकाला गया है जिनमें गर्भवती महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। भारतीय उच्चायोग ने रविवार को यहां इस संबंध में जानकारी दी।

वंदे भारत मिशन के तहत नौसेना के जहाजों से फंसे हुए भारतीयों को निकाला गया। भारत सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित पाबंदियों के कारण विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए सात मई को यह अभियान शुरू किया था।अभियान के पहले चरण के तहत सरकार ने खाड़ी क्षेत्र और अमेरिका, ब्रिटेन, फिलीपीन, बांग्लादेश, मलेशिया और मालदीव जैसे देशों से कुल 6,527 भारतीयों को निकाला।उच्चायोग ने यहां एक ट्वीट में कहा, यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि 22 राज्यों के 1488 भारतीयों को मालदीव से निकाला गया है जिनमें 205 महिलाएं, 133 गर्भवती महिलाएंचिकित्सा मामले और 38 बच्चे शामिल हैं। आने वाले सप्ताहों में हवाई मार्ग से विभिन्न शहरों तक और जहाजों से तमिलनाडु तक लोगों को पहुंचाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। उसने एक अन्य ट्वीट किया, माले से भारतीयों को लेकर जाने वाले विमान के 22 मई को बेंगलुरु और 23 मई को दिल्ली की उड़ान भरने का कार्यक्रम है। बेंगलुरु जाने वाले विमान में कर्नाटक के निवासी तथा सीमित संख्या में तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में रहने वाले भारतीय होंगे। दिल्ली जाने वाले विमान में दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और चंडीगढ़ में रहने वाले भारतीय सवार होंगे।

गिलगित-बाल्टिस्तान में कार्यवाहक सरकार बनाने, चुनाव कराने का आदेश जारी

भाषा। इस्लामाबाद

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने गिलगित-बाल्टिस्तान प्रांत में कार्यवाहक सरकार के गठन और चुनाव कराने के लिए आदेश जारी किया है। इस कदम का भारत ने कड़ा विरोध किया है।राष्ट्रपति कार्यालय से यह आदेश तब जारी किया गया है जब पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने 30 अप्रैल को संघीय सरकार को क्षेत्र में आम चुनाव कराने के लिए 2018 के एक प्रशासनिक आदेश में संशोधन करने की मंजूरी दे दी थी।

गिलगित-बाल्टिस्तान ऑर्डर ऑफ 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कई विषयों पर कानून बनाने के साथ ही प्रशासनिक बदलाव करने का अधिकार दिया गया है।उच्चतम न्यायालय द्वारा गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने की मंजूरी दिए जाने के बाद भारत ने इस्लामाबाद के समक्ष उसके अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में स्थिति में बदलाव लाने के उसके प्रयासों के लिए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इस महीने की शुरुआत में दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के एक वरिष्ठ राजनयिक को डेमार्श (आपत्ति पत्र) जारी कर अदालत के आदेश पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था और साफ तौर पर यह कहा था कि गिलगित-बाल्टिस्तान के इलाकों समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान मामलों के संघीय मंत्रालय द्वारा शनिवार को जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने गिलगित-बाल्टिस्तान में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए गिलगित-बाल्टिस्तान चुनाव एवं कार्यवाहक संशोधन आदेश जारी किया।गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा का पांच साल का कार्यकाल 24 जून को पूरा होगा। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी किए आदेश में कहा गया है कि निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराने के लिए गिलगित-बाल्टिस्तान में एक कार्यवाहक सरकार बनाने के लिए कानूनों में संशोधन आवश्यक था।

डॉन अखबार में प्रकाशित एक खबर के अनुसार, सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की गिलगित-बाल्टिस्तान इकाई के अध्यक्ष सैयद जफर शाह ने कहा कि क्षेत्र में कार्यवाहक सरकार बनाने का कोई प्रावधान नहीं था और राष्ट्रपति के आदेश के बाद इस मुश्किल को हटा दिया गया है।उन्होंने बताया कि गिलगित-बाल्टिस्तान विधानसभा चुनाव समय पर होंगे और कार्यवाहक सरकार दो महीनों के भीतर चुनाव कराने की व्यवस्था करेगी। विशेष परिस्थितियों में कार्यवाहक सरकार का कार्यकाल बढ़ाने का कानून भी है।

जेईई मेन की नई तारीख 18 से 23 जुलाई के बीच तय हो गयी है। यह समय है कि छात्र इसके लिए तैयार हो जाएं। परीक्षा में सफलता पाने में कौन से तरीके मददगार हैं इसके बारे में बताते हैं आर. एल. त्रिखा

दिनचर्या कुछ इस तरह बनायी जाएगी जिसमें दोहराना, याद करना व परीक्षा करना साथ साथ हो। यह आपको संक्षिप्त नोट्स, फार्मूले एवं अवधारणाओं को त्वरित ढंग से पलटने का अवसर भी देता है। हर विषय को समान समय दें और कृत्रिम परीक्षाओं व पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रों के अभ्यास के जरिए अवधारणाओं व उनके उपयोग को गहरायी से समझने करने पर ध्यान दें। गहन अध्ययन रटने से बड़ा मंत्र है।

स्थिर मन से करें तैयारी

कोविड -19 महामारी ने राज्य को पूर्ण तालाबंदी में डाल दिया है जिसे अब 17 मई, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। राज्य को छोड़कर, कोरोना वायरस ने मई में जेईई एडवांस्ड से पहले होने जेईई मेन (अप्रैल सत्र) में दिखने का सपना पालने वाले विद्वानों के सपनों पर रोक भी लगाई है।

लॉकडाउन से पहले, जेईई मेन (अप्रैल सत्र) परीक्षा 5, 7,9 और 11 अप्रैल को आयोजित होने वाली थी। इसके अलावा, लॉकडाउन के बढ़ने के ठीक बाद, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने जेईई मेन आवेदनों के लिए सही खिड़की को फिर से खोल दिया। यहां, वे छात्र, जिन्होंने अप्रैल सत्र के लिए आवेदन किया है, सुधार कर सकते हैं। मंगलवार को, एचआरडी मंत्री ने जेईई मेन के दूसरे सत्र की नयी तारीखें घोषित की हैं जो 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच सुनिश्चित हुई हैं। छात्रों को घबराना नहीं है, बल्कि अपनी तैयारी को तेज करने के लिए मौजूदा समय का उपयोग करना है। इस स्थिति को ईश्वर की कृपा के रूप में समझकर, छात्रों को शांतचित्त रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए तथा अपने कीमती समय को अपनी तैयारी की खूबियां व खामियां पहचानने में लगाना चाहिए।

जब कुछ भी अपने नियंत्रण में नहीं दिखता है, यह उत्तम है कि चुनौतियों का सामना करने में, अपनी योग्यताएं निखारने तथा बेहतर भविष्य के लिए उत्कृष्टता की ओर कदम बढ़ाने के लिए समय बिताएं। समय की अनिवार्यता है कि सकारात्मक रहें, कुछ उत्पादक व बेहतर बनाने में इस अतिरिक्त समय का प्रभावी उपयोग करें। निम्न बातें समय का बेहतर उपयोग करने में निश्चित रूप से काम आएंगी:

उपयोगी दिनचर्या बनाएं: जब आप कुछ साकार करना चाहेंगे तो प्रमुख बात है उसकी सहज तैयारी की योजना बनाएं। दिनचर्या कुछ इस तरह बनायी जाएगी जिसमें दोहराना, याद करना व परीक्षा करना साथ साथ हो। यह आपको संक्षिप्त नोटस, फार्मूले एवं अवधारणाओं को त्वरित ढंग से पलटने का अवसर भी देता हैं। हर विषय को समान समय दें और कृत्रिम परीक्षाओं व पूर्व परीक्षा प्रश्नपत्रों के अभ्यास के जरिए अवधारणाओं व उनके उपयोग को गहरायी से समझने करने पर ध्यान दें। गहन अध्ययन रटने से बड़ा मंत्र है।

बेहतर अध्यापन के लिए आनलाइन पढ़ें: मौजूदा परिदृश्य ने निश्चित रूप से तकनीक की महत्ता को उभारा है। ऐसे आनलाइन प्लेटफार्म हैं जो ईमानदारी से उन्नत तैयारी के लिए पूरे नोटस, विशेषज्ञ परामर्शों, आनलाइन कक्षाओं, कृत्रिम परीक्षाओं आदि के साथ वर्चुअल क्लासरूम माहौल प्रदान करने का काम कर रहे हैं। नालेज पार्टनर फिट्जी से समर्थित एडफोरा माइ पेट, एक ऐसा प्लेटफार्म है जो छात्रों को उनके घरों में सुरक्षित एवं प्रभावशाली ढंग से पढ़ने में सक्षम बनाता है।

थ्री-टियर दोहराव पद्धति चुनें: समय पर दोहराने से एकाग्रता व उत्पादकता प्रेरित होती है। निर्धारित दिन पर पढ़े गए विषय को तीन दिनों के बाद दोहराया जाएगा जिससे कि उक्त टापिक पूरे सप्ताह दिमाग में बना रहेगा। इस पद्धति के जरिए छात्र संभवतया मुद्दों व विषयों पर गहन समझ बनाने जा रहा है।

मुख्य फार्मूले का अवधारणागत उपयोग: आज के प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण चाहता है कि व्यक्ति जेईई मेन टाइप प्रश्नों में फार्मूले को सीखे और समझकर उसका उपयोग करे।

यह दोहराने के समय और भी उपयोगी हो सकता है। वे छात्र जो प्रश्न हल करने में काफी समय लेते हैं, वे अभ्यास कर सकते हैं और अपनी गति बढ़ा सकते हैं।

कृत्रिम परीक्षाएं: कृत्रिम परीक्षा एक प्रकार का अभ्यास मैच है जो छात्रों को परीक्षा के सही माहौल के साथ वास्तविक मैच के लिए तैयार करता है। मौजूदा तैयारी के सटीक विश्लेषण के लिए, कृत्रिम परीक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

शांत व उत्साहित बने रहें: उत्तम प्रदर्शन के लिए, यह जरूरी है कि आपका तन व मन संतुलित हो। घंटों की पढ़ाई के दौरान बीच बीच में कोई अवकाश न लेना शायद आपको अपेक्षित नतीजे नहीं दिलाएगा। दिमाग को ढालने के लिए, खोई ऊर्जा की पुन: हासिल करने तथा अगले अध्ययन सत्र के लिए तन और मन को पुन: ऊर्जावान बनाने के लिए जरूरी है कि निरंतर अंतराल पर अवकाश लें। इसलिए शांत रहें और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त हों।

समय प्रबंधन: इसका उत्पादक एवं असरकारी ढंग से उपयोग करना चाहिए। अवधारणाओं पर बेहतर समझ हासिल करने के लिए इस अतिरिक्त समय एवं कार्यकलाप का समझदारीपूर्ण उपयोग करना समय की आवश्यकता है। सटीक रणनीति एवं उचित समय प्रबंधन ऐसे तरीके हैं जिनका हर छात्र को इस वर्तमान लॉकडाउन के दौरान उपयोग करना चाहिए और ये उत्कृष्टता हासिल करने वाले कदम हैं। इसके अलावा, सफलता दिन के प्रदर्शन पर निर्भर करती हैं। इसलिए, व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए व एक घंटा भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब समय है जेईई मेन 2020 तथा उसके बाद जेईई एडवांस्ड 2020 में कामयाबी पाने का। जेईई मेन 2020 के जनवरी सत्र में प्रयास के बाद, यह समय अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करने, खामियों का पता लगाने, कमजोर पक्षों को दूर करने और अपने प्रयास को सबसे असरकारी से प्रस्तुत करने का है।

– लेखक फिट्जी, निदेशक हैं।

माइंड इट

वैश्विक महामारी- कोविड-19, पिछले साल के अंत में अपनी पहली मौजूदगी के बाद से, जीवन व आजीविका की व्यापक स्तरीय बर्बादी का कारण बनी है। अभी तक अनुमानत: लाखों की जान लीलने का दावा करने तथा दुनिया की कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने वाला यह जानलेवा वायरस सुदूर व्यापक स्तर पर फैल चुका है।

तनाव व बेचैनी के मौजूदा वातावरण में, मनोरंजन के कुछ ही संसाधन, जो अपने अपने घरों में कैद बच्चों को उलझाए हुए हैं, वे हैं कुछ इंडोर खेल, स्थानीय टेलीविजन तथा वर्ल्डवाइड वेब। यह बच्चों की मानसिक स्थिति बदल सकता है क्योंकि वे ऐसी सामग्री से परिचित हो रहे हैं जो उनकी उम्र के शायद अनुकूल नहीं है। उन्हें उपलब्ध जानकारी की तथ्यता जांचे बिना, ये मासूम व कोमल मन वही मान सकते हैं जो वे पढ़ते हैं। इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत असर हो सकता है। बेचैनी, महामारी उपरांत तनाव व हाइपरटेंशन तो उन बिमारियों के महज कुछ उदाहरण हैं जो इन हालात में बच्चों को प्रभावित कर सकती हैं।

ऐसे परिदृश्य में, बच्चों के साथ रह रहे माता पिता या बड़े लोग ही सूचना के भरोसेमंद स्रोत होते हैं, जो उनके साथ होते हैं। इसलिए, नन्हीं आत्माओं के तंदुरूस्त मानसिक स्वास्थ्य व स्वास्थ्य दिनचर्या को बनाए रखना व सुनिश्चित करना माता पिता की एक गंभीर जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित करने के लिए बाह्य वातावरण व चुनौतियां बच्चे को परेशान नहीं करती हैं, यह लाजिमी है कि माता पिता सचेत ढंग से इन निम्न कदमों का पालन करते हैं।

जिज्ञासाओं का समाधान करें: बच्चे अपने मन में दौड़ते प्रश्नों के निरंतर प्रवाह वाले जिज्ञासु स्वभाव के होते हैं। माता पिता को लगातार अपने बच्चों से बात करनी चाहिए और उनके हर सवालों का उत्तर देना चाहिए। इस तरह, माता पिता सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चे को सही जानकारी प्राप्त हो रही है और वे इंटरनेट से ली गयी किसी जानकारी के आधार पर राय नहीं बना रहे हैं। उनके प्रश्नों को सीधे नकार देने के बजाय, माता पिता को अपने बच्चों की जिज्ञासा का उत्तर देने का सजग प्रयास करना चाहिए।

बच्चों को सुनें और उनके कार्यों को समझें: बच्चे अक्सर अपने इर्दगिर्द की परेशानियों में उलझ जाते हैं और उसकी एक मानसिक छवि बना लेते हैं। माता पिता को अपने बच्चों को सुनना चाहिए तथा उनके कार्यों को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब बच्चा बताता है कि वह कैसा महसूस कर रहा है या कर रही है, तो माता पिता को उस पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सहज करने का प्रयास करना चाहिए। जब बच्चों को माता पिता के सहयोग से आश्वस्त हो जाते हैं तो उनके लिए अपनी भावनाओं से निपटना आसान हो जाता है।

सकारात्मक वातावरण बनाएं: सकारात्मकता एक अनमोल गुण है। माता पिता को सक्रियता के साथ उन सूचना स्त्रोतों पर नजर रखनी चाहिए जिनका उनके बच्चे अनुपालन कर रहे हैं और सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें उम्र के मुताबिक सकारात्मक खबरें व सूचना ही मिल रही हैं। इसके अलावा, घरों में भी माता पिता को मस्ती व मनोरंजन का एक सकारात्मक वातावरण निर्मित करना चाहिए ताकि बच्चे सहज महसूस कर सकें और बाह्य घटनाओं से परेशान न हों।

उन्हें व्यस्त रखें: सही कहा गया है, कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। माता पिता को अपने बच्चों को व्यस्त रखने के लिए उनके साथ विभिन्न इंडोर गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। यह माता पिता को अपने बच्चों के साथ समय बिताने, नयी गतिविधियां सीखने में बच्चों की सहायता करने तथा उनके मन से किसी हानिकारक जानकारी को दूर रखने में सहायता करेगा।

उनका जुड़ाव बनाए रखें: माता पिता को सही कारणों के लिए तकनीक का उपयोग करना चाहिए और अपने बच्चों व मित्रों के लिए वर्चुअल खेल खेलने में मदद करनी चाहिए। इस तरह, भले ही बच्चा अपने घर की चहारदीवारी में बंद है, मगर वे फिर भी अपने मित्रों से बात कर सकते हैं और अपने जीवन को महामारी से पहले जैसा सहज महसूस कर सकते हैं। बच्चों व बड़ों, दोनों के मानसिक स्वास्थ्य पर इस महामारी का प्रभाव अत्यंत स्पष्ट है। वायरस और उसके फैलाव संबंधी जानकारी की लगातार बमबारी लोगों को बेचैन बना रही है। ऐसी स्थिति में, यह जरूरी है कि वे संभी संभव उपाय अपनाएं जो स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखने में लोगों की सहायता कर सकें।

...राजीव बंसल

– लेखक ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, इंडिया के आपरेशंस डायरेक्टर हैं।

स्कॉलरशिप

ग्रीन टेलेंट्स अग्रणी वैज्ञानिकों से आवेदन आमंत्रित करता है। यह व्यापक जनों तक अपने शोध को प्रदर्शित करने, विशिष्ट विशेषज्ञों के साथ आदान प्रदान करने तथा जर्मन रीसर्च संस्थानों के स्थायी साझा कार्य का आधार निर्मित करने का एक अवसर है।

योग्यता: मास्टर उपाधिधारक छात्र, पीएचडी छात्र, पोस्टडाक्टरेट, साथ ही साथ युवा पेशेवर हों जिनके पास न्यूनतम तीन साल का पेशेवर कार्य अनुभव हो (अकादमिक डिग्री की संभावना के तहत हासिल पेशेवर कार्य अनुभव के अलावा) तथा स्थायी विकास पर गहरी एकाग्रता हो। आवेदकों के पास अंग्रेजी की उत्कृष्ट दक्षता व तथा उपरोक्त औसत ग्रेड प्रमाणित हो।

केवल गैर जर्मन नागरिक व प्रवासियों के आवेदन पर ही विचार हो सकता है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया *www.greentalents.de* पर जाएं जहां प्रतियोगिता फ्लायर समेत अवार्ड टेव्लर दोनों उपलब्ध है तथा हमें ट्वीटर व लिंक्डइन पर फालो कर सकते हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि: 19 मई, 2020, सायं 2 बजे तक आवेदन कर सकते हैं।

द युनिवर्सिटी आफ लीवरपूल इंटरनेशनल कालेज एक्सीलेंस स्कालरशिप प्रदान कर रही है।

आवेदन योग्य देश: गैरयूरोपीय देश

योग्यता: युनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तावित किसी भी विषय में अंडरग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम का हिस्सा हो। विदेशी दरों पर पूर्ण ट्यूशन फीस देने के लिए जवाबदेह होना चाहिए। 2020/21 के अकादमिक वर्ष में नया गैर-चिकित्सीय अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू होना चाहिए।

आवेदक ने यूनिवर्सिटी आफलीवरपूल इंटरनेशनल कालेज में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अर्जित किए हों। आवेदन के साथ प्री-क्वालिफेशन डिग्री, अकादमिक पांडुलिपियों व अवार्ड की प्रतिलिपियां, वक्तव्य, पासपोर्ट प्रतिलिपि संलग्न करें।

प्रवेश शर्तें: प्रवेश शर्तें कोर्स के अनुसार भिन्न भिन्न हैं।

भाषा शर्तें: जिन छात्रों की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है उनके पास अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अंग्रेजी भाषा योग्यता प्रमाणपत्र होना चाहिए। अंडरग्रेजुएट कोर्स के लिए युनिवर्सिटी आईईएलटीएस की मांग करती है।

आवेदन कैसे करें: अलग से आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उपयुक्त कोर्स में सफलतापूर्वक पंजीकृत होने के बाद इस आवेदन पर स्वत: विचार कर लिया जाएगा।

आवेदन की अंतिम तिथि: आवेदन की अंतिम तिथि है 30 जून, 2020।

एडटेक आवश्यकता है, सिर्फ पढ़ाने का औजार नहीं

शोभित भटनागर का कहना है कि लॉकडाउन के कारण स्कूलों व कालेजों के बंद होने से, एडटेक आफलाइन शिक्षा का महज विकल्प नहीं बल्कि धीरे-धीरे शिक्षा का प्रमुख मॉडल बन रही है

लॉकडाउन के कारण स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों, व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद होने से, किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपने घर की चारदिवारी में कैंद हो गए हैं। यदि उन्हें सहायता या मार्गदर्शन की जरूरत हो, तो वे अपने कोचिंग या ट्यूशन सेंटरों या उन सेवाओं के लिए बाहर नहीं जा सकते, जिसका उन्हें भुगतान किया होता है। शहरों के अलावा, ग्रामीण इलाकों के वे छात्र भी हैं जो अपने अपने कोचिंग सेंटरों तक जाने के लिए सुदूर यात्राएं किया करते थे, अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए, अब सवाल है कि हम किस प्रकार इन छात्रों की सहायता करें, जिनके जीवन विकल्प या भविष्य आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं पर आश्रित हैं?

मुफ्त लाइव कक्षाओं की उपलब्धता के जरिए, छात्रों की पढ़ाई निर्बाध ढंग से जारी रखना सुनिश्चित करके, एडटेक शिक्षा मूल मानवाधिकार है के आधार पर शिक्षण सुविधा प्रदान कर रही है। सबसे बड़ा लाभ जो एडटेक इंडस्ट्री प्रदान करती है, वो आज के समय में एक सुरक्षित सुविधाजनक, घर से पढ़ने का विकल्प है। यह अल्पकालिक स्थिति छात्रों व उनके माता पिता का एडटेक पर भरोसा बढ़ा रही है। मौजूदा स्थिति में एडटेक की, आफलाइन शिक्षा के विकल्प के रूप में, स्वीकार्य बढ़ेगी और धीरे धीरे यह शिक्षा का प्रमुख माडल बनती जाएगी।

शोभित भटनागर
सीईओ-को-फाउन्डर, ग्रेडअप

शैक्षणिक वीडियोज, संदेह समाधान व आनलाइन कक्षाओं की मांग बहुत बढ़ गयी है। 2019 की एक शोध रिपोर्ट ने इंगित किया कि सत्तर फीसदी से अधिक छात्र आनलाइन शिक्षा की ओर मुड़ना चाह रहे हैं यदि वे आनलाइन कक्षाओं तक अपनी पहुंच बना पाएं। रिपोर्ट ने यह भी सलाह दी कि यह प्रतिशत द्वितीय व तृतीय श्रेणी शहरों में कहीं अधिक है, जहां अस्सी फीसदी छात्र आनलाइन पढ़ने के इच्छुक हैं। 2016 के बाद से, हमने संदेह समाधान व आनलाइन कक्षाओं के लिए गूगल सर्च जिज्ञासा में सहमति पाई है। यूट्यूब पर चौथी सबसे बड़ी श्रेणी, शिक्षा ने 2019 में 19.12बी व्यूज देखे जो 2018 की तुलना में 53 फीसदी की वृद्धि है।

शिक्षा क्षेत्र 2016 में सौ अरब डॉलर का था और जो साल 2020 के अंत तक 180 अरब डॉलर होकर लगभग दूना होने की संभावना इस सेक्टर के अच्छे जानकार निवेशकों का पूर्वानुमान है कि शिक्षा की कुछ प्रस्तुतियां आनलाइन पद्धति में आ जाएंगी। गूगल-केपीएमजी स्टडी के अनुसार, आनलाइन शिक्षा के लिए कुल सालाना बाजार अवसर 2021 तक 1.96 अरब डालर तक पहुंच सकते हैं।

मौजूदा परिदृश्य कुछ कुछ नोटबंदी के डिजिटल भुगतानों से मिलता जुलता है। एक पद्धति से वापसी ने दूसरी पद्धति के लिए अवसर को प्रोत्साहित किया। हम शैक्षणिक सेवाओं की डिजीटल खपत में वृद्धि देख रहे हैं। वर्तमान समय में, आनलाइन शिक्षा बाजार बहुत तेज गति से बढ़ रहा है और यह 2021 तक 1.96 अरब डॉलर से भी अधिक हो सकता है।

ऐडटेक कंपनियां जो बेहतर सेवा प्रदान करती हैं, वे इस अवसर को हथियाने में सक्षम होंगी। कंपनियों को उन्नत शिक्षण अनुभव हेतु अपने मंचों पर एआई, एमएस को शामिल करके अपनी शिक्षण सेवाओं को उन्नत बनाना होगा। केवल वही कंपनियां छात्रों की नयी पीढ़ी की सेवा करने में पर्याप्त सक्षम होंगी जो अपने मौजूदा यूजर आधार को बरकरार रखते हुए हर साल उन्नत करिकुलम आवश्यकताओं के साथ लैस होंगी।

मौजूदा महामारी ने शायद हमें बाध्य यूजर आचरण में बदलाव की झलक दिखा दी है, लेकिन हम प्रबल मानना है कि आचरण टिकाऊ रहेगा और आनलाइन अध्यापन को अनेक छात्रों द्वारा भविष्य में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अपनाया जाएगा।

आनलाइन शिक्षा बाजार 2025 तक वैश्विक स्तर पर 350 अरब डालर पर पहुंच जाएगा। भारत के निकट भविष्य में अमरीका और चीन की कतारों में शामिल होने की संभावना है।